

अर्थव्यवस्था की स्थिति*

वर्ष 2023 संभवतः पहले के अनुमान की तुलना में मामूली वैश्विक मंदी से विशेष होगा, लेकिन प्रक्षेपवक्र अप्रत्याशित बना हुआ है। भारत में, घरेलू खपत और निवेश को कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए मजबूत संभावनाओं, व्यापार और उपभोक्ता विश्वास के सुदृढीकरण और मजबूत ऋण वृद्धि से लाभ होगा। भले ही, जनवरी में मुद्रास्फीति में वापसी देखी गई हो, लेकिन आपूर्ति प्रतिक्रियाओं और लागत की स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। केंद्रीय बजट 2023-24 में पूंजीगत व्यय पर जोर देने से निजी निवेश में आधिक्य, रोजगार सृजन और मांग में मजबूती और भारत की संभावित वृद्धि में बढ़ोतरी की उम्मीद है।

हम पूर्ण अनिश्चितता के युग में रहते हैं - हम जो कुछ भी जानते हैं वह सभी अच्छी तरह से जानते हैं - विस्फोटक सूचना क्रांति इसे सुनिश्चित करती है। जैसा कि जॉन केनेथ गालब्रेथ ने लगभग तीन दशक पहले लिखा था, "दो प्रकार के पूर्वानुमानकर्ता हैं: एक वे जो नहीं जानते हैं, और दूसरे वे जो नहीं जानते हैं कि वे नहीं जानते हैं।" ¹ फिर भी, जब हर कोई एक ही दिशा में अनुमान लगाता है, तो यह आमतौर पर सच हो जाता है।

एक अच्छा उदाहरण जनवरी 2023 का अंतिम सप्ताह है, जिसके दौरान तथाकथित प्रणालीगत केंद्रीय बैंकों² द्वारा मौद्रिक नीति के कदमों को कम नापने का पूरी तरह से हावी वित्तीय बाजारों द्वारा अनुमान लगाया गया था। दर वृद्धि के निचले क्रम के लिए एक पीरूएट निष्पादित करके, उन्होंने हमें वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण की एक झलक दी जैसा कि उनके नजरिए से देखा गया था। फरवरी के पहले सप्ताह में, दोनों उन्नत लेकिन ज्यादातर उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाली दस से अधिक केंद्रीय बैंकों की

* इस आलेख को जी. वी. नथनएल, मधुरेश कुमार, कुणाल प्रियदर्शी, हर्षिता केशन, रमेश के गुप्ता, पंकज कुमार, हरेंद्र बेहेरा, अर्जित शिवहरे, राशिका अरोड़ा, अनूप के. सुरेश, लव के. शांडिल्य, रोहन बंसल, सुधांशु गोयल, प्रियंका सचदेवा, सत्यम कुमार, अक्षरा अवस्थी, युवराज कश्यप, अंशु कुमारी, आशीष एस खोब्रागडे, राजेश कावेडिया, सुप्रिया मजूमदार, विवेक कुमार, सौरभ कुमार, सौरभी सरदार ने तैयार किया है। निवेदिता बैनर्जी, बिचित्रानंद सेठ, सुजाता कुंडू, शेषाद्री बैनर्जी, इप्सिता पाद्री, सक्षम सूद, विनीत कुमार श्रीवास्तव, समीर रंजन बेहरा, देब प्रसाद रथ और माइकल देबब्रत पात्रा इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों को नहीं दर्शाते हैं।

¹ जॉन केनेथ गालब्रेथ, वॉल स्ट्रीट जर्नल, 22 जनवरी 1993।

² अमेरिकी फेडरल रिजर्व; यूरोपीय सेंट्रल बैंक; बैंक ऑफ इंग्लैंड।

गति धीमी हुई या रुकी, इसके बाद दूसरे सप्ताह में पांच और केंद्रीय बैंकों ने इस विचार को मजबूती दी कि वर्ष 2023 शायद पहले के अनुमान की तुलना में हल्की वैश्विक मंदी से विशेष होगा।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 30 जनवरी को जारी अपने विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट में भी भविष्य के बारे में कुछ अधिक आशावादी दृष्टिकोण की पुष्टि की, जैसा कि निम्नलिखित खंड में निर्धारित किया गया है। आईएमएफ के पूर्वानुमान की एक उल्लेखनीय विशेषता उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की ताकत है, जिसमें एशिया अग्रणी है। चीन और भारत 2023 में वैश्विक विकास का आधा हिस्सा उत्पन्न करेंगे।

आईएमएफ के अनुसार, वैश्विक मुद्रास्फीति 2022 में 8.8 प्रतिशत से घटकर 2023 में 6.6 प्रतिशत हो सकती है, क्योंकि रि-ओपनिंग, कमोडिटी की कीमतों में कमी और आपूर्ति श्रृंखलाओं की बहाली से मांग बढ़ती है - लेकिन फिर भी 2024 में 4.3 प्रतिशत के लक्ष्य के सापेक्ष ऊंची रह सकती है। जोखिम नीचे की ओर चला गया है, लेकिन एक महत्वपूर्ण मोड़ बीत चुका है³, और केंद्रीय बैंक इसे जानते हैं। फिर भी, उनमें से कोई भी वित्तीय बाजारों द्वारा उनके खिलाफ दांव लगाने के बावजूद कम होने के मूड का खुलासा नहीं कर रहा है कि वे इस साल के अंत में न केवल रोकेंगे बल्कि दरों में कटौती भी करेंगे।

केंद्रीय बैंक जानते हैं कि मुद्रास्फीति नीचे आ रही है, लेकिन वे इस बात से सतर्क हैं कि वित्तीय कीमतों को बढ़ाने में बाजारों का तर्कहीन उत्साह वास्तव में मांग और मुद्रास्फीति के पुनरुत्थान को फिर से बढ़ावा दे सकता है। इसलिए, जीओएटी की महंगी नीति त्रुटि⁴ को याद करते हुए, केंद्रीय बैंक सावधानी बरतने के पक्ष में

³ पियरे-ओलिवियर गौरिनचास, आईएमएफ, विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट कार्यवाही, 31 जनवरी, 2023। <https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/01/31/tr-13123-world-economic-outlook-update>

⁴ पॉल वोल्कर को अब तक का सबसे महान (जीओएटी) केंद्रीय बैंकर माना जाता है। हालांकि, कम ज्ञात, लेकिन उन्होंने 1980 में गंभीर नीतिगत गलती की थी। मंदी शुरू होने के बाद मई में बेरोजगारी दर एक प्रतिशत से अधिक बढ़कर 7 प्रतिशत से अधिक हो गई, फेड ने रिवर्स कोर्स करने और संघीय निधि दर को 7 प्रतिशत अंक से अधिक कम करने का फैसला किया। यह कार्रवाई इस तथ्य के बावजूद की गई कि मुद्रास्फीति अप्रैल में 14.7 प्रतिशत के शिखर पर पहुंच गई थी। फेड ने हस्तक्षेप किया था और मुद्रास्फीति सेनानी के रूप में वोल्कर की विश्वसनीयता को झटका लगा था। मुद्रास्फीति की उम्मीदें उच्च बनी रहीं और वास्तविक मुद्रास्फीति 1980 के अंत तक 12 प्रतिशत से ऊपर रही। जुलाई 1980 में मंदी समाप्त होने के साथ, फेड मुद्रास्फीति से लड़ने वाले व्यवसाय में वापस आ गया और संघीय निधि दर को फिर से बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार, अपनी विश्वसनीयता को फिर से स्थापित करने के लिए, फेड को 1981 के मध्य तक संघीय निधि दर को लगभग 20 प्रतिशत के क्रशिंग स्तर तक बढ़ाना पड़ा। जुलाई 1981 में शुरू हुई आगामी मंदी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे गंभीर मंदी बन गई। (फ्रेडरिक मिशिकन, फाइनेंशियल टाइम्स, 14 सितंबर 2022)।

गलती करेंगे और कम के बजाय अधिक करेंगे। यदि सॉफ्ट लैंडिंग लगभग सुनिश्चित है, तो दरों में हमेशा कटौती की जा सकती है यदि विकास उम्मीद से अधिक धीमा हो जाता है, एक बार कम मुद्रास्फीति टिकाऊ आधार पर हासिल हो जाती है। जैसे-जैसे मुद्रास्फीति का दबाव कम होता है, वित्तीय स्थितियों में सुधार की संभावना होगी, और इससे विकास को सहायता मिलेगी।

दूसरी ओर, वित्तीय बाजार इस दांव से प्रेरित हैं कि मुद्रास्फीति का पतन एक पीढ़ी में एक बार आने वाली गिरावट होगी, जैसा कि मुद्रास्फीति के बाजार-आधारित गेज जैसे ब्रेक-ईवन दरों और स्वैप कर्व्स में पता चलता है। इक्विटी स्थिर हैं और बॉन्ड में तेजी आई है जबकि मुद्रास्फीति सकारात्मक जोखिम वाली आस्तियों में फैल गई है। अमेरिकी डॉलर बुनियाद खो चुका है और शेष विश्व में व्यापक आर्थिक स्थितियों में सुधार के साथ इसमें और गिरावट की संभावना है।

क्या आने वाला डेटा अपेक्षाओं अपूर्ण रखना जारी रख सकता है? 2022 तक मौद्रिक नीति को सख्त बनाने से सबसे भारी दबाव अभी तक पकड़ में नहीं आया है। मंदी के मुहाने पर एक वैश्विक अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित बनी हुई है। 2023 अभी भी एक चुनौतीपूर्ण वर्ष होगा। केंद्रीय बैंकों के लिए यह अनुमान लगाना मुश्किल होगा कि कहां रुकना और ठहरना है। यदि वास्तव में वैश्विक विकास धीमा हो जाता है लेकिन मुद्रास्फीति ऊंची बनी रहती है। उनकी सबसे बुरी आशंका सच हो सकती है।

लचीलेपन की आवश्यकता है, जिसमें आने वाले आंकड़ों की व्याख्या करना शामिल है, विशेष रूप से श्रम बाजार - अभी भी कमजोर श्रम भागीदारी, इस्तीफे, अंशकालिक काम की अधिक घटनाओं और हाल ही में बड़े पैमाने पर कामबंदी के लिए समायोजित, यह उतना गर्म नहीं हो सकता है जितना कि बेरोजगारी दर और आय के आंकड़ों से पता चलता है। जैसे-जैसे दृष्टिकोण अधिक स्थिर होता है, मुद्रास्फीति की संरचनात्मक विशेषताओं पर महामारी और भू-राजनीति के बार-बार के झटके के निशान का वास्तविक रूप से आकलन करना महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्या स्वर्णिम अर्थ बिखर गया है, जिससे मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है? क्या विकसित अर्थव्यवस्थाओं को 4 प्रतिशत के मुद्रास्फीति लक्ष्यों को स्वीकार करना होगा, जबकि उभरती अर्थव्यवस्थाओं को और भी अधिक मुद्रास्फीति लक्ष्यों को अपनाना होगा।

व्यापार, वाणिज्य, वित्तीय और प्रौद्योगिकी प्रवाह के लिए अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में गंभीर जोखिम बढ़ रहे हैं। विश्व व्यापार संरक्षणवाद या फ्रेंड शोरिंग की ओर बलपूर्वक उठाए गए कदमों से खंडित हो सकता है, जिसमें प्रत्येक देश सब्सिडी और अन्य प्रोत्साहनों के उपयोग के माध्यम से रणनीतिक सामग्री और उद्योगों के उत्पादन पर नियंत्रण चाहता है। समय के साथ, अन्य क्षेत्र रणनीतिक हो सकते हैं क्योंकि बलपूर्वक व्यापार, औद्योगिक और प्रौद्योगिकी नीतियां शुरू की जाती हैं।

आईएमएफ का अनुमान है कि सीमित विखंडन परिदृश्य में वैश्विक उत्पादन के 0.2 प्रतिशत के बीच इन विकासों की लागत एक गंभीर परिदृश्य में लगभग 7 प्रतिशत के बीच - लगभग जर्मनी और जापान के संयुक्त वार्षिक उत्पादन के बराबर है। यदि तकनीकी अलगाव को इस उलझन में जोड़ा जाता है, तो कुछ देशों को सकल घरेलू उत्पाद के 12 प्रतिशत तक का नुकसान हो सकता है। आईएमएफ ने चेतावनी दी है कि माल और पूंजी का वैश्विक प्रवाह कम हो रहा है और प्रतिबंधों में वृद्धि दुनिया को बहुत छोटी जगह बना रही है। वित्तीय क्षेत्रीकरण और खंडित वैश्विक भुगतान प्रणाली व्यापार प्रतिबंधों से होने वाले नुकसान को बढ़ा सकती है। कम अंतरराष्ट्रीय जोखिम-साझाकरण के साथ, समष्टि आर्थिक अस्थिरता बढ़ सकती है, और अधिक गंभीर संकट न केवल राष्ट्रीय बफर पर अधिक दबाव डाल सकते हैं, बल्कि ऋणग्रस्तता सहित संकट में देशों का समर्थन करने के लिए वैश्विक समुदाय की क्षमता को भी कमजोर कर सकते हैं।⁵

जैसा कि केंद्रीय बैंक के भाषण से पता चलता है, समष्टि आर्थिक संभावनाओं को देखने की परंपरा को ध्यान में रखते हुए, भारत की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की पिछली बैठक 8 फरवरी, 2023 को 2023-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अनुमानों की सार्वजनिक विज्ञप्ति के साथ हुई थी। अपने फॉरवर्ड गाइडेंस⁶ के डेल्फिक भाग में, एमपीसी ने कृषि और संबद्ध

⁵ क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, विखंडन का सामना करना जहां यह सबसे ज्यादा मायने रखता है: व्यापार, ऋण और जलवायु कार्रवाई, आईएमएफ ब्लॉग। 16 जनवरी, 2023।

⁶ ओडिसन फॉरवर्ड गाइडेंस के बीच एक अंतर तैयार किया गया है, जो सार्वजनिक रूप से और स्पष्ट रूप से केंद्रीय बैंक को भविष्य की कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध करता है, और डेल्फिक फॉरवर्ड गाइडेंस, जो उनमें निहित संभावित मौद्रिक नीति कार्यों के साथ समष्टि आर्थिक प्रदर्शन का पूर्वानुमान लगाता है (कैपबेल)। जे.आर., चार्ल्स ई इवांस, जोनास डी एम फिशर और एलेजांद्रो जस्टिनियानो, फेडरल रिजर्व फॉरवर्ड गाइडेंस के समष्टि आर्थिक प्रभाव, आर्थिक गतिविधि पर बुकिंग्स पेपर्स, स्प्रिंग 2012)।

गतिविधियों के लिए मजबूत संभावनाओं, संपर्क-गहन क्षेत्रों और विवेकाधीन खर्च में वापसी, व्यापार और उपभोक्ता विश्वास को मजबूत करने, मजबूत ऋण वृद्धि, लचीला वित्तीय बाजार, और घरेलू उपभोग और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाने वाले कारकों के रूप में पूंजीगत व्यय और बुनियादी ढांचे पर सरकार के निरंतर जोर की ओर इशारा किया। उनके दृष्टिकोण से, ये कारक वैश्विक मंदी के कारण निर्यात के लिए प्रतिकूल प्रभावों की भरपाई करेंगे।

तदनुसार, 2023-24 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.4 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया था। मुद्रास्फीति के परिदृश्य के बारे में एमपीसी ने प्रतिकूल मौसम की घटनाओं, वैश्विक पण्य मूल्य परिदृश्य को लेकर अनिश्चितताओं और उत्पादन मूल्यों, विशेष रूप से सेवाओं में इनपुट लागत के निरंतर पास-श्रु को पहचानते हुए फसल की संभावनाओं में सुधार का हवाला देते हुए 2023-24 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति को 5.3 प्रतिशत पर अनुमानित किया, जो 2022-23 में 6.5 प्रतिशत से कम है। एमपीसी की राय में, मुद्रास्फीति उस दृष्टिकोण के लिए एक बड़ा जोखिम बनी हुई है जिसमें घरेलू आर्थिक गतिविधि लचीली रहने की उम्मीद है। तदनुसार, इसने निर्णय लिया कि मुद्रास्फीति पर सतर्क रहना अनिवार्य है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह सहिष्णुता बैंड के भीतर रहे और उत्तरोत्तर लक्ष्य के साथ संरेखित हो। इसलिए मुद्रास्फीति अपेक्षाओं को बनाए रखने, कोर मुद्रास्फीति की दृढ़ता को तोड़ने और उससे मध्यम अवधि की विकास संभावनाओं को मजबूत करने के लिए और अधिक जांची-परखी मौद्रिक नीति कार्रवाई की आवश्यकता है।⁷

इस बैठक में एमपीसी ने नीतिगत रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत करने का फैसला किया और समायोजन वापस लेने के रुख को बरकरार रखा। एमपीसी के फैसले को 2021-22 की दूसरी छमाही में महामारी से प्रेरित चलनिधि अंतःक्षेपण की समाप्ति, महामारी सुविधाओं को बंद करने, परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो नीलामी के माध्यम से चलनिधि का मॉड्यूलेशन और नकदी आरक्षित अनुपात में वृद्धि के साथ शुरू हुई यात्रा के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, जिनमें से सभी ने

सामान्य चलनिधि प्रबंधन संचालन और बाजार के समय की बहाली के लिए बुनियाद तैयार की।

शुरुआत में नीतिगत दरों में वृद्धि फ्रंट लोडेड थी, लेकिन घरेलू आर्थिक गतिविधियों को अस्थिर करने से बचने के लिए प्रणालीगत केंद्रीय बैंकों के कार्यों की विशेषता वाली 75 आधार अंकों की बड़ी वृद्धि को टाल दिया गया था। मुद्रास्फीति जून 2022 में चरम पर थी और उसके बाद इसमें कमी आई। दिसंबर 2022 से, दर वृद्धि के निचले स्तरों को ठीक करने के लिए स्थितियां अनुकूल हो गईं और फरवरी 2023 तक, मुद्रास्फीति से पहले चार तिमाहियों के लिए समायोजित होने पर नीतिगत दर ने सकारात्मक स्थान हासिल कर लिया। महत्वपूर्ण रूप से, कोई बैकस्लाइड या रिवर्सल नहीं हुआ है और दर परिवर्तन का आकार फॉरवर्ड गाइडन्स का सबसे अच्छा रूप रहा है।

एमपीसी मुद्रास्फीति को लक्ष्य तक लाने के अपने संकल्प को व्यक्त करने में दक्ष रही है। गवर्नर श्री शक्तिकांत दास के 8 फरवरी, 2023 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के हवाले से, "हमें मुद्रास्फीति में निर्णायक कमी देखने की आवश्यकता है। हमें मुद्रास्फीति को कम करने की अपनी प्रतिबद्धता पर अटल रहना होगा। इस प्रकार, मौद्रिक नीति को एक स्थिर अवस्फीति प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए....। दर वृद्धि के आकार में कमी मुद्रास्फीति दृष्टिकोण और बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था पर अब तक किए गए कार्यों के प्रभावों का मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करती है। यह आगे बढ़ने के लिए उचित कार्यों और नीतिगत रुख को निर्धारित करने के लिए सभी आने वाले डेटा और पूर्वानुमानों को तौलने के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान करती है। मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था के समक्ष आनेवाली चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए मुद्रास्फीति के पथ में गतिशील हिस्सों के प्रति चुस्त और सतर्क बनी रहेगी।"

मौद्रिक नीति की कार्रवाइयों का प्रभाव प्रसारण के चैनलों में परिलक्षित हो रहा है, लेकिन आगे की राह चुनौतीपूर्ण है। आने वाले वर्ष में, मुद्रास्फीति की वापसी जिद्दी होने और आपूर्ति के झटके से घिरे होने की उम्मीद है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लगभग हर दूसरे घटक - सांख्यिकीय और अपवाद-आधारित उपाय - मूल्य दबाव में वृद्धि दिखा रहे हैं। परिवारों की मुद्रास्फीति की अपेक्षाएं फ्लैट- लाईड हैं और विनिर्माण निगमों को बिक्री और

⁷ मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2022-23 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 6-8 फरवरी, 2023।

राजस्व की वृद्धि में कमी का सामना करना पड़ रहा है। लाभ पर दबाव बढ़ने के साथ, पूंजीगत व्यय नियंत्रित रहता है। इसलिए, मौद्रिक नीति के रुख को स्थायी आधार पर उपभोक्ता खर्च और व्यावसायिक निवेश के लिए अवस्फीतिकारी बने रहने की आवश्यकता होगी और विकास में तेजी के लिए एक ठोस आधार प्रदान करना होगा।

भारत की उत्पादक क्षमता के विस्तार के लिए मध्यम अवधि की नीतियां घरेलू विनिर्माण और व्यापार नीतियों पर जोर दे रही हैं जो घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करती हैं और मूल्य श्रृंखलाओं या जिसे 'उत्पादवाद'⁸ कहा जाता है, को पुनर्जीवित करती हैं। गतिविधि का पुनरुद्धार पहले से ही भीतरी इलाकों में रात की रोशनी में स्पष्ट है। भारत के जी-20 की अध्यक्षता में डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं के बुनियादी ढांचे के केंद्र में आने के साथ, देश डिजिटल नवाचारों में नेतृत्व करने और भारत के तकनीकी कार्यों को साकार करने के लिए तैयार है। ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम, इलेक्ट्रिक वाहनों और सेमी-कंडक्टर उत्पादन की योजनाओं, और बढ़ते नवीकरणीय ऊर्जा के साथ संप्रभु ग्रीन बॉन्ड की पहली पेशकश के मुद्दे के साथ अर्थव्यवस्था को हरा-भरा करने की प्रक्रिया गति पकड़ रही है। अधिक आत्मविश्वास से भरा भारत 2047 के दृष्टिकोण के साथ उच्च लक्ष्य लेकर चल रहा है। समापन खंड में, हम इस बात को रेखांकित करते हैं कि केंद्रीय बजट 2023-24 इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए एक निश्चित कदम उठाता है।

इस पृष्ठभूमि पर निर्धारित, लेख के शेष भाग को चार खंडों में संरचित किया गया है। खंड II वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से विकसित हो रहे विकास को रेखांकित करता है। घरेलू अर्थव्यवस्था का विकास खंड III में रखा गया है। खंड IV घरेलू वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करता है, जबकि अंतिम खंड समापन टिप्पणी निर्धारित करता है।











II. वैश्विक सेटिंग

वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए परिदृश्य कम निराशाजनक हो गया क्योंकि मुद्रास्फीति में नरमी ने आगे आक्रामक मौद्रिक सख्ती की आशंकाओं को कम कर दिया। महामारी प्रतिबंधों से दुनिया के

कुछ हिस्सों के फिर से खुल जाने से, पहले के अनुमान की तुलना में मामूली मंदी की संभावनाओं में सुधार हुआ है। हालांकि, काफी अनिश्चितता बनी हुई है, क्योंकि आने वाले डेटा को पार्स किया जाता है।

विश्व आर्थिक परिदृश्य (डब्ल्यूईओ) के जनवरी 2023 के अपडेट में आईएमएफ ने अक्टूबर के अपने अनुमानों की तुलना में 2023 के लिए वैश्विक वृद्धि दर को 2.0 आधार अंक (बीपीएस) बढ़ाकर 2.9 प्रतिशत कर दिया। इस संशोधन में नियंत्रित की गई मांग से मजबूत वृद्धि, मुद्रास्फीति में तेजी से गिरावट और वित्तीय स्थितियों में नरमी जैसे सकारात्मक अप्रत्याशित बातों को ध्यान में रखा गया है। विशेष रूप से, एक वैश्विक मंदी अब आधारभूत मूल्यांकन नहीं है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) के लिए, 2023 के लिए विकास को 1.0 आधार अंकों से बढ़ाकर 1.2 प्रतिशत कर दिया गया था, जबकि उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) के

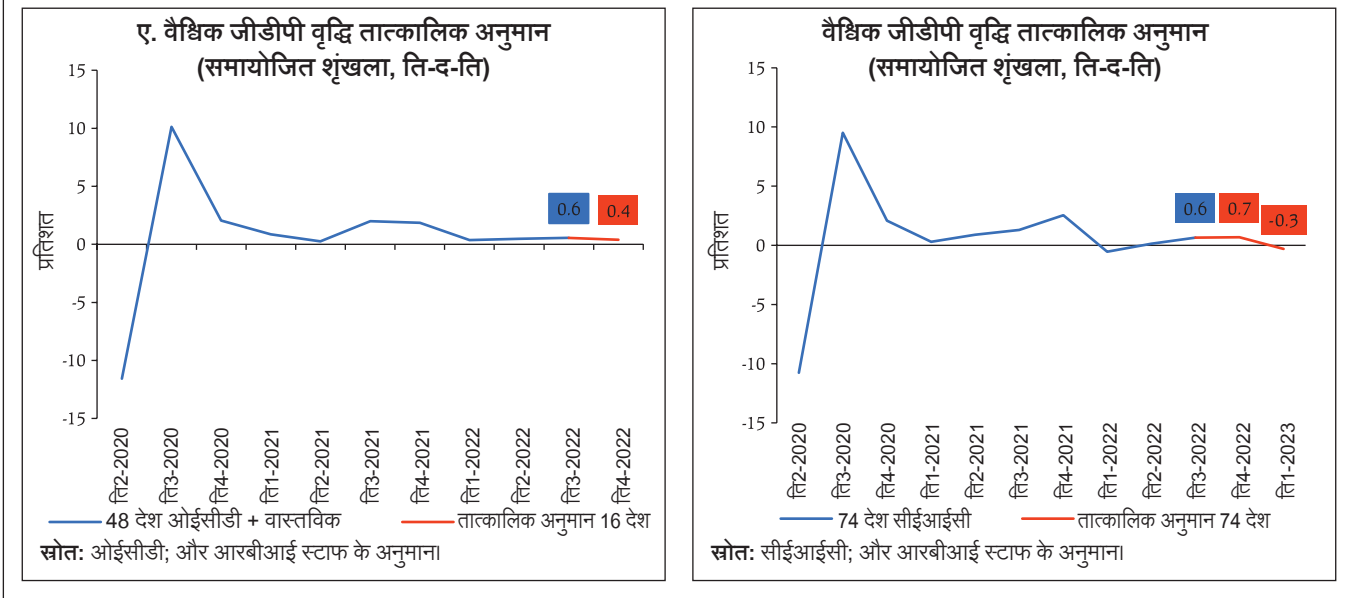
सारणी 1: जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान – चुनिंदा ईई और ईएमई (प्रतिशत)

अवधि के लिए पूर्वानुमान पूर्वानुमान के माह	2023		2024	
	जनवरी 2023	अक्टूबर 2022	जनवरी 2023	अक्टूबर 2022
 विश्व	2.9	2.7	3.1	3.2
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं				
 यूएस	1.4	1.0	1.0	1.2
 यूके	-0.6	0.3	0.9	0.6
 यूरो क्षेत्र	0.7	0.5	1.6	1.8
 जापान	1.8	1.6	0.9	1.3
उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं				
 ब्राजील	1.2	1.0	1.5	1.9
 रूस	0.3	-2.3	2.1	1.5
 भारत	6.1	6.1	6.8	6.8
 चीन	5.2	4.4	4.5	4.5
 दक्षिण अफ्रीका	1.2	1.1	1.3	1.3

स्रोत: आईएमएफ

⁸ दानी रॉड्रिग, 5 जुलाई, 2022, प्रोजेक्ट सिंडिकेट

चार्ट 1: वैश्विक जीडीपी तात्कालिक अनुमान (नाउकास्ट)



लिए, यह 2023 में 4.0 प्रतिशत पर 30 आधार अंक अधिक होने का अनुमान है (डब्ल्यूईओ अक्टूबर 2022 के अनुमानों की तुलना में) [सारणी1]।

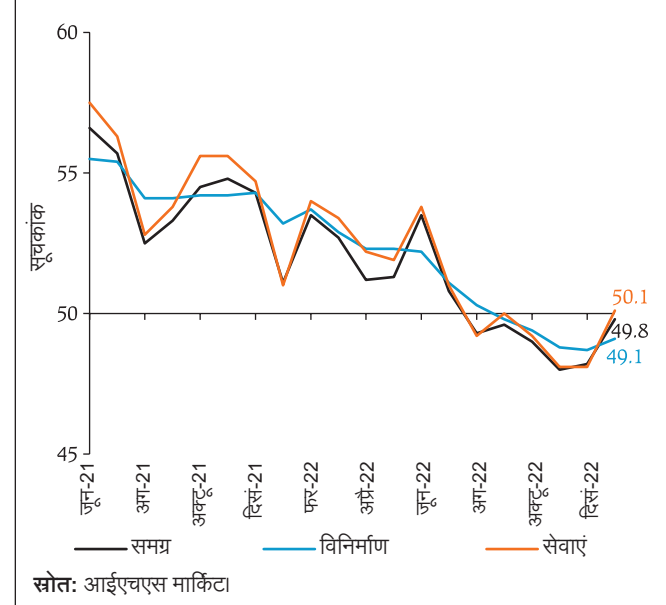
इस पृष्ठभूमि में, हमारे मॉडल आधारित नाउकास्ट, जिसमें 74 देशों के डेटा शामिल हैं, ने 2023 की पहली तिमाही में वैश्विक विकास की गति में -0.3 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है (चार्ट: 1ए और 1बी)।

उच्च आवृत्ति संकेतकों में, जनवरी 2023 में 49.8 पर वैश्विक समग्र क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) ने तेजी दर्ज की, लेकिन लगातार छठे महीने संकुचन क्षेत्र में रहा (चार्ट 2)। वैश्विक विनिर्माण खरीद प्रबंधक सूचकांक जनवरी में 49.1 पर लगातार पांचवें महीने तटस्थ चिह्न से नीचे रहा, हालांकि संकुचन ने उत्पादन और नए स्तर दोनों में कमी के संकेत दिखाए, रोजगार में मामूली वृद्धि दर्ज की। सेवा पीएमआई छह महीने बाद विस्तारवादी मोड में लौट आया।

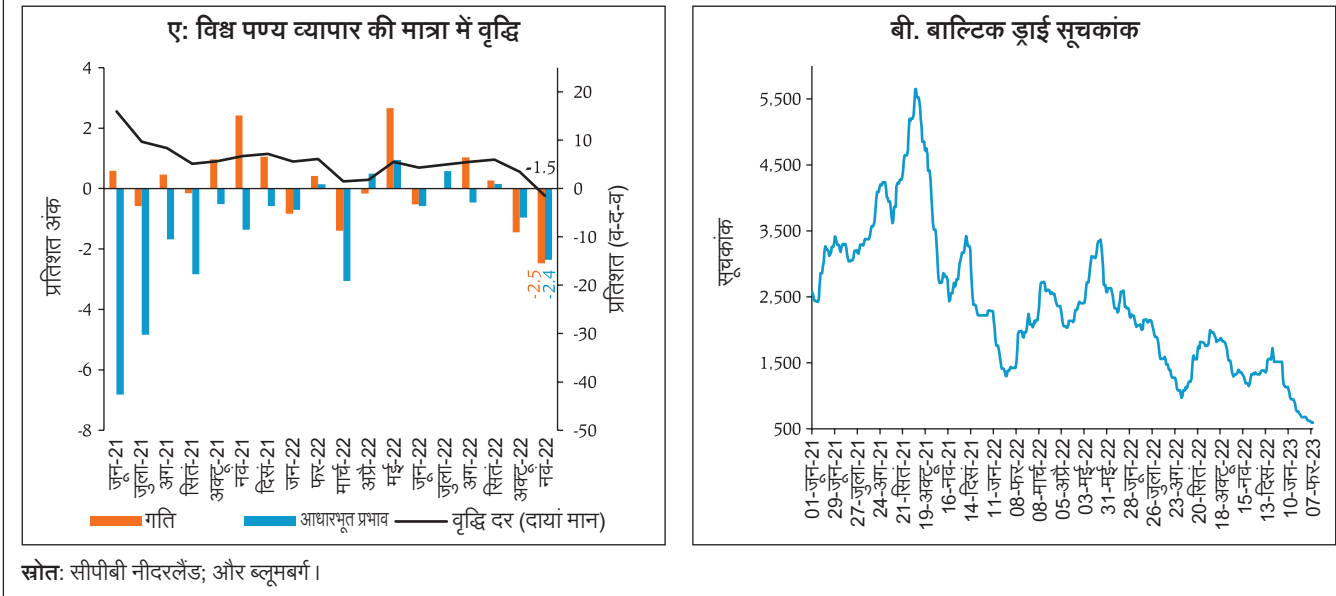
नवंबर 2022 में विश्व व्यापार की मात्रा में तीव्र नकारात्मक गति और प्रतिकूल आधार प्रभाव के कारण 1.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की गिरावट आई (चार्ट 3 ए)। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स - शुष्क थोक वस्तुओं के लिए शिपिंग शुल्क का एक नाप - जनवरी 2023

में अपने मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक गिर गया क्योंकि सभी पोत खंडों में कमजोर मांग के साथ कैपसाइज मांग कम रही (चार्ट 3 बी)। आईएमएफ का अनुमान है कि वस्तुओं और सेवाओं में वैश्विक व्यापार 2022 में 5.4 प्रतिशत से घटकर 2023 में 2.4 प्रतिशत रह जाएगा।

चार्ट 2: वैश्विक पीएमआई



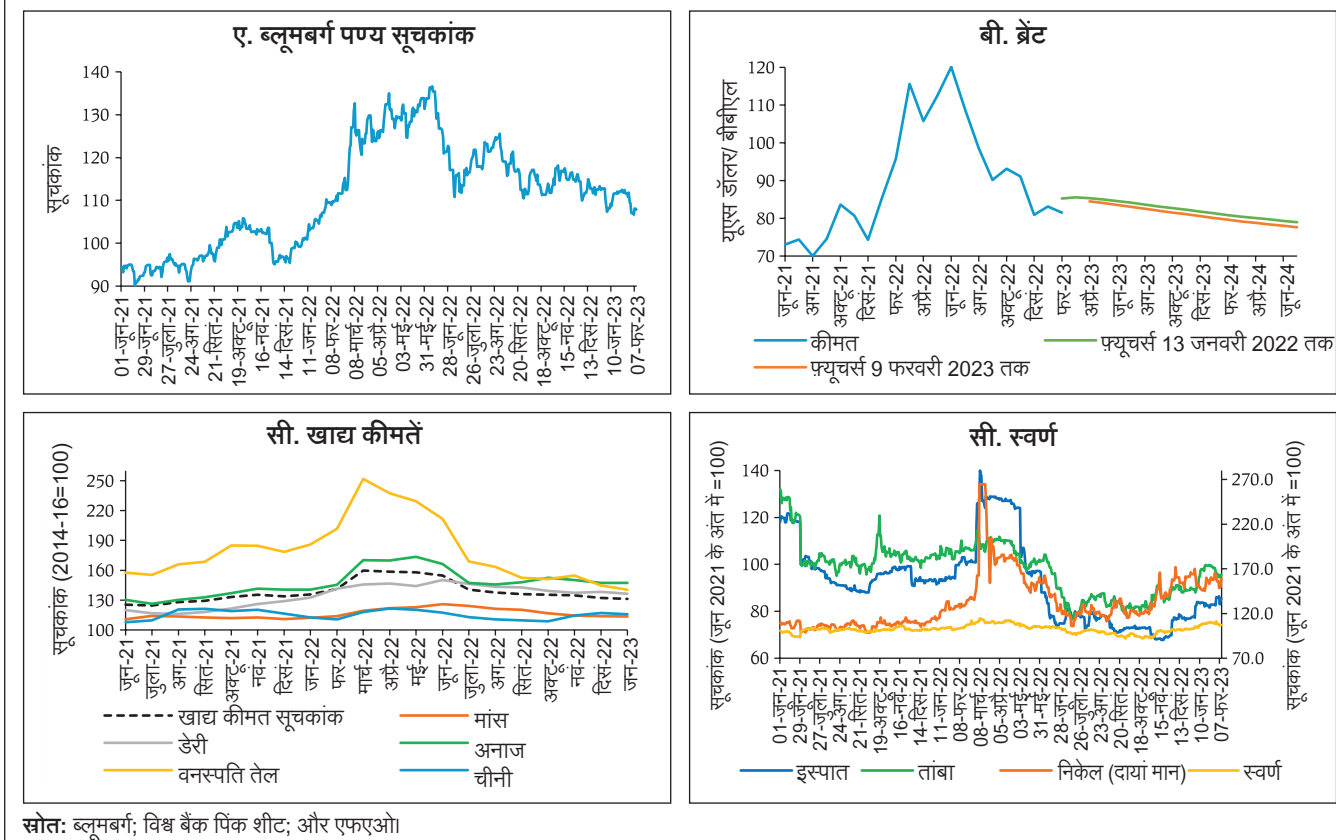
चार्ट 3: विश्व व्यापार और नौ-परिवहन लागत



अभी भी कमजोर वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण ने मांग पर दबाव जारी रखा है जिसके कारण (चार्ट 4 ए) वैश्विक पण्य कीमतों ने

अस्थिरता का प्रदर्शन जारी रखा है (चार्ट 4 ए) तुर्की में भूकंप के बाद उभरती भू-राजनीतिक चिंताएं, आपूर्ति की कमी और एक

चार्ट 4: पण्य और खाद्य कीमतें



प्रमुख निर्यात टर्मिनल के बंद होने के आसपास घुमती अनिश्चितता के बाद जनवरी और फरवरी (15 फरवरी, 2023 तक) में कच्चे तेल की कीमतों ने औसतन 83 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार किया (चार्ट 4 बी)। खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) खाद्य मूल्य सूचकांक⁹ में जनवरी में लगातार दसवें महीने गिरावट आई, जो वनस्पति तेलों, डेयरी और चीनी से प्रेरित थी, जबकि अनाज और मांस की कीमतें काफी हद तक स्थिर रहीं (चार्ट 4 सी)।

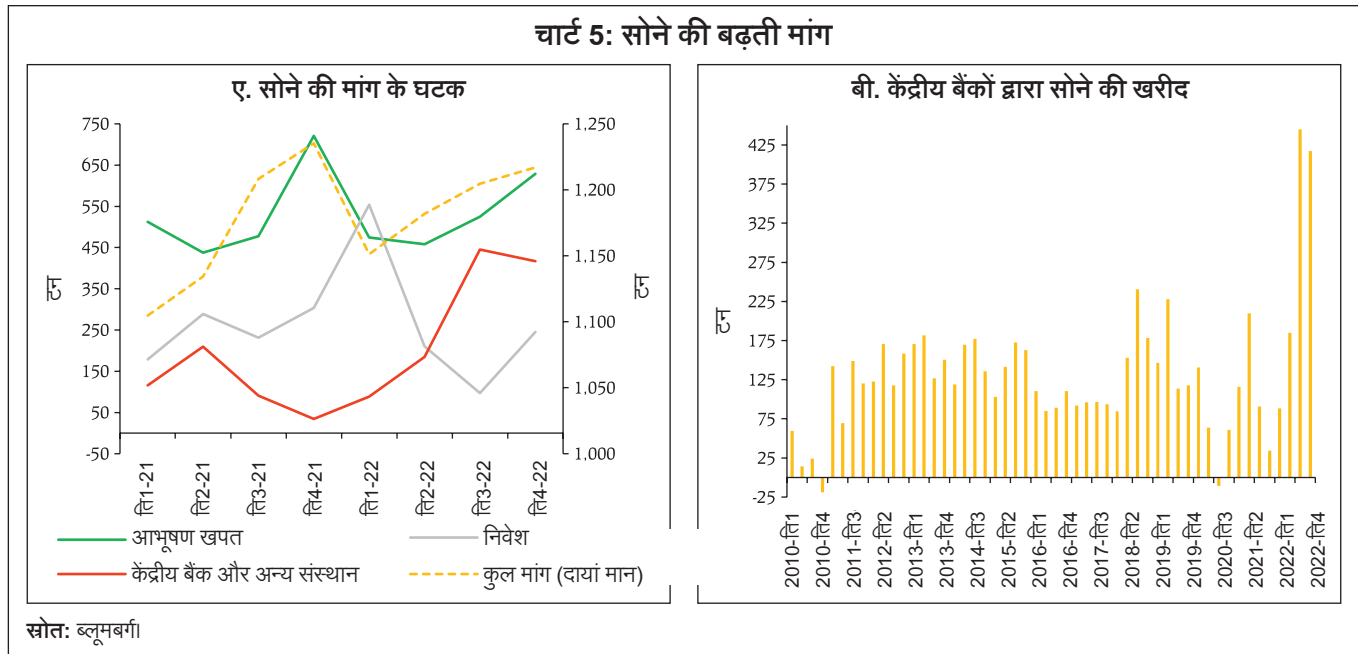
महामारी के प्रतिबंधों में ढील और वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में उच्च वृद्धि के कारण दुबारा खुली योजनाओं और उच्चतर मांग की अपेक्षाओं पर धातु की कीमतों में वृद्धि हुई। सुरक्षित निवेश मांग के कारण जनवरी में सोने की कीमतों में तेजी आई (चार्ट 4 डी)। सभी प्रमुख हितधारकों से सोने की मांग बढ़ रही है, 1967 के बाद से केंद्रीय बैंकों की सोने की खरीद 2022 की चौथी तिमाही में उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है (चार्ट 5ए और 5बी)।

अधिकांश एई और ईएमई में हेडलाइन मुद्रास्फीति कम हो गई। हालांकि वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति 2022 की तीसरी तिमाही में चरम पर है, आईएमएफ ने चेतावनी दी है कि अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में मुख्य मुद्रास्फीति महामारी से पहले के स्तर से ऊपर बनी हुई है। अमेरिका में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति जनवरी 2023 में मामूली घटकर 6.4 प्रतिशत रही जो

एक महीने पहले 6.5 प्रतिशत थी। व्यक्तिगत उपभोग व्यय (पीसीई) सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति दिसंबर 2022 में स्पष्ट रूप से घटकर 5.0 प्रतिशत हो गई (चार्ट 6 ए)। जनवरी में यूरो क्षेत्र और ब्रिटेन में मुद्रास्फीति घटकर क्रमशः 8.5 प्रतिशत और 10.1 प्रतिशत पर आ गई। जापान में सीपीआई (ताजा खाद्य पदार्थ से इतर सभी वस्तुएं) मुद्रास्फीति दिसंबर 2022 में 4.0 प्रतिशत के साथ 41 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई। ईएमई में, दिसंबर 2022 में ब्राजील (5.8 प्रतिशत), रूस (11.9 प्रतिशत), और दक्षिण अफ्रीका (7.2 प्रतिशत) में मुद्रास्फीति में और कमी आई (चार्ट 6 बी)। हालांकि, चीन ने दिसंबर में सीपीआई मुद्रास्फीति में 20 आधार अंकों की वृद्धि दर्ज की और यह 1.8 प्रतिशत हो गई।

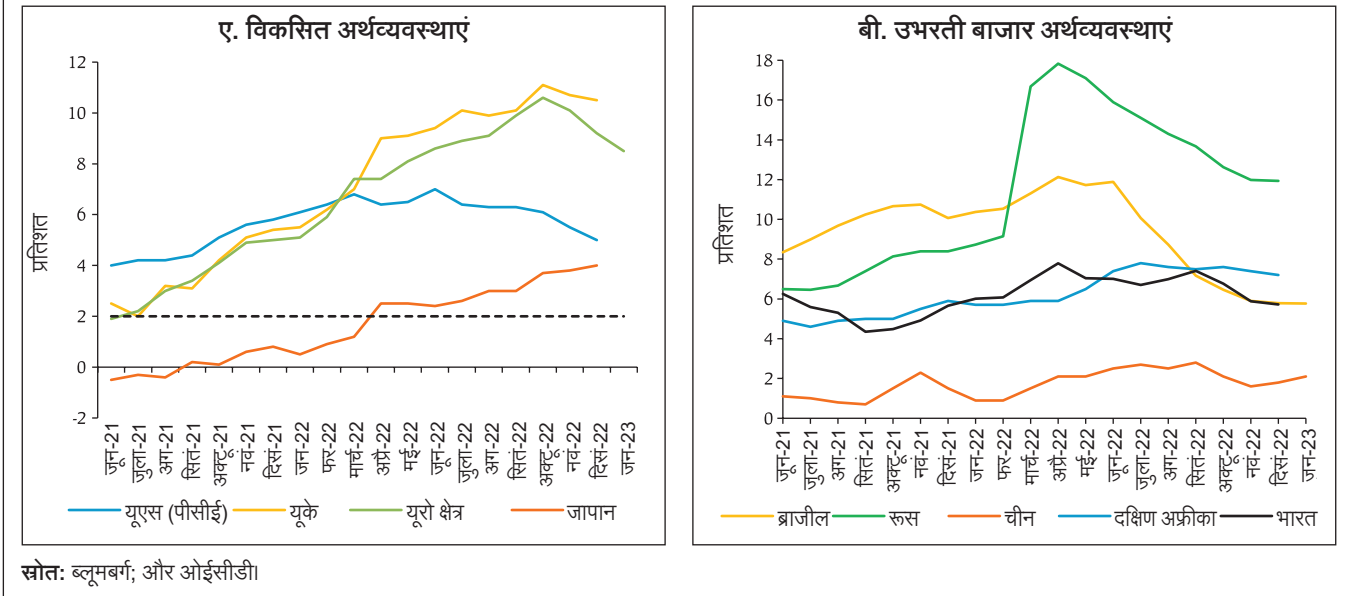
वैश्विक इक्विटी बाजारों ने 2023 की शुरुआत नए आशावाद के साथ की क्योंकि आने वाले आंकड़ों ने मुद्रास्फीति में कमी और कम आक्रामक दर वृद्धि की उम्मीदों का सुझाव दिया, जिसमें ईएमई एई की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे (चार्ट 7 ए)। हालांकि, फरवरी की शुरुआत में बाजार में गिरावट आई, विशेष रूप से ईएमई में, क्योंकि निवेशकों ने जोखिम से परहेज किया, विशेष रूप से, अमेरिका में मजबूत गैर-कृषि पेट्रोल और कम बेरोजगारी दर के आंकड़ों के जारी होने के बाद, जो एई में उच्च ब्याज दरों की अपेक्षाओं को दर्शाता है।

चार्ट 5: सोने की बढ़ती मांग



⁹ उप-सूचकांकों में अनाज, वनस्पति तेल, डेयरी, मांस और चीनी मूल्य सूचकांक शामिल हैं।

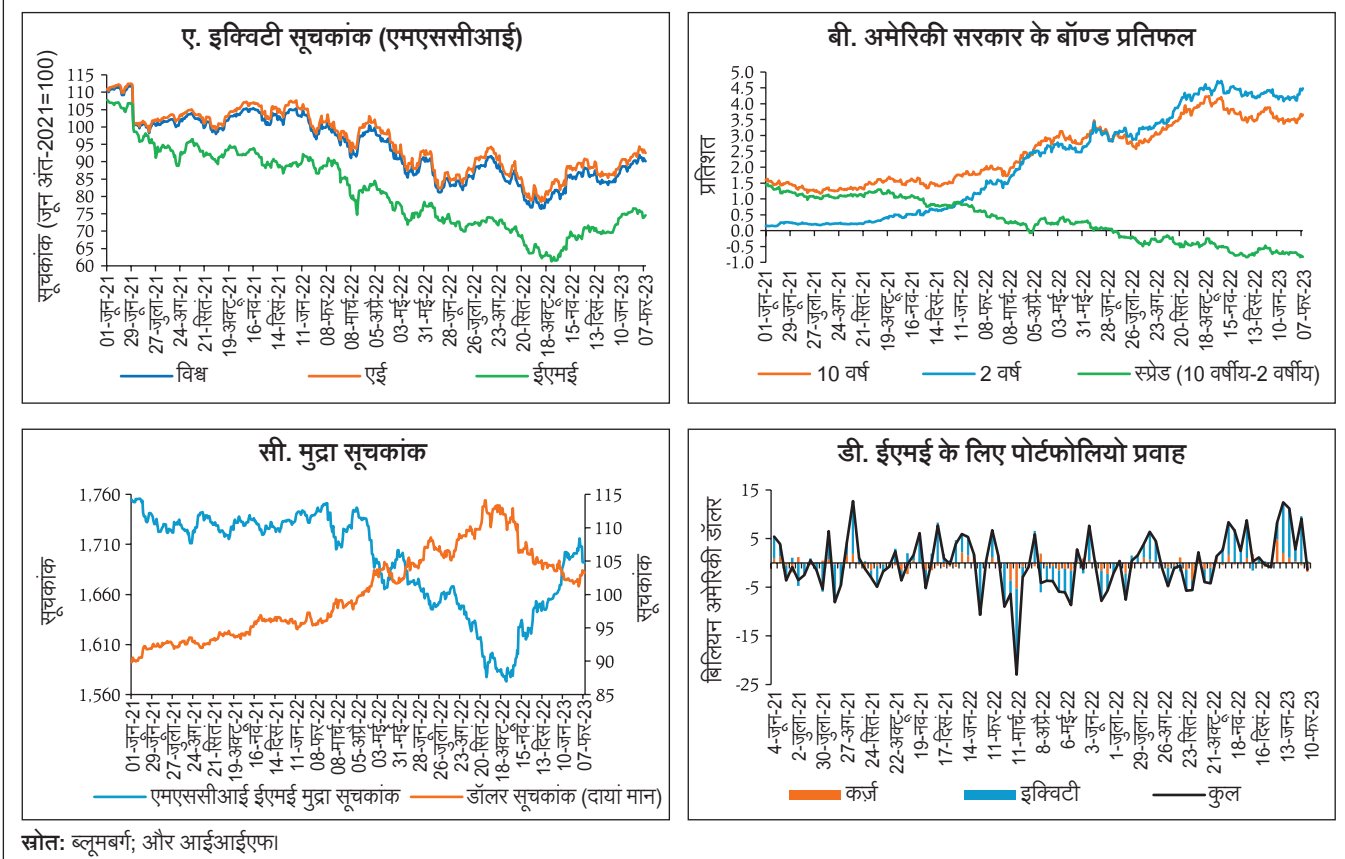
चार्ट 6: मुद्रास्फीति



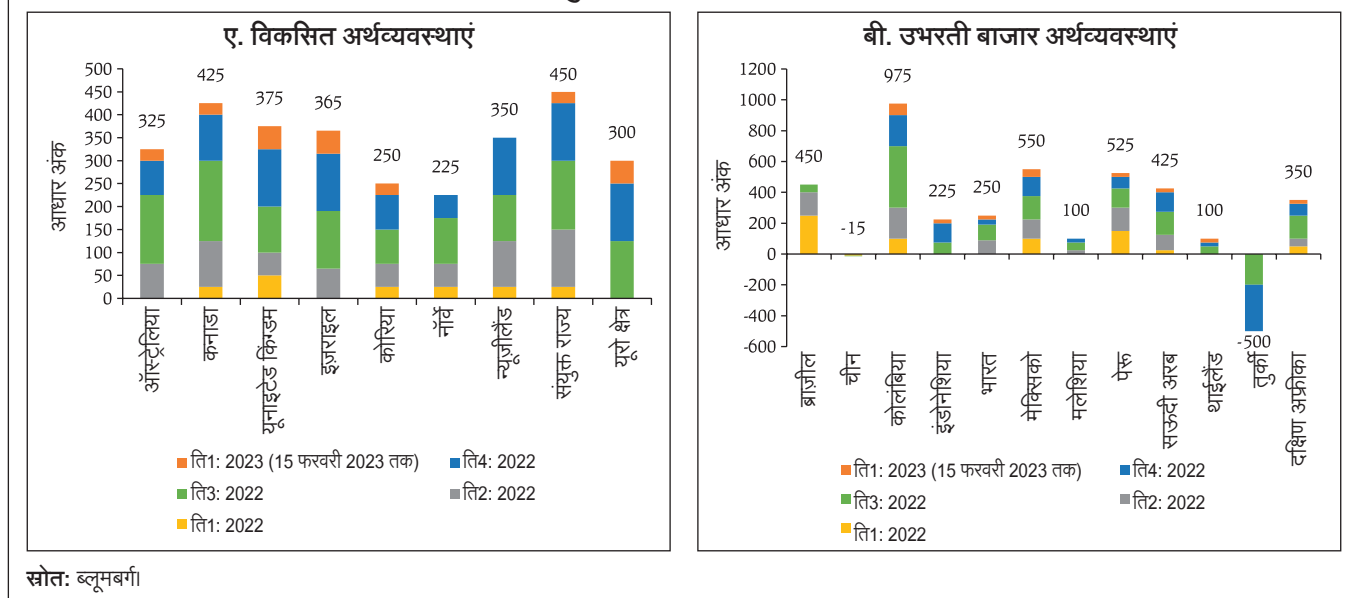
जनवरी 2023 के दौरान, अमेरिका सहित अधिकांश देशों में उम्मीद से कम मुद्रास्फीति के कारण प्रमुख एई में 10-वर्षीय जी-

सेक प्रतिफल कम हो गया, जिसके परिणामस्वरूप 10-वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में 37 आधार अंकों की गिरावट आई और

चार्ट 7: वित्तीय बाजार



चार्ट 8: प्रमुख नीतिगत दर में उतार-चढ़ाव



2-वर्षीय जी-सेक यील्ड में 22 बीपीएस की कमी आई। इससे उपज वक्र व्युत्क्रमण का परिमाण बढ़ गया (चार्ट 7बी)। हालांकि, फरवरी में अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल अनुमान से अधिक अमेरिकी गैर-कृषि पेट्रोल आंकड़ों के कारण मजबूत हुआ और 2 साल के जी-सेक प्रतिफल में 20 आधार अंकों (08 फरवरी, 2023 तक) की वृद्धि हुई। अमेरिकी डॉलर ने सितंबर 2022 में चरम पर पहुंचने के बाद अपनी तेजी को उलट दिया और जनवरी में कम आक्रामक नीतिगत दरों में वृद्धि की उम्मीद में 1.4 प्रतिशत गिर गया। इसके साथ-साथ, ईएमई के लिए एमएससीआई मुद्रा सूचकांक ने गति प्राप्त की, पूंजी प्रवाह (चार्ट 7 सी और 7 डी) के कारण 2.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

अधिकांश एई और ईएमई के केंद्रीय बैंकों ने हाल के महीनों में सख्ती की गति को धीमा कर दिया (चार्ट 8 ए)। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने फेडरल फंड्स रेट की लक्ष्य सीमा 25 आधार अंक बढ़ाकर 4.50-4.75 प्रतिशत कर दी है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) और बैंक ऑफ इंग्लैंड (बीओई) ने फरवरी 2023 में अपनी प्रमुख दरों में 50 बीपीएस की वृद्धि करने का फैसला किया। कनाडा ने जनवरी में अपनी नीतिगत दर में 25 आधार अंकों की वृद्धि की और ऑस्ट्रेलिया ने फरवरी की बैठक में अपनी दर में 25 बीपीएस की वृद्धि जारी रखी। जापान ने उदार रुख बनाए रखते

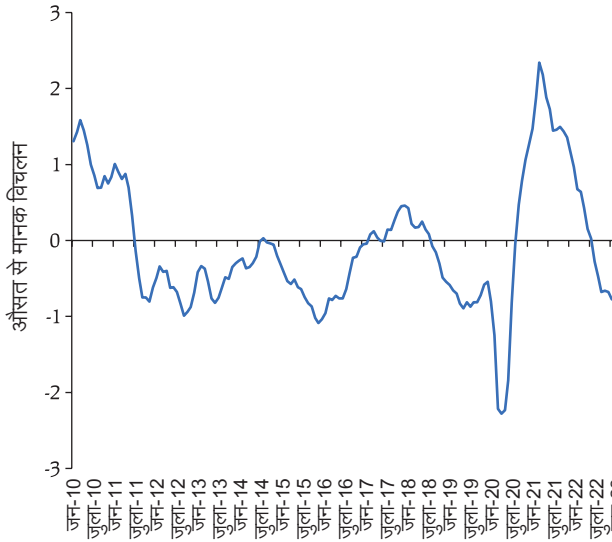
हुए अलग रहना जारी रखा है; हालांकि, इसने 10 साल के सरकारी बॉन्ड प्रतिफल में उतार-चढ़ाव के लिए अपनी सीमा का विस्तार किया।

अधिकांश ईएमई केंद्रीय बैंकों ने भी नीतिगत सख्ती जारी रखी है, जबकि कुछ अन्य रुक गए हैं (चार्ट 8 बी)। दिसंबर में, दक्षिण अफ्रीका ने अपनी नीतिगत दर में वृद्धि की गति को 75 बीपीएस से 25 बीपीएस तक कम कर दिया और सऊदी अरब ने अपनी जनवरी की बैठक में 50 बीपीएस से 25 बीपीएस तक धीमा कर दिया। इंडोनेशिया और थाईलैंड ने जनवरी में अपनी नीतिगत दरों में 25-25 आधार अंकों की वृद्धि की थी। ब्राजील ने फरवरी में और मलेशिया, चिली और हंगरी ने जनवरी में अपनी प्रमुख दरों को अपरिवर्तित रखा। इसके विपरीत, चीन ने मौद्रिक समायोजन जारी रखा।

III. घरेलू घटनाक्रम

भारतीय अर्थव्यवस्था में आपूर्ति प्रतिक्रियाओं और समग्र लागत की स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। आपूर्ति श्रृंखला दबाव कम होता रहा जैसा कि भारत के लिए आपूर्ति श्रृंखला दबाव के हमारे सूचकांक द्वारा इंगित किया गया है (आईएसपीआई) [चार्ट 9]।

चार्ट 9: भारत के लिए आपूर्ति शृंखला दबाव सूचकांक



स्रोत: आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

आर्थिक गतिविधि सूचकांक (ईएआई) ने नवंबर और दिसंबर 2022 में गतिविधि में तेजी दिखाई (चार्ट 10 ए)। तदनुसार,

2022-23 की तीसरी तिमाही के लिए हमारे सकल घरेलू उत्पाद का अब का अनुमान 4.4 प्रतिशत पर रखा गया है (चार्ट 10 बी)।

कुल मांग

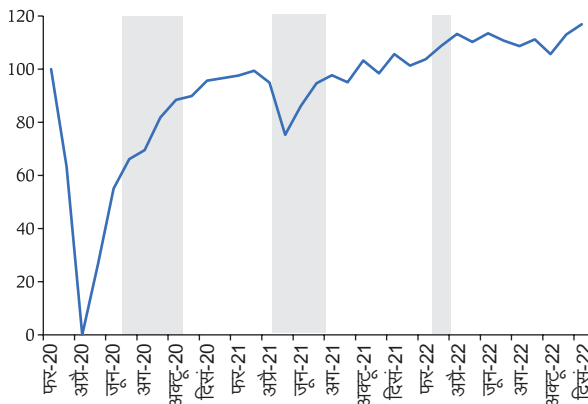
प्रमुख संकेतक आर्थिक गतिविधियों में निरंतर गति की ओर इशारा करते हैं। हालांकि ई-वे बिल की मात्रा और टोल संग्रह में मध्यम गति से वृद्धि जारी रही। (चार्ट 11)।

मौसमी कारकों के कारण ईंधन की खपत दिसंबर में दर्ज नौ महीने के उच्च स्तर से नीचे आ गई। उच्च मांग के कारण ऑटोमोबाइल (यात्री और वाणिज्यिक वाहनों), दोपहिया वाहनों की बिक्री और वाहन पंजीकरण (परिवहन और गैर-परिवहन वाहन) में तेजी आई। फसल की बेहतर कीमतों ने ट्रैक्टर की बिक्री में तेजी लाने में मदद की है। मोटरसाइकिल और तिपहिया वाहनों की बिक्री में भी तेजी आई, जो बाद में जनवरी 2022 की तुलना में दोगुनी से अधिक हो गई (चार्ट 12)।

पर्यटन क्षेत्र में, कमरे की औसत दरों में वृद्धि जारी रही, भले ही होटल रिहाइश दरें सपाट रहीं। नवंबर में गिरावट दर्ज करने के

चार्ट 10: आर्थिक गतिविधि और जीडीपी तात्कालिक अनुमान

ए: आर्थिक गतिविधि सूचकांक



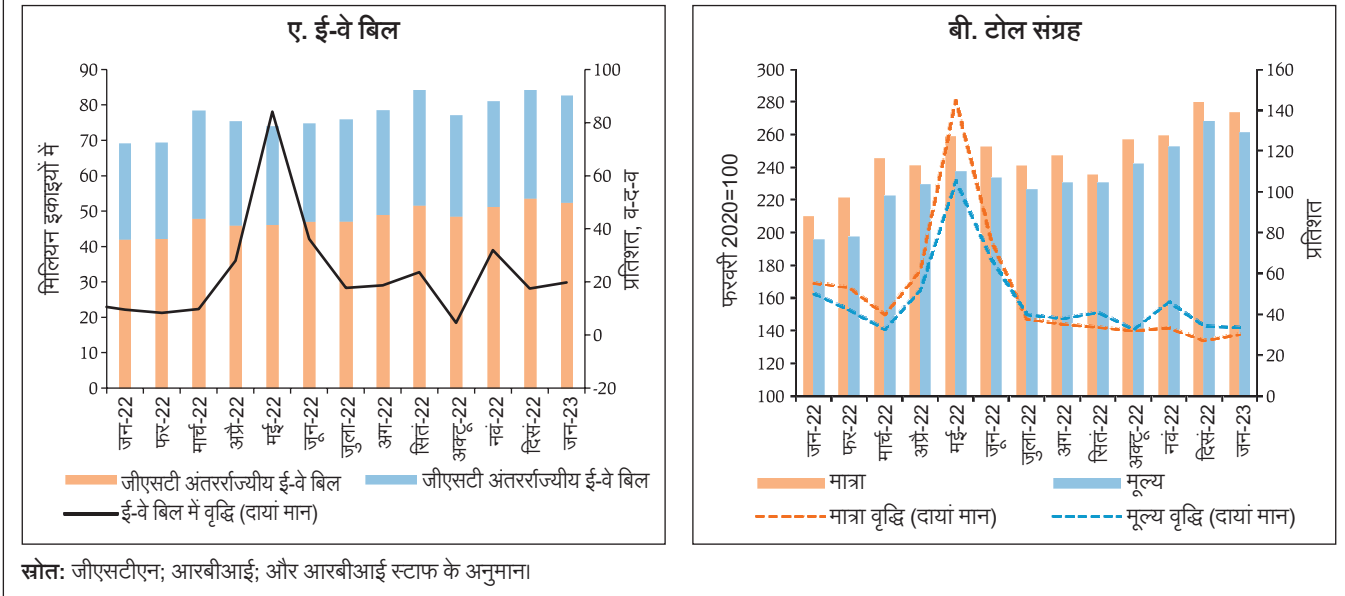
टिप्पणी: गतिविधि सूचकांक का निर्माण गतिशील कारक मॉडल (डीएफएम) का उपयोग करके आर्थिक गतिविधि के चयनित उच्च आवृत्ति संकेतकों के एक समूह के अंतर्गत सामान्य प्रवृत्ति की पहचान कर किया गया है। ईएआई के लिए मान फरवरी 2020 के लिए 100 और अप्रैल 2020 के लिए 0 तक पहुंचा है। छायांकित क्षेत्र उन अवधियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जब दैनिक नए पुष्ट मामले 50,000 से अधिक हो गए।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

बी: जीडीपी- वास्तविक और तात्कालिक अनुमान



स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

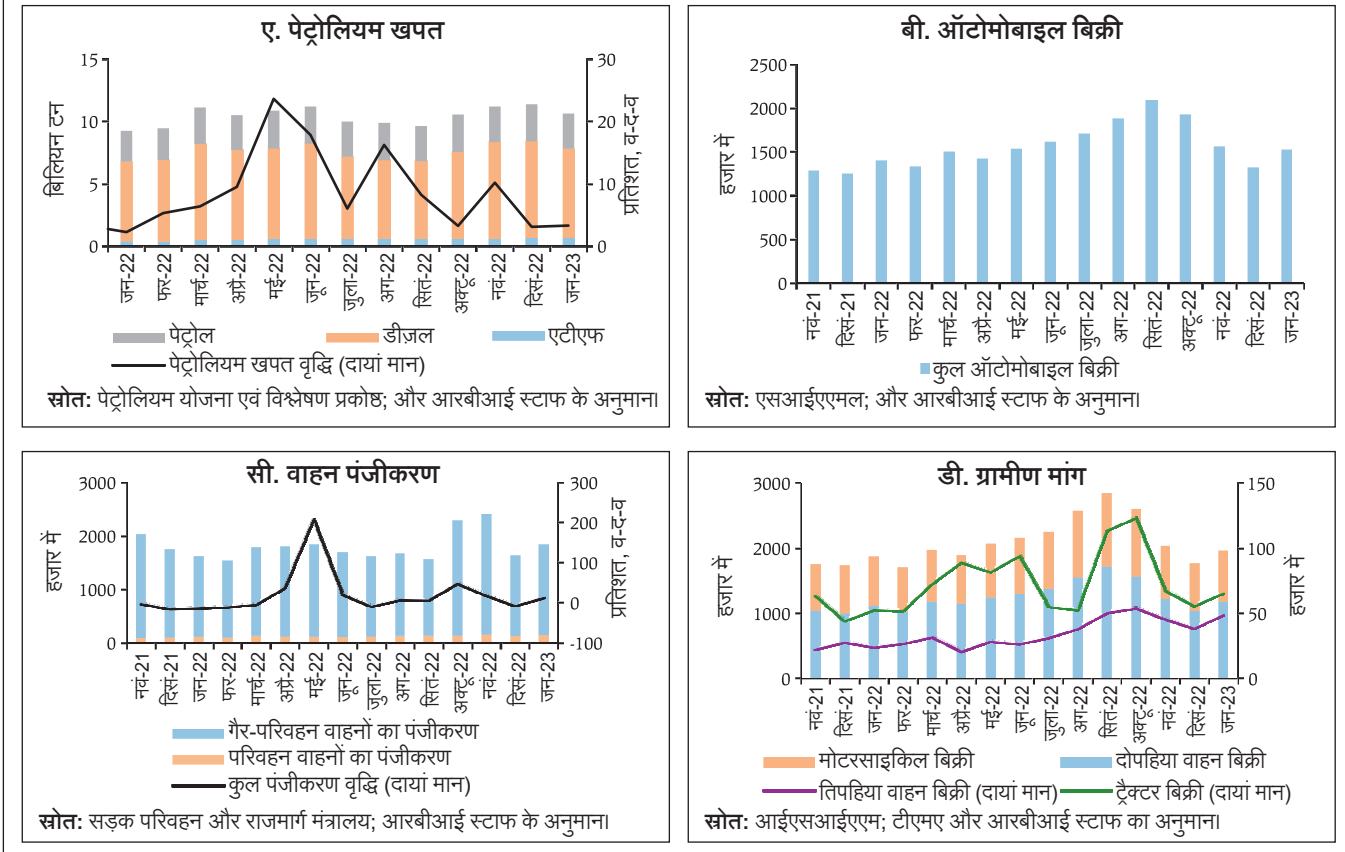
चार्ट 11: ई-वे बिल और टोल संग्रह



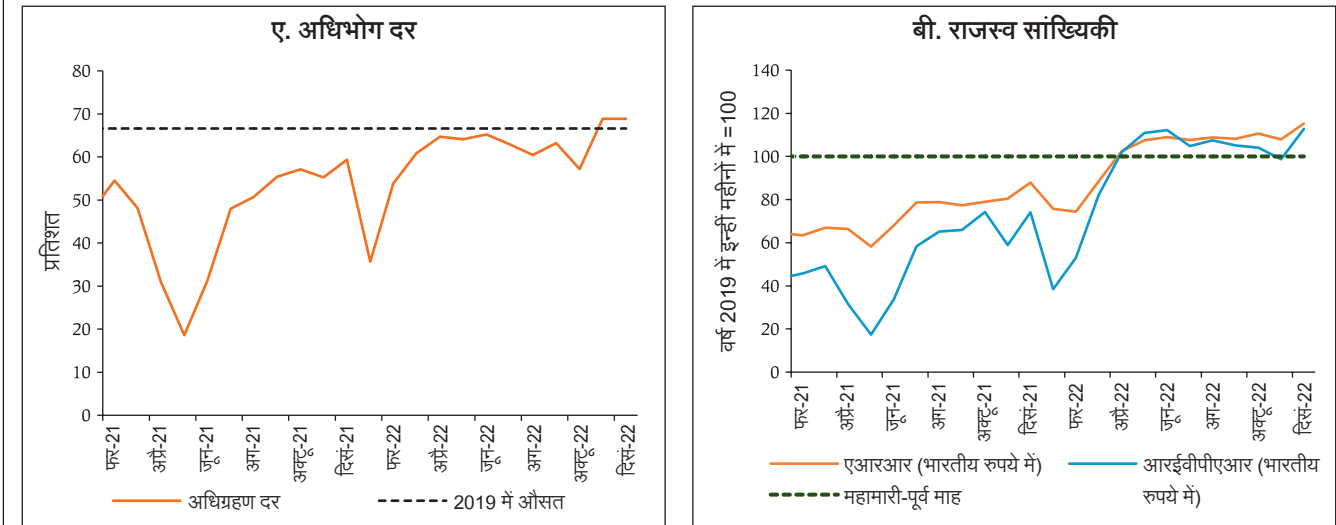
बाद, प्रति उपलब्ध कमरे (आरईवीपीएआर) राजस्व में वृद्धि हुई (चार्ट 13)।

रिजर्व बैंक के उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस) में रिपोर्ट की गई आर्थिक स्थितियों के लिए परिवारों का आकलन और

चार्ट 12: ऑटोमोबाइल क्षेत्र के संकेतक



चार्ट 13: होटल क्षेत्र के संकेतक



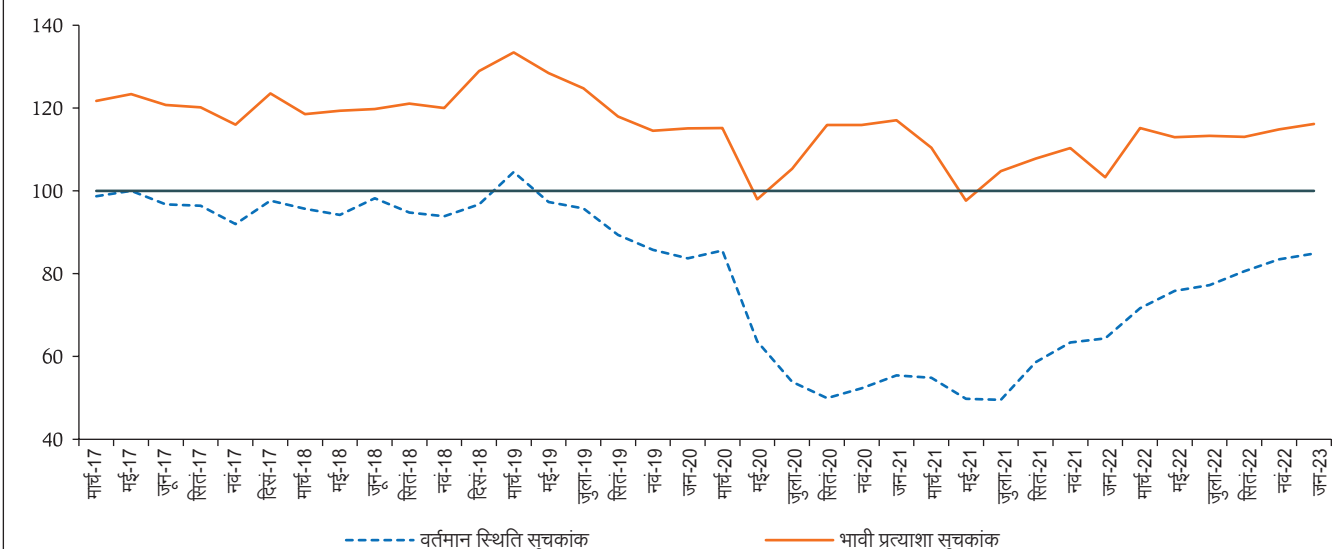
टिप्पणी: एआरआर; कमरे की औसत दर।
स्रोत: एचवीएस एनारोक; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

दृष्टिकोण वर्तमान स्थिति सूचकांक (सीएसआई) के साथ-साथ एक साल की अवधि में भविष्य की अपेक्षा सूचकांक (एफईआई) में परिलक्षित बढ़ते विश्वास की ओर इशारा करता है (चार्ट 14)।

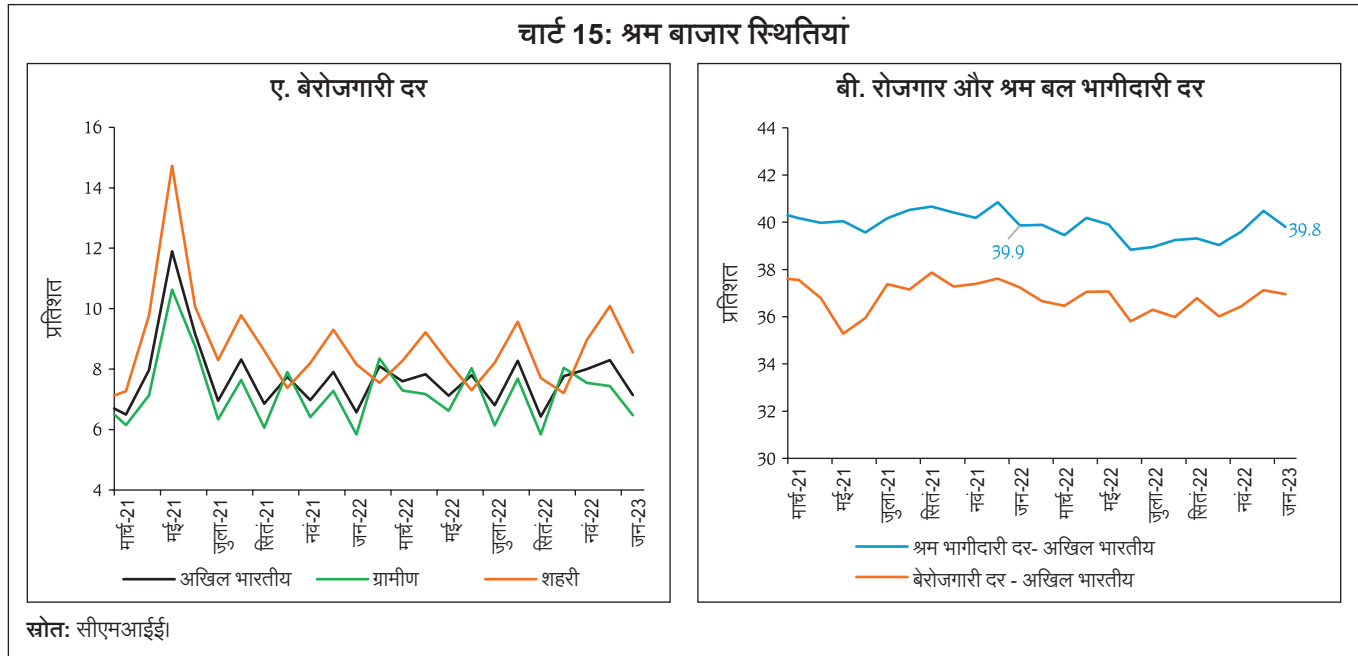
शहरी बेरोजगारी में अपेक्षाकृत बड़ी गिरावट के कारण, अखिल भारतीय बेरोजगारी दर दिसंबर 2022 में 8.3 प्रतिशत से

घटकर जनवरी 2023 में 7.1 प्रतिशत हो गई (चार्ट 15 ए)। हालांकि, श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) जनवरी में पिछले महीने के 40.5 प्रतिशत से घटकर 39.8 प्रतिशत हो गई, जिसमें रोजगार दर (ईआर) काफी हद तक सपाट रही (चार्ट 15 बी)।

चार्ट 14: उपभोक्ता विश्वास सूचकांक



स्रोत: आरबीआई।

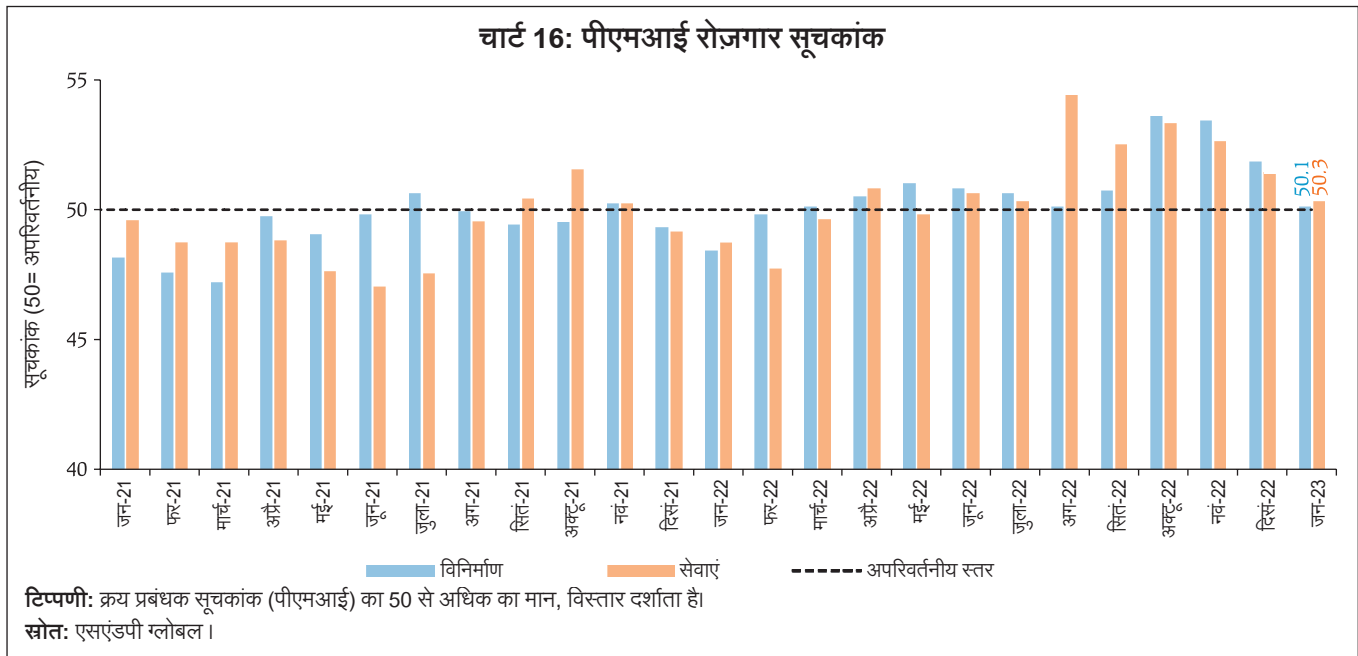


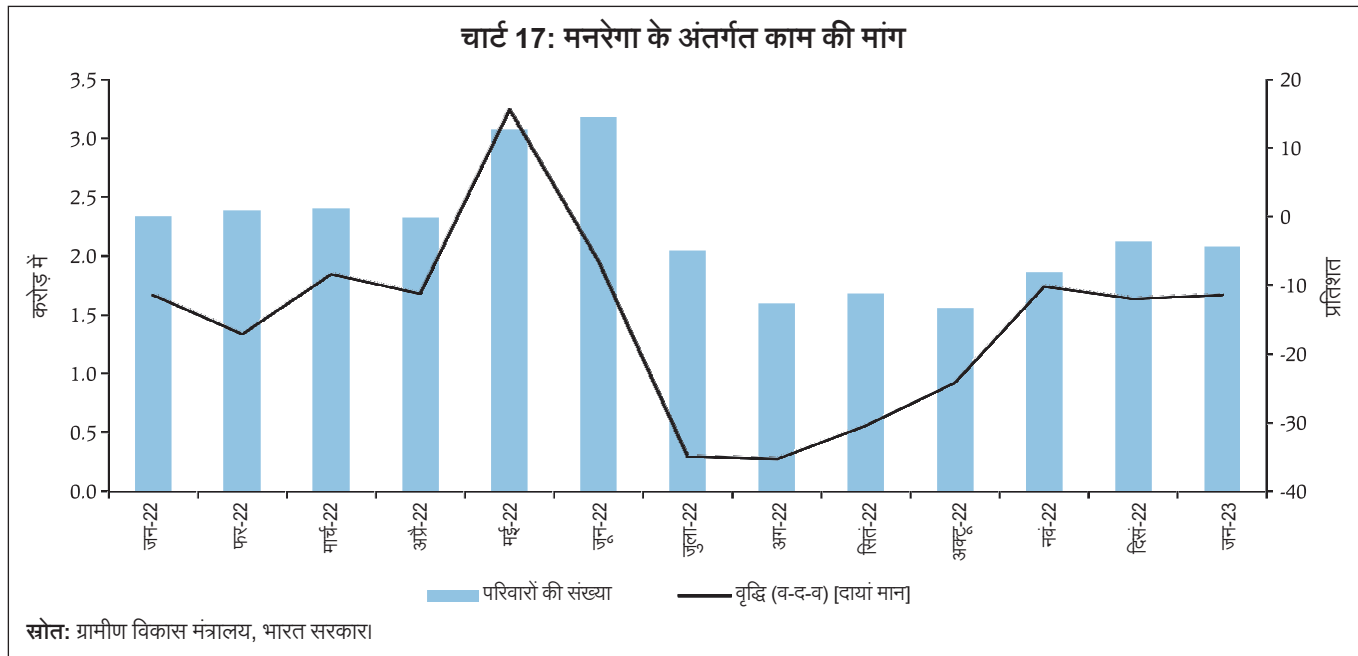
पीएमआई रोजगार सूचकांक जनवरी 2023 में मोटे तौर पर अपरिवर्तित रहा (चार्ट 16)।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत कार्य की मांग में वर्ष-दर-वर्ष

आधार पर गिरावट आई है, जो अन्य गतिविधियों विशेष रूप से रबी बुवाई में श्रम मांग में वृद्धि को दर्शाती है (चार्ट 17)।

जनवरी 2023 में भारत का व्यापारिक निर्यात 32.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें सालाना आधार पर 6.6 प्रतिशत और



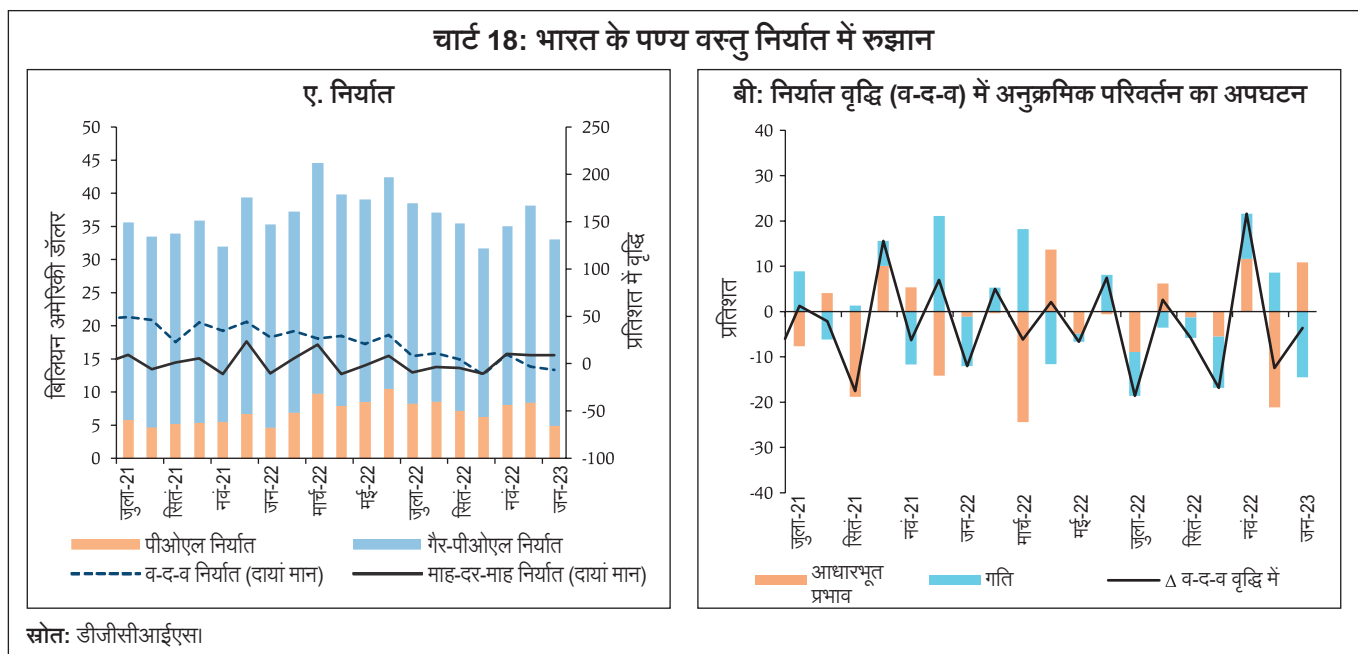


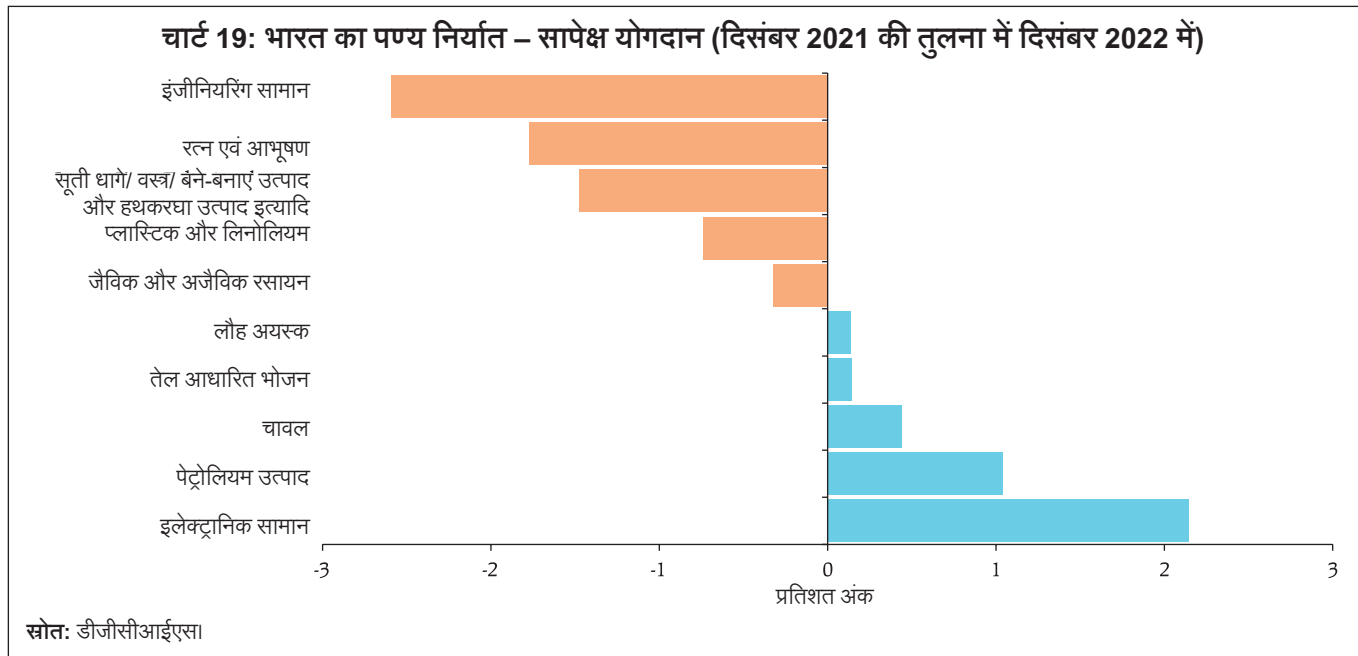
क्रमिक आधार पर 13.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई (चार्ट 18)। अप्रैल-जनवरी 2022-23 के दौरान, संचयी व्यापारिक निर्यात 8.5 प्रतिशत बढ़कर 369.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।

जनवरी 2023 में गैर-तेल निर्यात में सालाना आधार पर 8.7 प्रतिशत की गिरावट आई, जिसमें इंजीनियरिंग सामान, रत्न और आभूषण, और सूती धागे और कपड़े में गिरावट आई (चार्ट 19)। दूसरी ओर, पेट्रोलियम उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक सामान और चावल ने समग्र निर्यात में सकारात्मक योगदान दिया।

सॉफ्टवेयर और यात्रा सेवाओं से होने वाली कमाई के कारण भारत का सेवा निर्यात जो 31.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, उसमें दिसंबर 2022 में 20.4 प्रतिशत की जोरदार वृद्धि हुई (दिसंबर 2021 में 26.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर)।

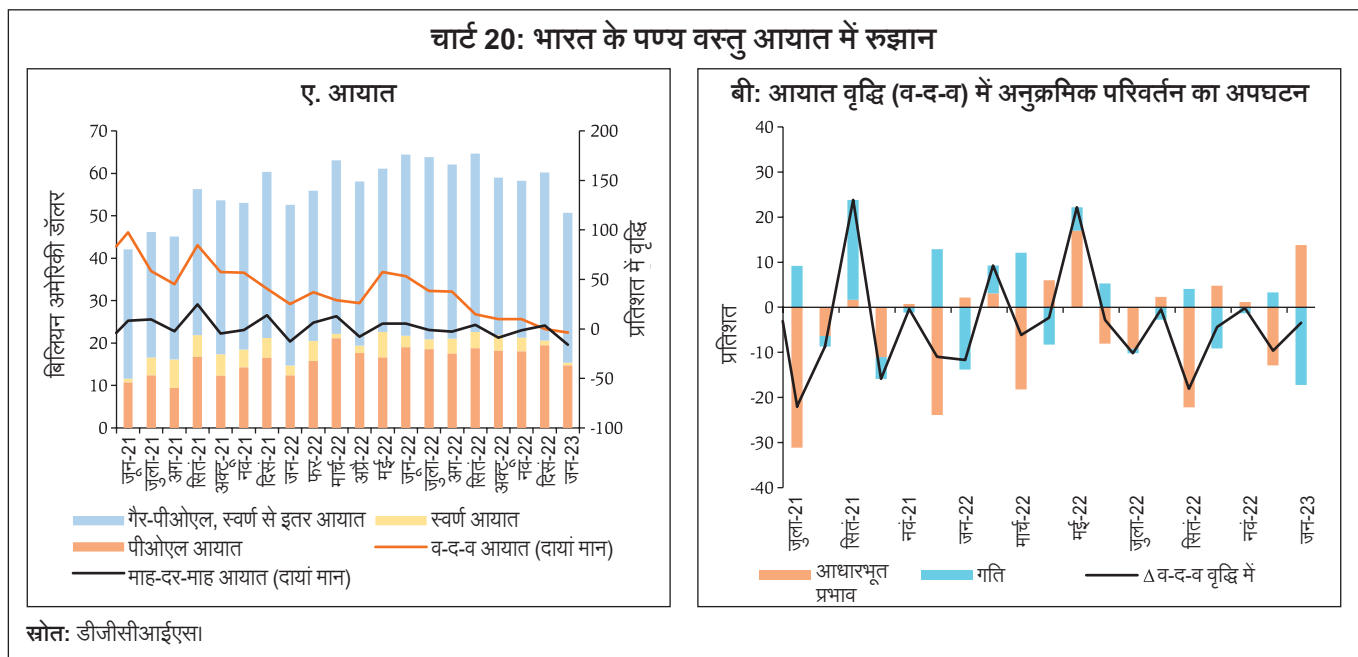
जनवरी 2023 में 50.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापारिक आयात में 3.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की गिरावट आई, जो आंशिक रूप से कच्चे तेल, कुछ उर्वरकों और वनस्पति तेलों



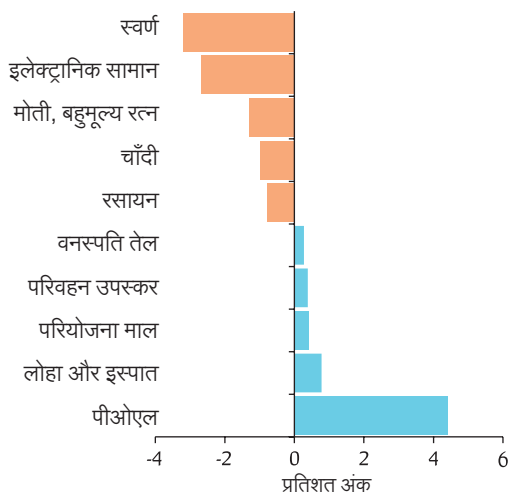


की कीमतों में गिरावट को दर्शाती है। क्रमिक आधार पर, आयात में गिरावट 15.8 प्रतिशत (चार्ट 20) पर और भी तेज थी। सोना, इलेक्ट्रॉनिक सामान और मोती और कीमती पत्थर वे मुख्य वस्तुएं थीं जिन्होंने आयात को नीचे खींच लिया, जबकि पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक (पीओएल), लोहा और इस्पात और परियोजना के सामान जैसी वस्तुओं ने सकारात्मक योगदान दिया (चार्ट 21)।

जनवरी 2023 में अंतरराष्ट्रीय सोने की कीमतें 9 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचने के साथ, भारत का सोने का आयात 70.8 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की गिरावट के साथ 20 महीने के निचले स्तर 697 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर आ गया। लगातार 25 महीनों तक विस्तारक्षेत्र में रहने के बाद, गैर-तेल गैर-सोना (एनओजी) आयात जनवरी 2023 में 6.7 प्रतिशत घट गया।



चार्ट 21: भारत का पण्य आयात: सापेक्ष योगदान (दिसंबर 2021 की तुलना में दिसंबर 2022 में)



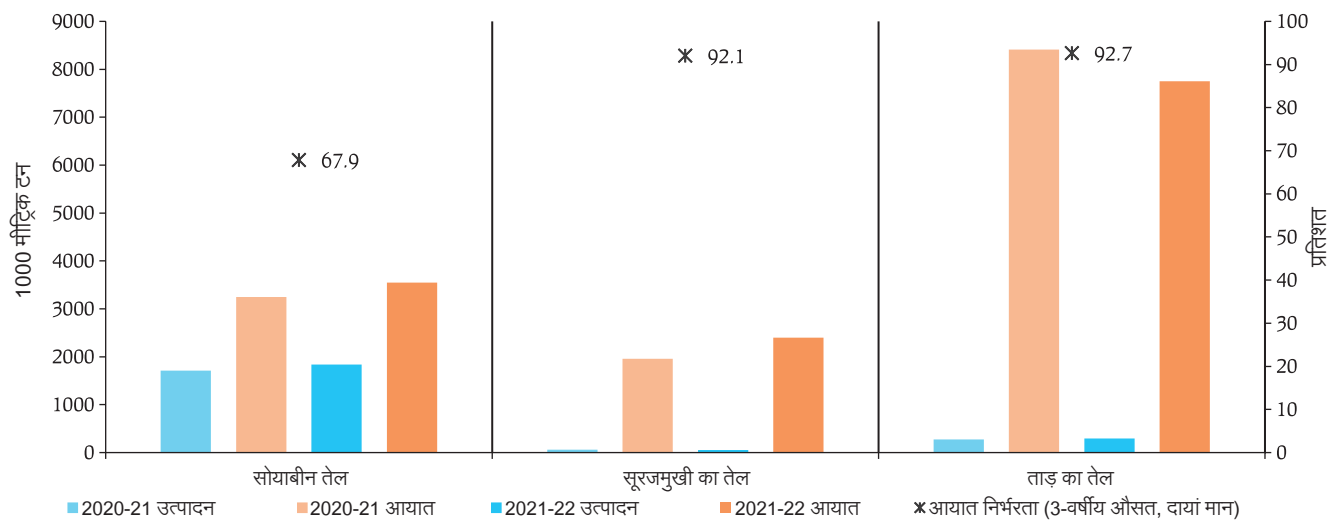
स्रोत: डीजीसीआईएसा

खाद्य तेल - जिसके लिए भारत आयात¹⁰ पर बहुत अधिक निर्भर है - ने दिसंबर 2022¹¹ में मात्रा में 28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की और 15.6 लाख मीट्रिक टन (एमटी) तक पहुंच गया। जबकि

पाम तेल खाद्य तेल आयात का 71 प्रतिशत था, सूरजमुखी और सोयाबीन तेल शेष थे (चार्ट 22)। हालांकि, दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक इंडोनेशिया द्वारा कुछ निर्यात परमिट निलंबित किए जाने के संकेत के बाद फरवरी के दूसरे सप्ताह में अंतरराष्ट्रीय पाम तेल की कीमतों में तेजी से उछाल आया।¹² नवंबर-दिसंबर 2022 के दौरान, इंडोनेशिया परिष्कृत ब्लिचड डिओडोराइज्ड (आरबीडी) पामोलीन और कच्चे पाम तेल का भारत का प्रमुख आपूर्तिकर्ता था।¹³

सकारात्मक बात यह है कि फसल वर्ष 2022-23 में सरसों के बीज का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की संभावना है क्योंकि 98 लाख हेक्टेयर में अब तक की सबसे अधिक बुआई कवरेज और प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में मौसम अनुकूल है। चूंकि सरसों के तेल की घरेलू खाद्य तेल उत्पादन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, इसलिए फसल का ज्यादा उत्पादन अन्य खाद्य तेलों के आयात को कम करने में मदद कर सकता है।¹⁴ इसके अलावा, 2021 में शुरू किए गए सरकार के 'खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन - ऑयल पाम' का उद्देश्य घरेलू कच्चे पाम तेल उत्पादन

चार्ट 22: भारत में खाद्य तेल आयात निर्भरता



टिप्पणी: भारत का खाद्य तेल उत्पादन और आयात, विपणन वर्ष (अक्टूबर-सितंबर) के लिए हैं।

स्रोत: अमेरिकी कृषि विभाग, विदेशी कृषि सेवा

¹⁰ खाद्य तेल के लिए भारत की घरेलू मांग का लगभग 55 प्रतिशत आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है।

¹¹ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया।

¹² <https://www.reuters.com/markets/commodities/indonesia-suspend-some-palm-oil-export-permits-senior-official-2023-02-06/>

¹³ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया।

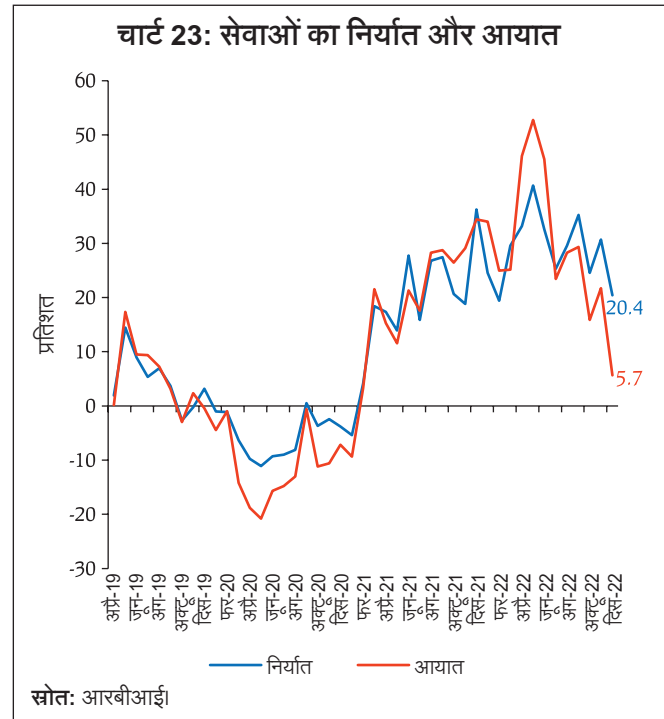
¹⁴ https://www.agriwatch.com/newsdetails.php?st=NEWS&commodity_id=11&sid=631435

को 2019-20 में 0.27 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 2025-26 तक 11.20 लाख मीट्रिक टन करके पाम तेल पर आयात निर्भरता को कम करना है। आयात में तेज गिरावट के कारण, जनवरी 2023 में पण्य व्यापार घाटा 17.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के 12 महीने के निचले स्तर पर आ गया।

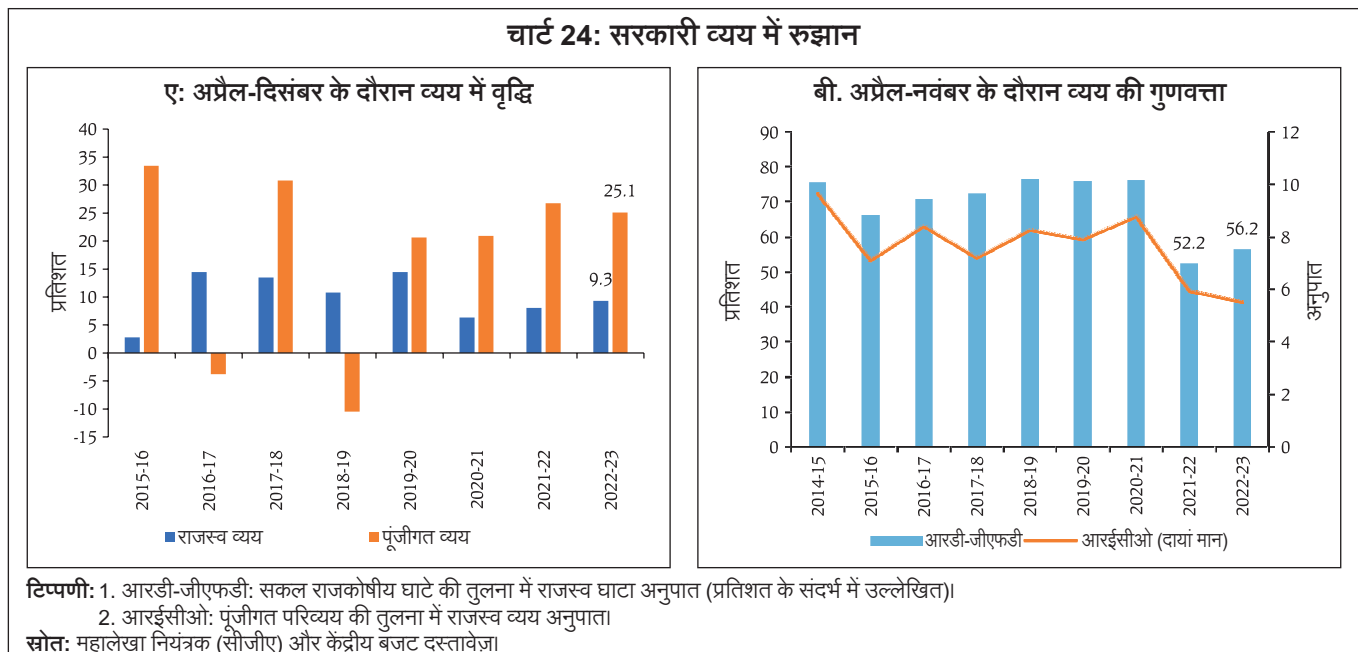
उच्च आधार और परिवहन सेवाओं में गिरावट के कारण 15.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सेवा आयात में कमी आई। तदनुसार, दिसंबर 2022 के लिए निवल सेवा आय 15.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है (चार्ट 23)।

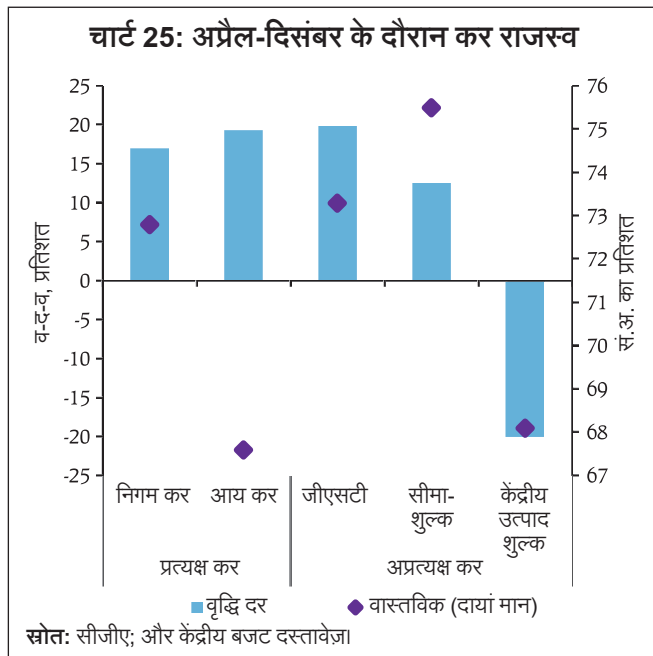
अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान केंद्र सरकार का सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) संशोधित अनुमानों (आरई) का 56.6 प्रतिशत था, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अधिक (47.7 प्रतिशत) था। पूंजीगत परिव्यय में 17.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जबकि राजस्व व्यय में 9.3 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की गई, जिससे खर्च की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ (चार्ट 24)।

अप्रैल-दिसंबर के दौरान उत्पाद शुल्क को छोड़कर (मई 2022 में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती के कारण) सभी क्षेत्रों में संग्रहण में सुधार के साथ सकल कर राजस्व में 12.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में क्रमशः 17.6 प्रतिशत और 7.2 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि



हुई (चार्ट 25)। हालांकि गैर-कर राजस्व में 17.4 प्रतिशत की गिरावट आई है। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के सफल आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के कारण गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में 93.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई।



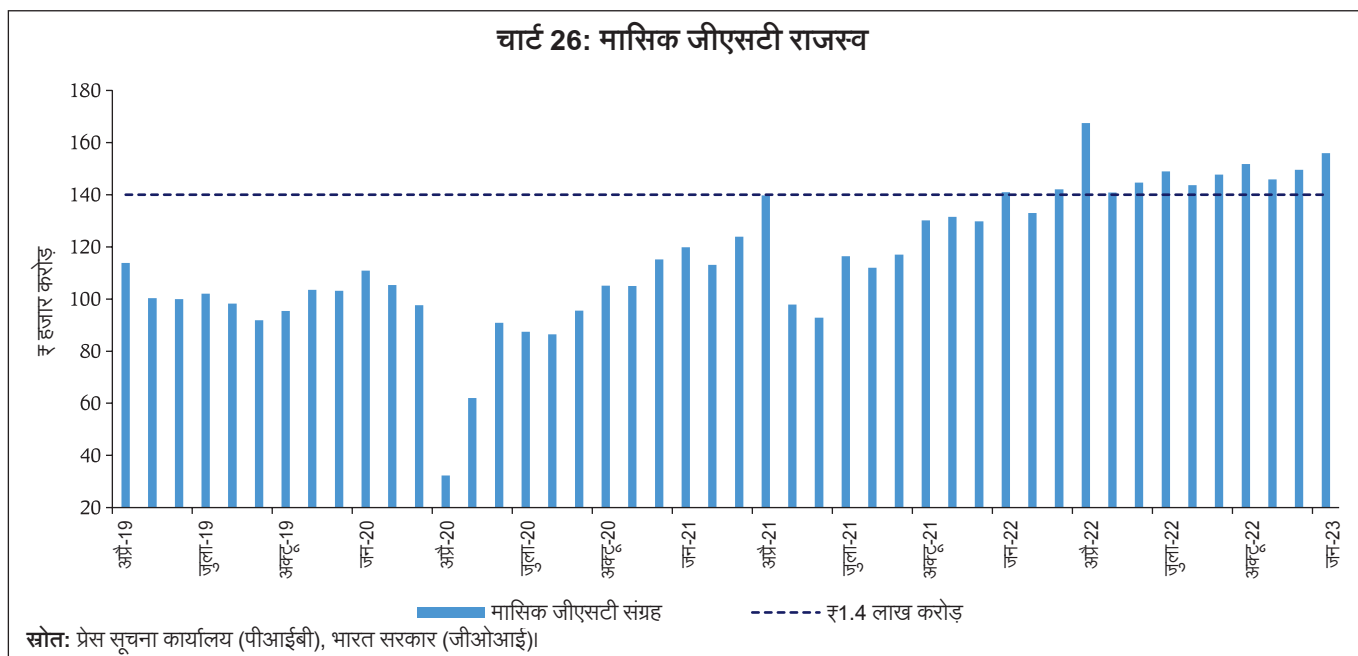


जनवरी 2023 में जीएसटी संग्रहण (केंद्र और राज्य) 10.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 1.55 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो अप्रैल 2022 के बाद से सबसे अधिक संग्रहण है (चार्ट 26)।

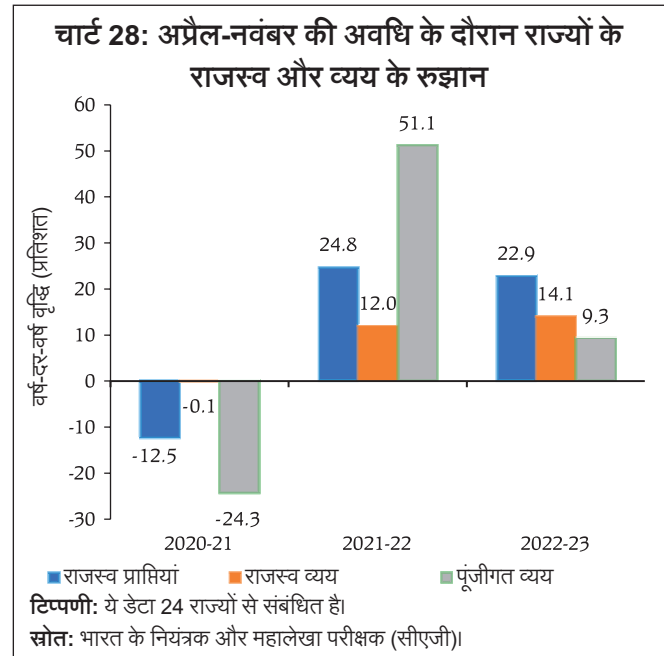
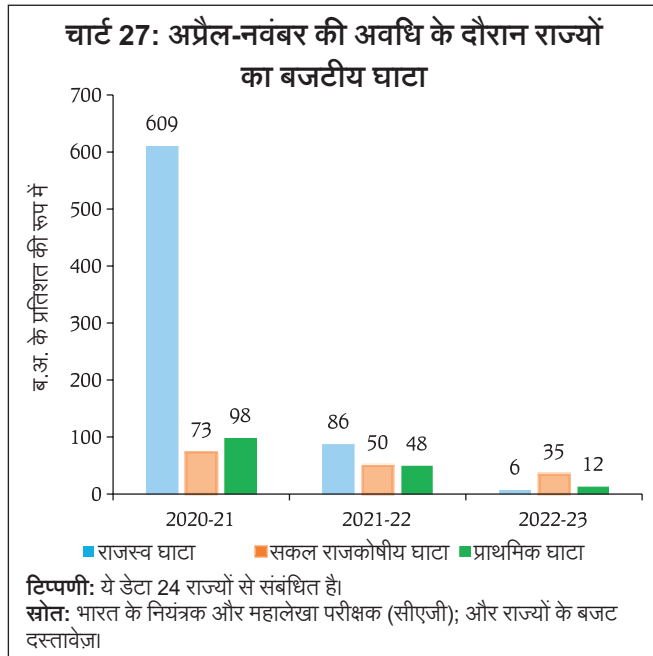
राज्यों की वित्तीय स्थिति में सुधार जारी है, जैसा कि अप्रैल-नवंबर 2022 के दौरान बजटीय घाटे में गिरावट से परिलक्षित होता है (चार्ट 27)।¹⁵

एसजीएसटी संग्रहण में उच्च वृद्धि और केंद्र से कर हस्तांतरण के कारण राजस्व प्राप्तियों में ठोस वृद्धि बनी हुई है। राजस्व व्यय में गति भी बनी हुई है। संबंधित अवधि में पूंजीगत व्यय में 9.3 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई (चार्ट 28)। पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता 2022-23 के तहत कर हस्तांतरण में वृद्धि और उठाव में वृद्धि के साथ पूंजीगत व्यय में यह गति 2022-23 की चौथी तिमाही में बनी रहने की उम्मीद है।

केंद्रीय बजट 2023-24 में पूंजीगत व्यय पर ध्यान केंद्रित करते हुए बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया गया है, जिससे निजी निवेश में भरमार और रोजगार सृजन तथा मांग के मजबूत होने की उम्मीद है। सरकार ने 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद के 6.4 प्रतिशत के बजटीय राजकोषीय लक्ष्य का पालन किया (संशोधित अनुमान, आरई के अनुसार)। हालांकि, पूर्ण रूप से, जीएफडी ने बजट अनुमानों (बीई) को 94,123 करोड़ रुपये से पार कर लिया क्योंकि राजस्व व्यय में वृद्धि प्राप्तियों में वृद्धि से अधिक थी। 2023-24 (बजट अनुमान) में जीएफडी का बजट जीडीपी के 5.9 प्रतिशत पर रखा गया है, जो 2025-26 तक जीएफडी को 4.5 प्रतिशत से नीचे लाने के मध्यम अवधि के लक्ष्य के अनुरूप है।



¹⁵ आंकड़े 24 राज्यों से संबंधित हैं।



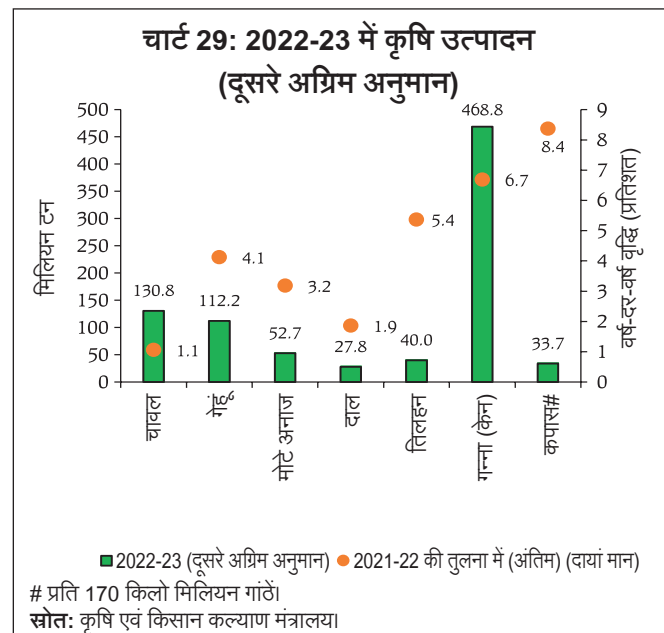
वित्त वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय का लक्ष्य 10 लाख करोड़ रुपये रखा गया है जो जीडीपी का 3.3 प्रतिशत है। प्रभावी पूंजीगत व्यय, जिसमें केंद्र का पूंजीगत व्यय और पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए राज्यों को सहायता अनुदान शामिल है, का बजट 2023-24 (बीई) में सकल घरेलू उत्पाद का 4.5 प्रतिशत है। इसके विपरीत राजस्व व्यय में 1.2 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। 2023-24 के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल बाजार उधार 8.6 प्रतिशत बढ़कर 15.4 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जबकि 2023-24 के दौरान 11.8 लाख करोड़ रुपये पर निवल बाजार उधार 6.6 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है।

केंद्रीय बजट 2023-24 में राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 3.5 प्रतिशत तय की गई है, जिसमें से 0.5 बिजली क्षेत्र के सुधारों से जुड़ा होगा। केंद्र ने राज्यों को उनके पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के लिए 2023-24 के दौरान 1.3 ट्रिलियन रुपये के बढ़े हुए आवंटन के साथ ब्याज मुक्त 50 साल के ऋण प्रदान करना जारी रखने का भी फैसला किया है।

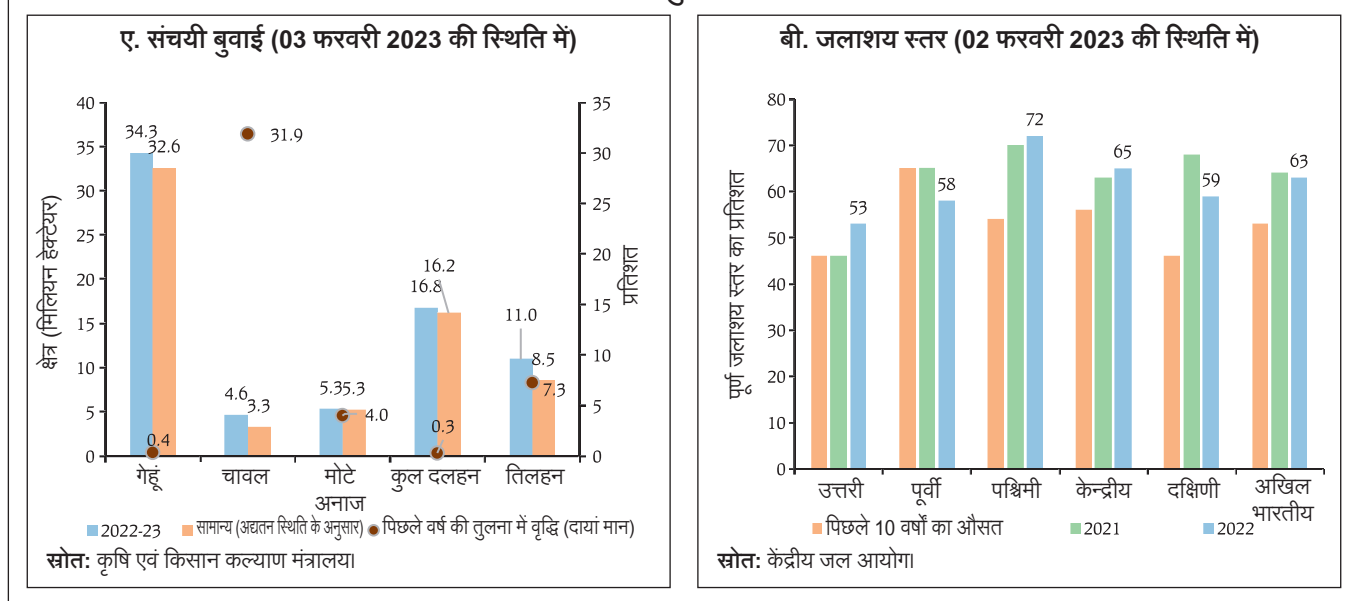
कुल आपूर्ति

कृषि फसल उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमानों (एई) के अनुसार, भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन 2022-23 में 323.6 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है, जो 2021-22 के अंतिम

अनुमानों की तुलना में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। रबी फसलों की 6.2 प्रतिशत की वृद्धि ने खरीफ खाद्यान्न उत्पादन में 1.2 प्रतिशत की गिरावट की भरपाई कर दी है, जिसके परिणामस्वरूप रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। खाद्य फसल श्रेणी में गेहूं (एक रबी स्टेपल), मक्का और दालों के साथ-साथ वाणिज्यिक फसलों के बीच तिलहन और गन्ने के लिए नया उत्पादन रिकॉर्ड का अनुमान लगाया गया है। कपास उत्पादन ने एई के अनुसार उच्चतम वृद्धि दर दर्ज की है।(चार्ट 29)



चार्ट 30: रबी मौसम संचयी बुवाई और जलाशय की स्थिति



रबी फसल की बुवाई का मौसम 72.1 मिलियन हेक्टेयर के रिकॉर्ड क्षेत्रफल के साथ समाप्त हुआ, जिसमें सभी फसलों के तहत पर्याप्त वृद्धि हुई (चार्ट 30 ए)। जलाशय का स्तर सुखद रहा (चार्ट 30 बी)।

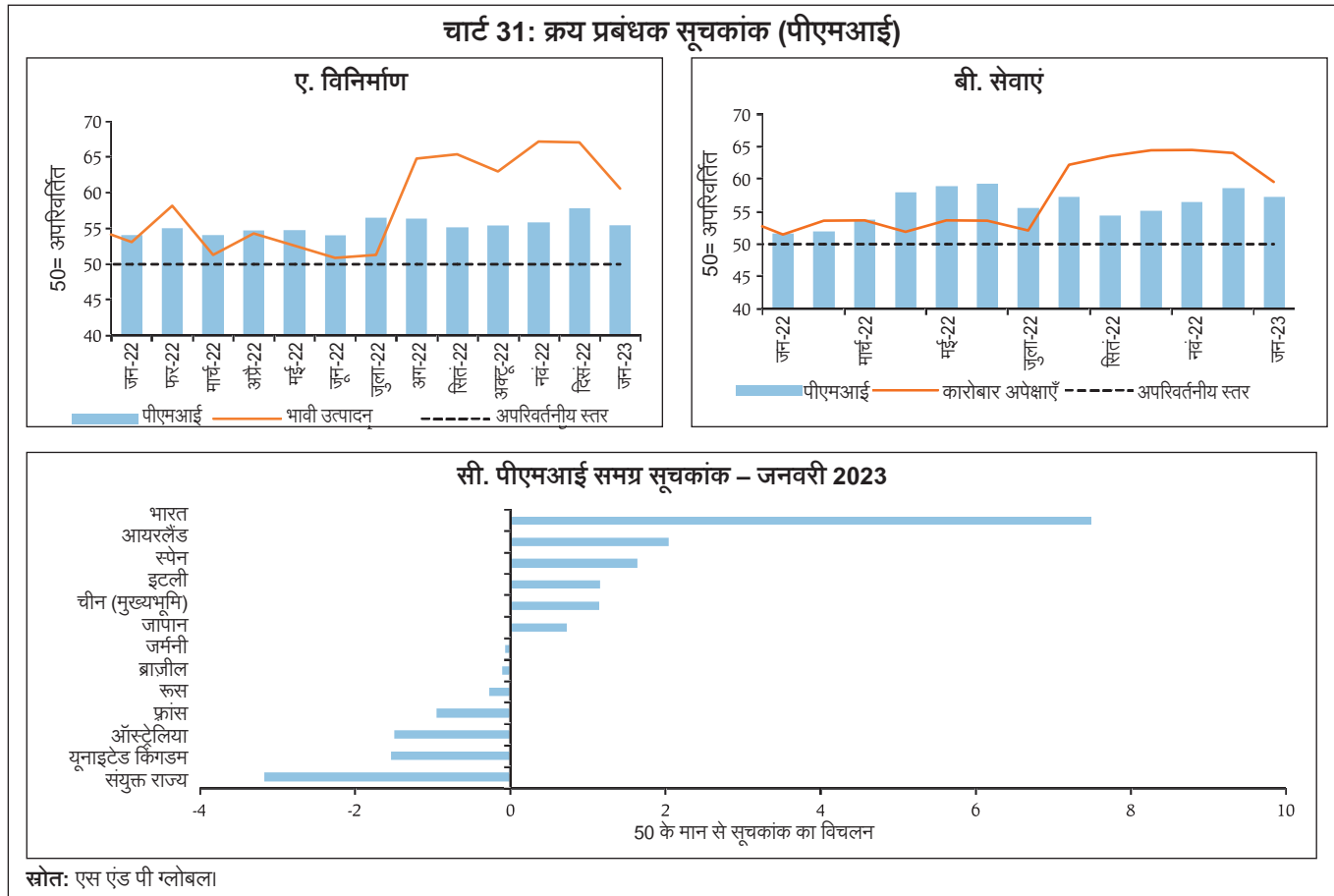
09 फरवरी, 2023 तक संचयी चावल खरीद (अनमिल्ड धान सहित) एक साल पहले की तुलना में मामूली रूप से कम थी, लेकिन चालू खरीफ विपणन सत्र में धान की मंडी आवक वर्ष-दर-वर्ष (09 फरवरी, 2023 तक) 36.9 प्रतिशत अधिक रही है। 01 फरवरी, 2023 तक चावल और गेहूं का सार्वजनिक स्टॉक बफर मानदंडों के क्रमशः 6.2 और 1.1 गुना पर संतोषजनक रहा। 25 जनवरी, 2023 को सरकार ने केंद्रीय पूल से विभिन्न चैनलों के माध्यम से 3 मिलियन टन गेहूं की खुले बाजार में बिक्री की घोषणा की। सबसे पहले, 16 फरवरी, 2023 को। यह पहले ही दो ई-नीलामी के माध्यम से 1.3 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं बेच चुका है। दूसरा, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी समितियों/परिसंघों, केंद्रीय भंडार और एनसीसीएफ/नैफेड को रियायती दर पर 3 लाख मीट्रिक टन गेहूं का आबंटन भी किया है।

केंद्रीय बजट 2023-24 कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक सुधारों और नीतियों पर केंद्रित है, जिनमें: (i) बाजरा के उत्पादन

और खपत में वृद्धि; (ii) संबद्ध क्षेत्रों का विविधीकरण और संवर्धन; (iii) अंतिम छोर तक संपर्क के लिए संभार तंत्र अवसंरचना को बढ़ावा देना; (iv) कृषि निर्यातों पर जोर देना; (v) सहकारी आधारित विकास और वृद्धि; और (vi) डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के माध्यम से कृषि विस्तार को सुदृढ़ करना शामिल हैं। सरकार नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कृषि गतवर्धक निधि के माध्यम से एक कृषि-तकनीकी स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र का पोषण करने का भी इरादा रखती है।

अनुक्रमिक बिलप के बावजूद जनवरी 2023 में विनिर्माण और सेवाओं के लिए हेडलाइन पीएमआई क्रमशः 55.4 और 57.2 पर, विस्तारवादी क्षेत्र में रहा (चार्ट 31 ए और 31 बी)। विनिर्माण और सेवाओं के लिए दृष्टिकोण उत्साहजनक बना हुआ है, और ऐतिहासिक औसत से ऊपर है। क्रॉस-कंट्री तुलना से पता चलता है कि भारत में प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक पीएमआई रीडिंग थी (चार्ट 31 सी)।

विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता उपयोग 2022-23 की दूसरी तिमाही में अपने दीर्घकालिक औसत को पार कर गया। विनिर्माताओं को बाद की तिमाहियों में और सुधार की उम्मीद है। विनिर्माण, बुनियादी ढांचा और सेवा क्षेत्रों की कंपनियों ने 2023-24 की



पहली छमाही तक मांग की स्थिति को लेकर बहुत अधिक आशावाद दिखाया है, जैसा कि रिजर्व बैंक के दृष्टिकोण सर्वेक्षण (अनुबंध 1) में परिलक्षित होता है।

सेवा क्षेत्र में, परिवहन संकेतकों में विस्तार दर्ज किया गया, जिसमें रेलवे माल ढुलाई आय जनवरी 2023 में महीने-दर-महीने (एम-ओ-एम) और साल-दर-साल आधार पर बढ़ी, जो भारतीय रेलवे की हंगर फॉर कार्गो पहल द्वारा समर्थित है (चार्ट 32 ए)। कोकिंग कोल और कंटेनराइज्ड कार्गो के पोतभार में वृद्धि के कारण जनवरी में प्रमुख बंदरगाहों पर कार्गो यातायात में तेजी आई (चार्ट 32 बी)।

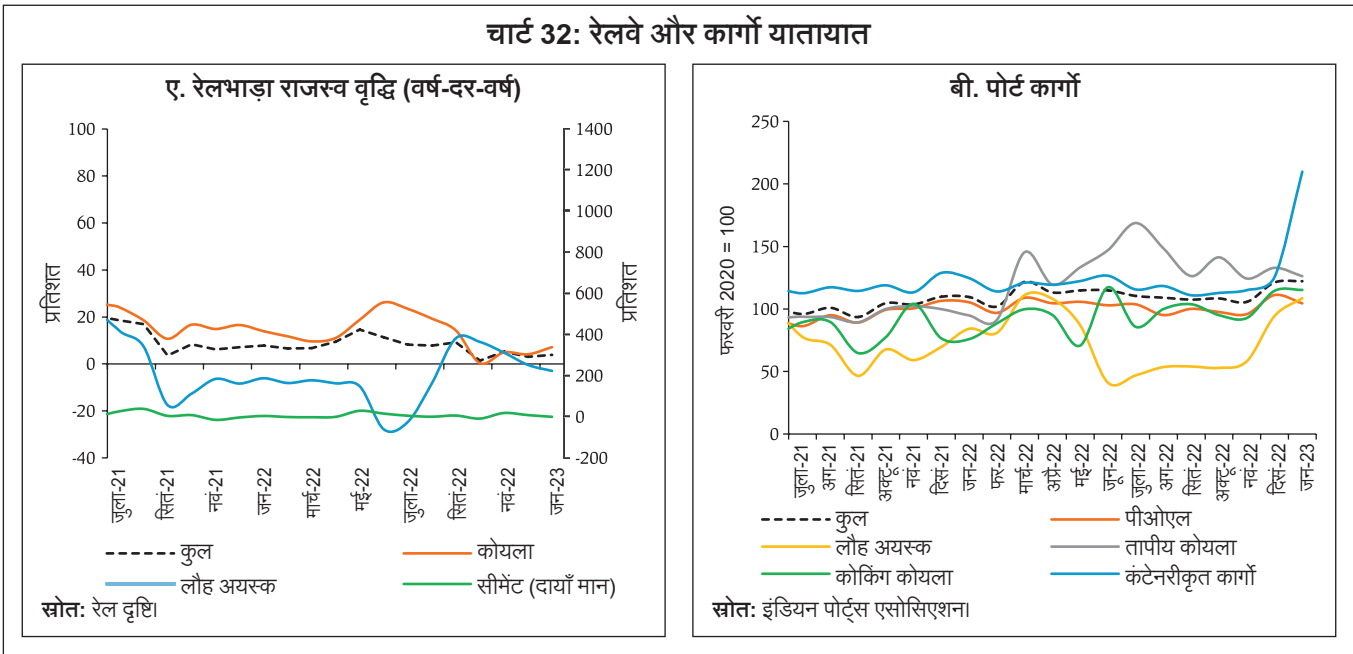
निर्माण क्षेत्र में इस्पात की खपत जनवरी 2023 में सालाना आधार पर 2.7 प्रतिशत बढ़ी जबकि एक साल पहले इसी महीने

में इसमें 0.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। सीमेंट उत्पादन में वृद्धि एक उच्च आधार पर कम हो गई (चार्ट 33)।

सेवा क्षेत्र में उच्च आवृत्ति संकेतक अंतरराष्ट्रीय यात्री आंदोलन और हवाई कार्गो यातायात को छोड़कर आम तौर पर सकारात्मक गति जारी रहने की ओर इशारा करते हैं (सारणी 2)।

राज्य स्तर पर प्रमुख नीतिगत पहलों के संदर्भ में, तमिलनाडु ने तमिलनाडु इमर्जिंग सेक्टर सीड फंड (टीएनईएसएफ) शुरू किया है जिसका उद्देश्य उभरते/सनराइज क्षेत्रों में स्टार्ट-अप के लिए निवेश प्रदान करना है। पश्चिम बंगाल ने कपड़ा क्षेत्र को विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने वाली एक योजना शुरू की। ओडिशा ने ओडिशा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन (ओपीजीसी)

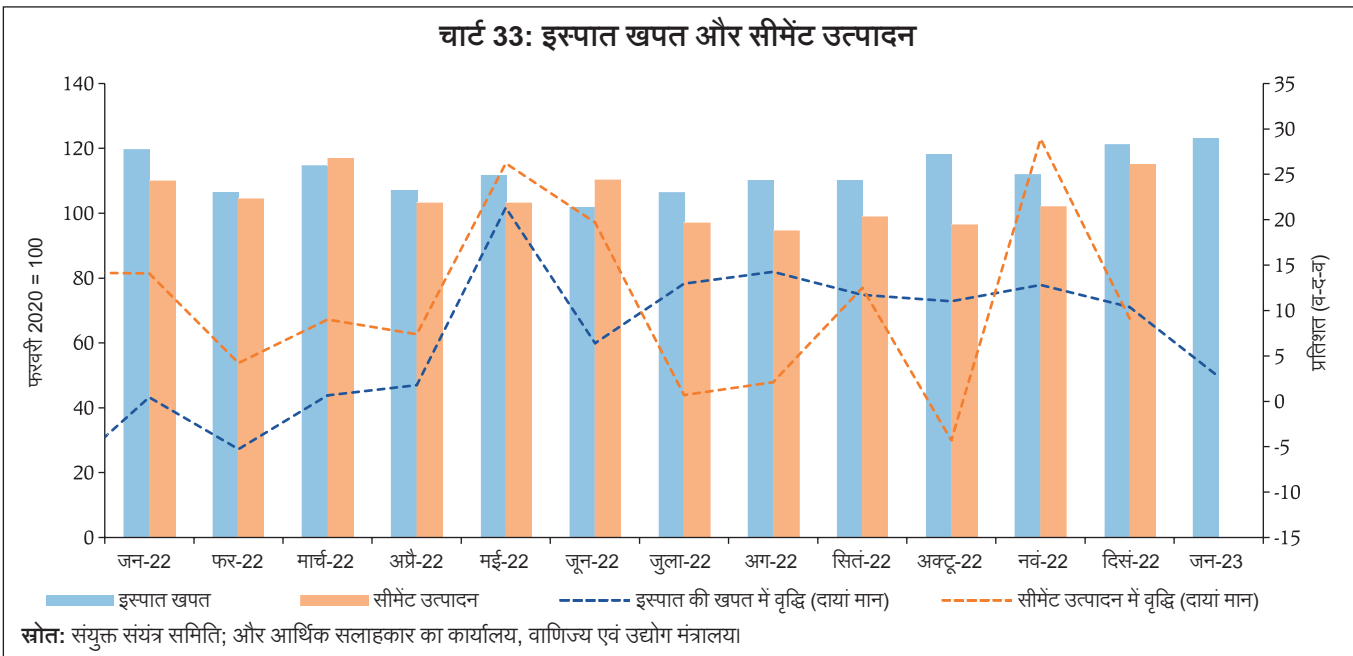
चार्ट 32: रेलवे और कार्गो यातायात



में अपनी 49 प्रतिशत हिस्सेदारी के विनिवेश के लिए एक वैश्विक निविदा जारी की। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में निजी औद्योगिक

पार्क के विकास की सुविधा के लिए एक नई योजना को मंजूरी दे दी है।

चार्ट 33: इस्पात खपत और सीमेंट उत्पादन



सारणी 2: उच्च आवृत्ति संकेतक – सेवाएं

सेवाओं में वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)

क्षेत्र	संकेतक	अक्टू-22	नव-22	दिसं-22	जन-23
शहरी मांग	यात्री वाहन बिक्री	28.6	28.1	7.2	17.2
	दुपहिया वाहन बिक्री	2.3	16.5	3.9	5.0
ग्रामीण मांग	तिपहिया वाहन बिक्री	70.4	103.2	37.6	103.0
	ट्रैक्टर बिक्री	6.8	6.5	25.6	24.4
	वाणिज्यिक वाहन बिक्री	16.6			
व्यापार, होटल, परिवहन, संचार	रेलवे माल ढुलाई यातायात	1.4	5.2	3.1	3.8
	पोर्ट कार्गो यातायात	3.1	1.8	10.3	
	घरेलू हवाई कार्गो यातायात	-8.3	3.7	-3.6	
	अंतरराष्ट्रीय हवाई कार्गो यातायात	-18.7	-6.0	-7.4	
	घरेलू हवाई यात्री यातायात	30.4	12.6	14.6	
	अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात	115.0	97.5	85.9	
	जीएसटी ई-वे बिल (कुल)	4.6	32.0	17.5	19.7
	जीएसटी ई-वे बिल (अंतरराज्यीय)	12.0	37.7	23.2	24.1
	जीएसटी ई-वे बिल (अंतर-राज्यीय)	-5.9	23.1	8.6	12.8
	पर्यटक आगमन	243.2	191.3	204.2	
निर्माण	इस्पात खपत	11.0	12.8	10.3	2.7
	सीमेंट उत्पादन	-4.3	28.9	9.1	
पीएमआई सूचकांक	सेवाएं	55.1	56.4	58.5	57.2

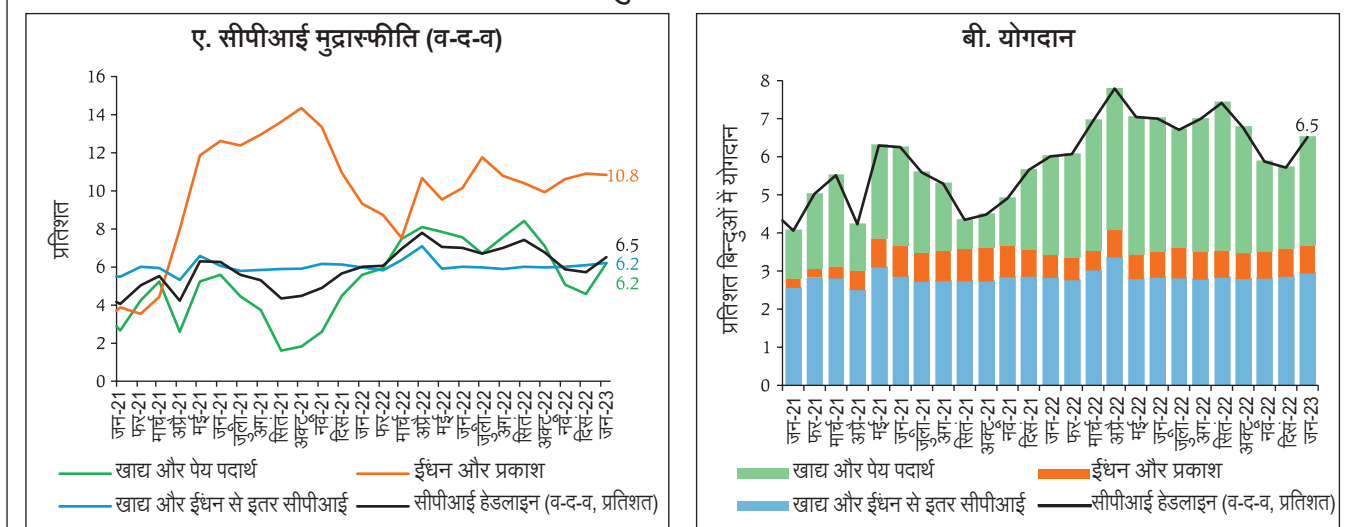
स्रोत: सीएमआईई; सीईआईसी आंकड़े; आईएचएस मार्किट; एसआईएएम; भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण; और संयुक्त प्लान्ट समिति।

मुद्रास्फीति

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार मुद्रास्फीति – जैसा कि अखिल भारतीय

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में साल-दर-साल परिवर्तनों द्वारा मापा जाता है – दिसंबर 2022 में 5.7 प्रतिशत से बढ़कर जनवरी 2023 में 6.5 प्रतिशत हो गया (चार्ट 34 ए)। सूचकांक में 46 बीपीएस की वृद्धि हुई, जिसके साथ-साथ प्रतिकूल आधार

चार्ट 34: सीपीआई मुद्रास्फीति के रुझान और वाहक



टिप्पणी: अप्रैल-मई 2021 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति की गणना, अप्रैल-मई 2020 के लिए अनुमानित सीपीआई सूचकांकों के आधार पर की गई थी।

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ); और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

प्रभाव (एक साल पहले कीमतों में एम-ओ-एम परिवर्तन) 30 बीपीएस के साथ, जिसके परिणामस्वरूप दिसंबर और जनवरी के बीच हेडलाइन मुद्रास्फीति में लगभग 80 बीपीएस की वृद्धि हुई।

मूल्य दबाव मुख्य रूप से खाद्य और पेय समूह (45 बीपीएस) और 'कोर' (खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई) समूह (52 बीपीएस) में एम-ओ-एम वृद्धि से उत्पन्न होता है। हालांकि ईंधन समूह का सूचकांक संबंधित महीने में अपरिवर्तित रहा।

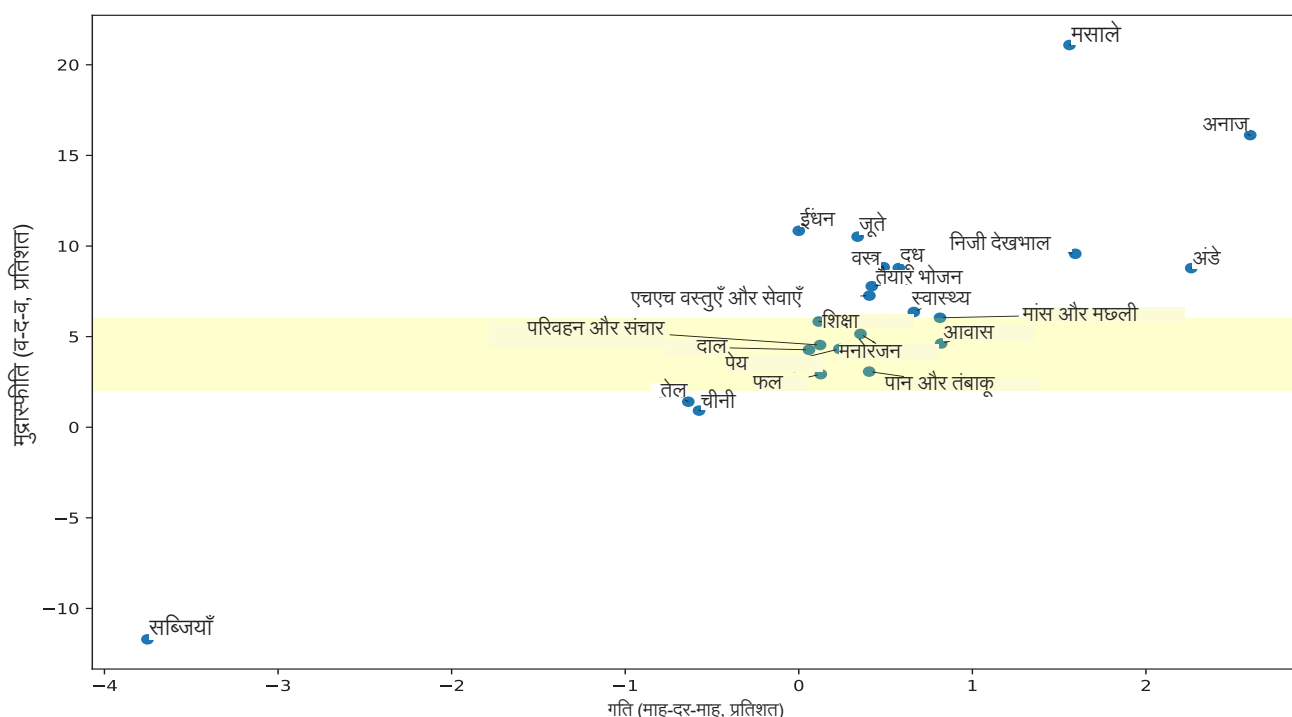
उपरोक्त मूल्य सूचकांक आधारित खाद्य मुद्रास्फीति जनवरी में तेजी से बढ़कर 6.2 प्रतिशत हो गई, जो एक महीने पहले 4.6 प्रतिशत थी (चार्ट 34बी)। खाद्य समूह के भीतर, अनाज में मुद्रास्फीति काफी बढ़कर 16.1 प्रतिशत - जून 2013 के बाद से सबसे अधिक - और मसालों में, 21.1 प्रतिशत - वर्तमान सीपीआई श्रृंखला में सबसे अधिक हो गई (चार्ट 35)। फल, खाद्य तेल, चीनी, प्रोटीन आधारित खाद्य (दालें, अंडे, मांस, मछली और दूध) और गैर-मादक पेय जैसे अन्य उप-समूहों ने महीने के दौरान मुद्रास्फीति में वृद्धि दर्ज की। सब्जियों ने

दिसंबर 2022 की तुलना में जनवरी 2023 में कम अपस्फीति दर्ज की (चार्ट 36)।

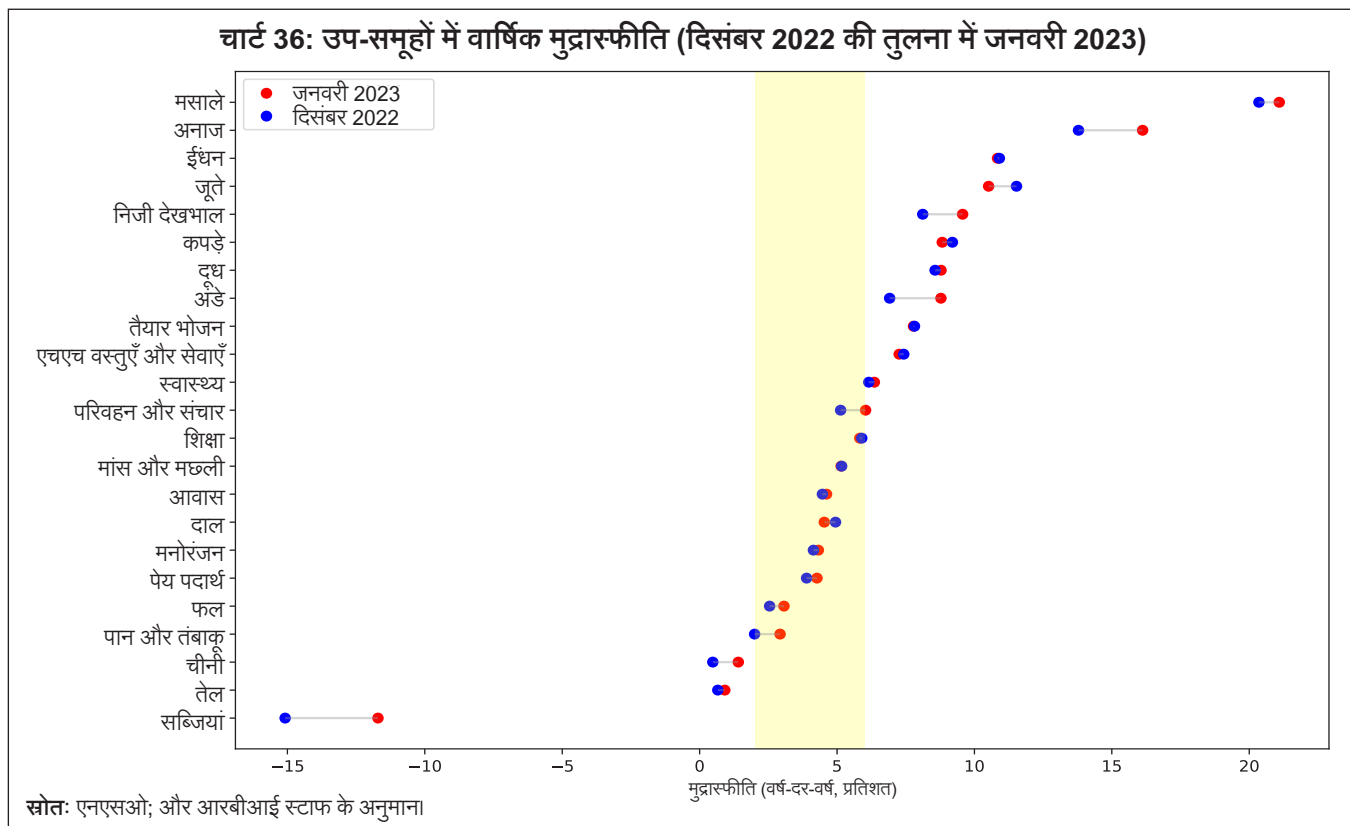
ईंधन और बिजली समूह की मुद्रास्फीति जनवरी में मामूली रूप से कमी आकर वह 10.8 प्रतिशत रही जो दिसंबर में 10.9 प्रतिशत थी। केरोसीन-पीडीएस और बिजली की मुद्रास्फीति में कुछ कमी दर्ज की गई, जबकि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) ने एक महीने पहले की तुलना में मूल्य वृद्धि का उच्च स्तर दर्ज किया। सीपीआई बास्केट में 6.8 प्रतिशत के भारांश वाले ईंधन समूह ने जनवरी में हेडलाइन मुद्रास्फीति में 11.3 प्रतिशत का योगदान दिया।

उपरोक्त मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति जनवरी में बढ़कर 6.2 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो दिसंबर में 6.1 प्रतिशत थी। दूसरी ओर कपड़े और जूते-चप्पल, घरेलू सामान एवं सेवाएं, परिवहन एवं संचार तथा शिक्षा उप-समूहों में जनवरी में मुद्रास्फीति में नरमी देखी गई।

चार्ट 35: वार्षिक मुद्रास्फीति (व-द-व) और उप-समूहों में गति (माह-दर-माह)



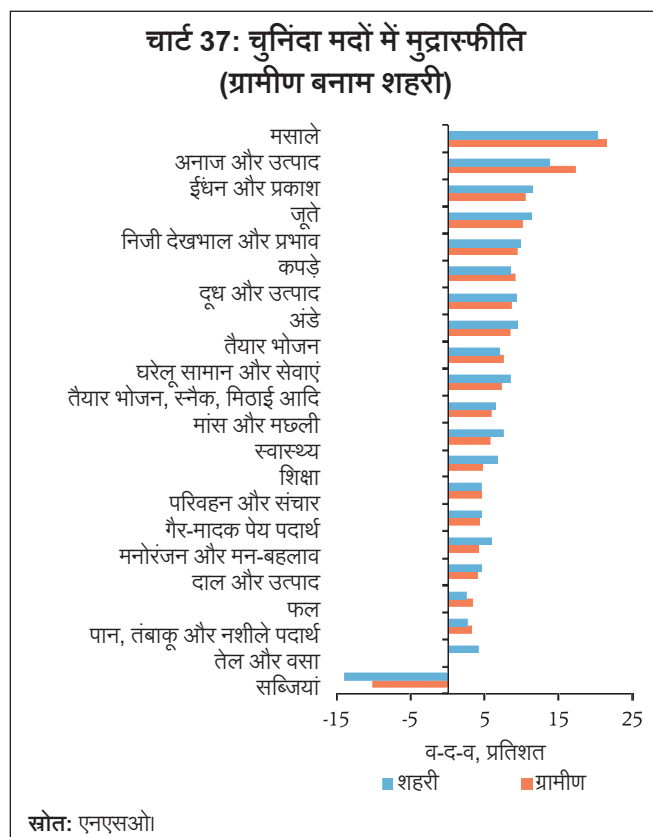
स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।



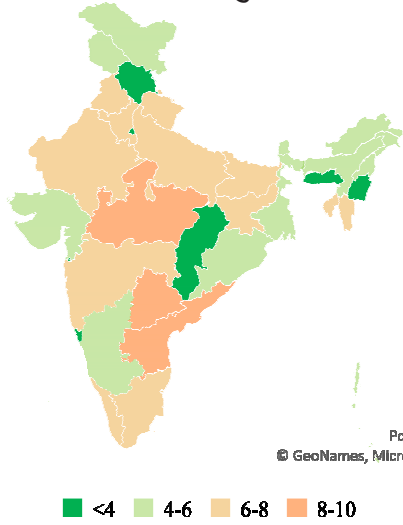
जनवरी 2023 में ग्रामीण मुद्रास्फीति 6.85 प्रतिशत रही जो शहरी मुद्रास्फीति (6.00 प्रतिशत) से अधिक है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज, फल, कपड़े की मुद्रास्फीति अधिक थी, दूध, अंडे, मांस और ईंधन और प्रकाश में शहरी केंद्रों में उच्च मुद्रास्फीति दर्ज की गई (चार्ट 37)।

राज्यों में, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना ने 8 प्रतिशत से अधिक मुद्रास्फीति का अनुभव किया, जबकि छत्तीसगढ़, दमन और दीव, दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय ने मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत से नीचे दर्ज की (चार्ट 38)।

फरवरी 2023 (13 फरवरी तक) के लिए खाद्य कीमतों पर उच्च आवृत्ति डेटा से पता चलता है कि चावल और गेहूँ के लिए कीमतों में वृद्धि जारी रही। मूंग को छोड़कर दालों की कीमतों में गिरावट आई है। खाद्य तेल और सब्जियों की कीमतों में फरवरी में गिरावट जारी रही (चार्ट 39)।



चार्ट 38: जनवरी 2023 में मुद्रास्फीति का स्थानिक वितरण (सीपीआई- संयुक्त, वर्ष-दर-वर्ष)



स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

सारणी 3: पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें

मदें	इकाई	घरेलू कीमतें			माह की तुलना (प्रतिशत)	
		फर-22	जन-23	फर-23 [^]	जन-23	फर-23
पेट्रोल	₹/लीटर	102.87	102.92	102.92	0.0	0.0
डीजल	₹/लीटर	90.51	92.72	92.72	0.0	0.0
केरोसिन (सहायकी सहित)	₹/लीटर	42.11	53.67	55.79	-9.0	4.0
एलपीजी (सहायकी रहित)	₹/सिलेंडर	910.13	1063.25	1063.25	0.0	0.0

[^]: 1-13 फरवरी 2023 की अवधि के लिए।

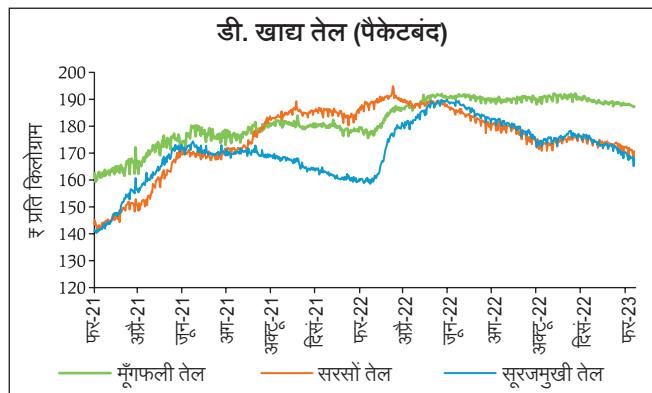
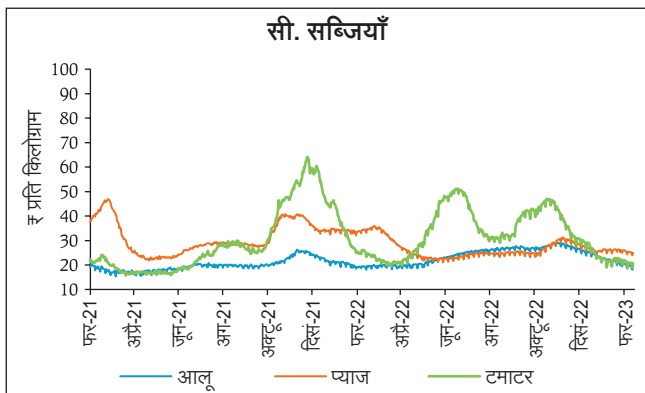
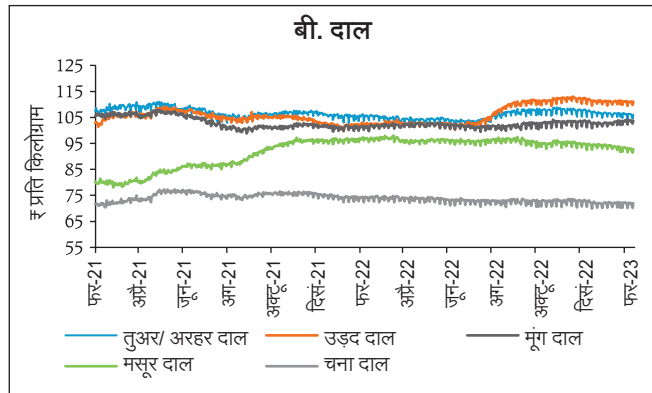
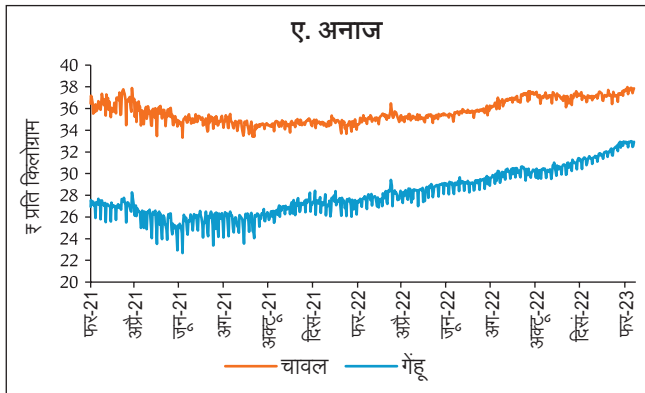
टिप्पणी: मिट्टी के तेल के अलावा, कीमतें चार प्रमुख महानगरों (दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई) में औसत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की कीमतों का प्रतिनिधित्व करती हैं। मिट्टी के तेल के लिए कीमतें, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में रियायती कीमतों के औसत को दर्शाती हैं।

स्रोत: इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल); पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी); तथा आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

चार प्रमुख महानगरों में पेट्रोल और डीजल की खुदरा बिक्री कीमतें फरवरी में अब तक स्थिर रही हैं। जबकि एलपीजी की

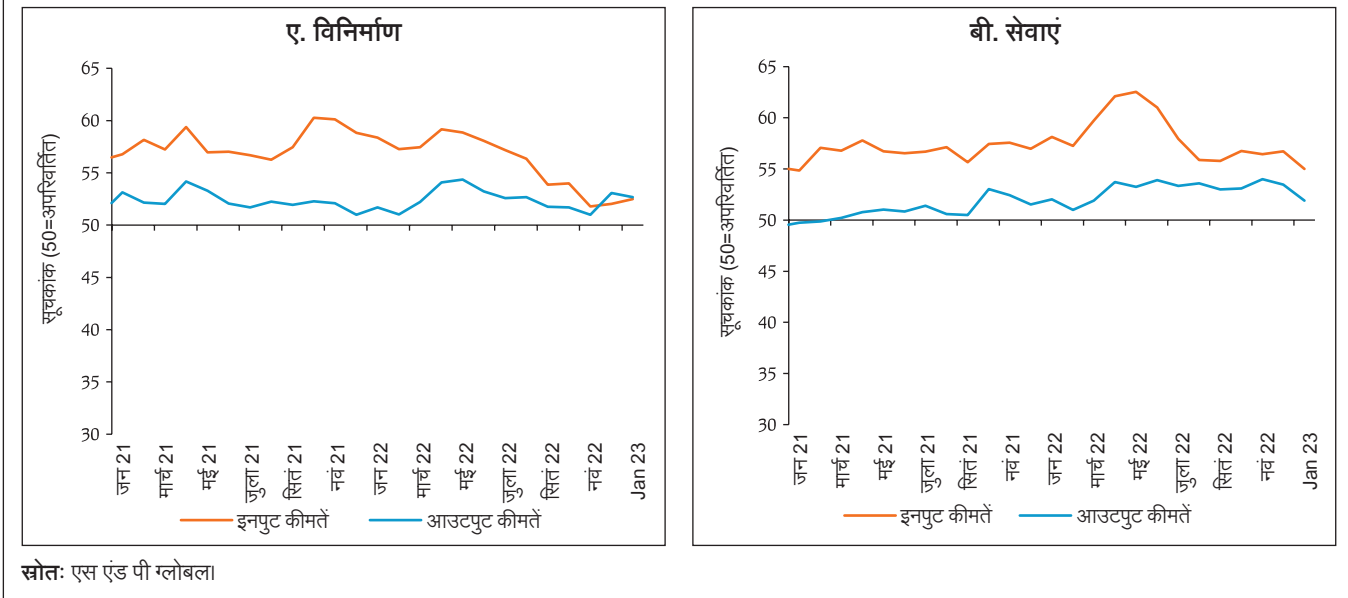
कीमतों को अपरिवर्तित रखा गया था, जनवरी में तेजी से गिरावट के बाद मिट्टी के तेल की कीमतों में वृद्धि हुई (सारणी 3)।

चार्ट 39: डीसीए आवश्यक वस्तुओं की कीमतें



स्रोत : उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

चार्ट 40: पीएमआई: इनपुट और आउटपुट कीमतें



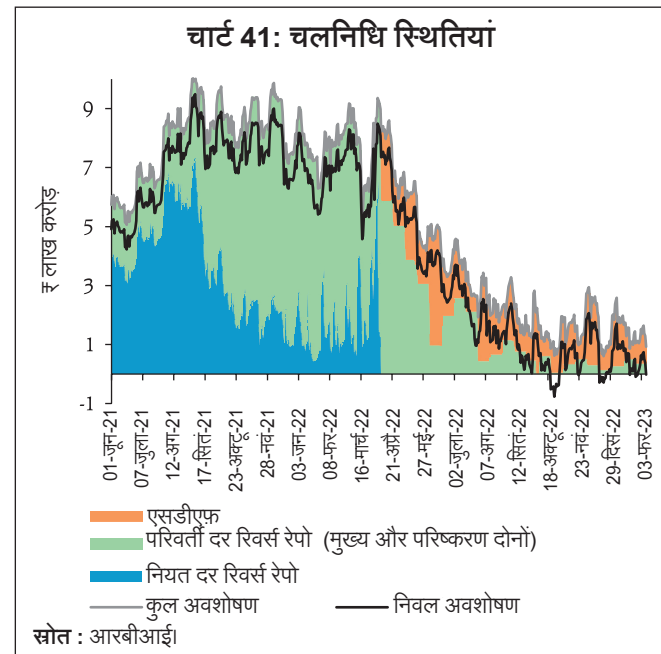
इनपुट लागत और बिक्री मूल्य, जैसा कि पीएमआई में परिलक्षित होता है, विनिर्माण और सेवाओं दोनों के लिए विस्तारवादी मोड में रहा (चार्ट 40), बाद में वृद्धि की गति में क्रमिक कमी देखी गई।

4. वित्तीय स्थिति

जनवरी 2023 की दूसरी छमाही में जीएसटी संग्रह¹⁶ के कारण बहिर्वाह की वजह से अधिशेष चलनिधि कम हो गई, लेकिन फरवरी की शुरुआत में सरकारी खर्च ने प्रणाली चलनिधि को फिर से बढ़ा दिया। कुल मिलाकर, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत औसत दैनिक अवशोषण 16 जनवरी से 8 फरवरी, 2023 के दौरान 1.3 लाख करोड़ रुपये तक कम हो गया, जो दिसंबर के मध्य से 15 जनवरी, 2023 के दौरान 1.5 लाख करोड़ रुपये था (चार्ट 41)। इस अवधि के दौरान दैनिक औसत अधिशेष चलनिधि में से 0.4 लाख करोड़ रुपये रात्रिकालीन स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) के माध्यम से अवशोषित किए गए थे, जबकि शेष को परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) नीलामी के माध्यम से जुटाया गया था।

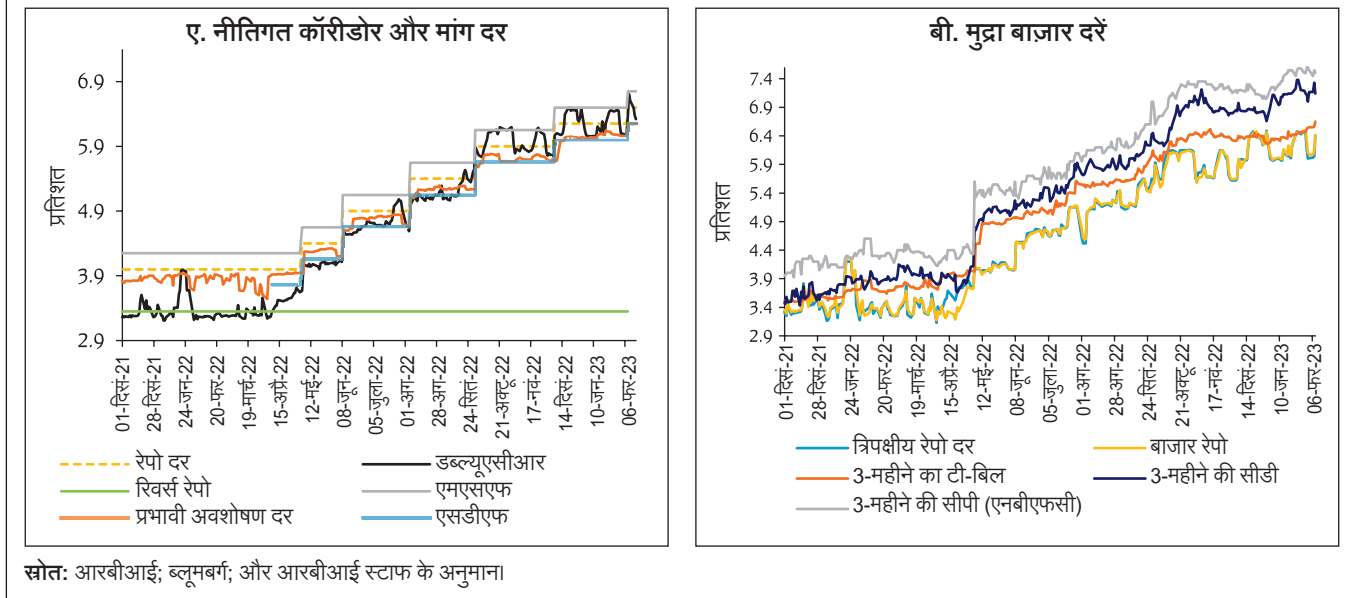
अधिशेष चलनिधि में गिरावट ने कुछ बैंकों को सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया, जो इसी अवधि के दौरान औसतन ₹ 0.06 लाख करोड़ था। एसडीएफ के तहत अधिशेष निधियों के बड़े पैमाने पर जमावट की पृष्ठभूमि में बैंकों द्वारा एमएसएफ का सहारा लेना प्रणाली में विषम चलनिधि

चार्ट 41: चलनिधि स्थितियां



¹⁶ जनवरी 2023 का मासिक जीएसटी संग्रह 1.56 लाख करोड़ रुपये था, जो अप्रैल 2022 में 1.68 लाख करोड़ रुपये के बाद दूसरा सबसे अधिक संग्रह था।

चार्ट 42: नीतिगत कॉरिडोर और मुद्रा बाजार दरें



वितरण को दर्शाता है। निवल आधार पर (रेपो और एमएसएफ के माध्यम से अंतःक्षेपण के लिए समायोजित) समीक्षाधीन अवधि में औसत अवशोषण घटकर 0.34 लाख करोड़ रुपये रह गया, जो पिछली अवधि में 0.51 लाख करोड़ रुपये था। पाक्षिक वीआरआरआर नीलामी के तहत रखी गई राशि भी 27 जनवरी, 2023 से शुरू होने वाले पखवाड़े के लिए 0.35 लाख करोड़ रुपये (पिछली नीलामी के दौरान 0.52 लाख करोड़ रुपये) से कम थी।

अधिशेष चलनिधि की स्थिति में कमी और दीर्घकालिक रेपो परिचालन की आगामी परिपक्वता के बीच, रिजर्व बैंक ने संशोधित चलनिधि ढांचे के तहत पहली बार 10 फरवरी, 2023 को 14-दिवसीय परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) संचालन किया, जिसके लिए 0.50 लाख करोड़ रुपये की अधिसूचित राशि के सामने 1.34 लाख करोड़ रुपये की बोली प्राप्त हुई। केंद्रीय बजट 2023-24 में प्रस्तुत 2022-23 के संशोधित अनुमानों से स्पष्ट सरकारी खर्च में संभावित वृद्धि से फरवरी-मार्च के दौरान संचालन में मुद्रा में सामान्य विस्तार और मार्च-अप्रैल 2023 के दौरान एलटीआरओ और टीएलटीआरओ (आंशिक रूप से) की परिपक्वता से अपेक्षित चलनिधि निकासी की भरपाई करने में मदद मिलेगी।¹⁷

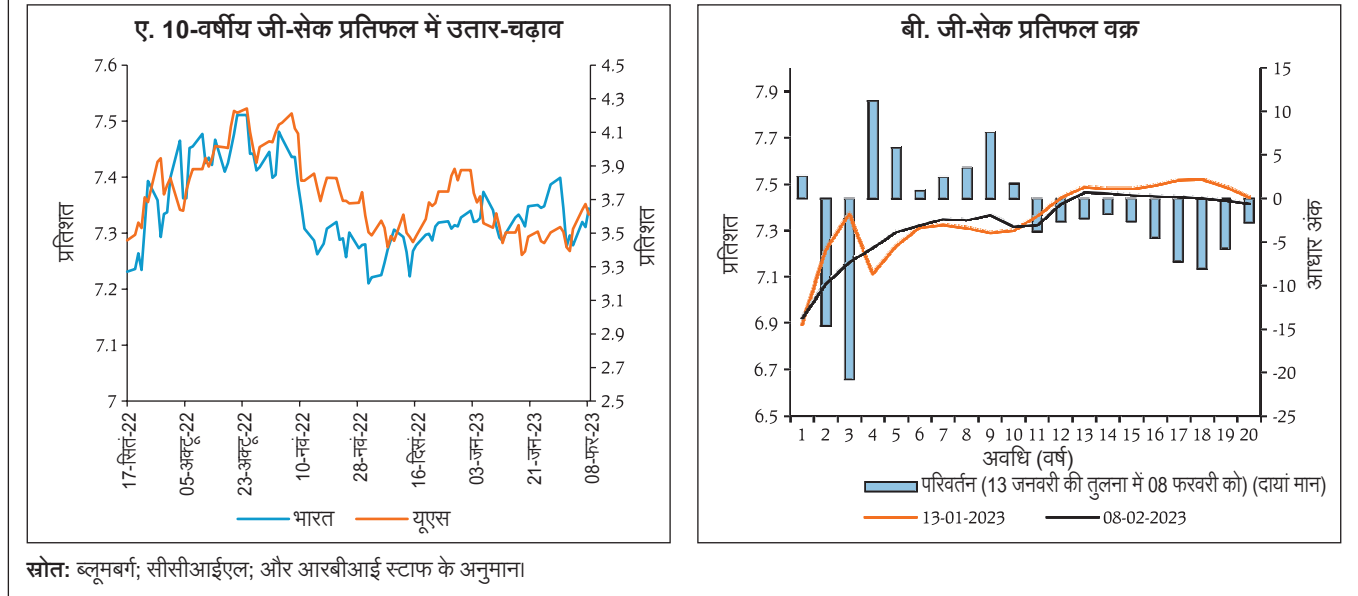
¹⁷ 13,517 करोड़ रुपये फरवरी-मार्च 2023 में परिपक्व होंगे और 61,131 करोड़ रुपये अप्रैल 2023 में परिपक्व होंगे।

भारत औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर) ने जनवरी 2023 के अंत में एलएएफ कॉरिडोर की ऊपरी सीमा को कुछ समय के लिए छुआ, लेकिन बाद में उसमें कमी आई। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, डब्ल्यूएसीआर का औसत 6.28 प्रतिशत था, जो नीतिगत रेपो दर के करीब (औसतन) कारोबार कर रहा था (चार्ट 42 ए)। मांग बाजार में गतिविधियों में तेजी आई और 16 जनवरी से 8 फरवरी, 2023 के दौरान औसत दैनिक मात्रा 14,420 करोड़ रुपये रही, जो 13 दिसंबर, 2022 से 15 जनवरी, 2023 के दौरान 11,343 करोड़ रुपये थी।

इसके साथ ही, संपार्श्विक खंड में दरें भी मजबूत हुईं - जबकि त्रिपक्षीय रेपो दर नीति रेपो दर से 4 बीपीएस नीचे कारोबार करती है, बाजार रेपो दरें नीति रेपो दर के करीब कारोबार करती हैं। मियादी मुद्रा खंड में, 3 महीने के खजाना बिल (टी-बिल) पर दर एमएसएफ दर से 7 बीपीएस नीचे कारोबार करती है, जबकि एनबीएफसी के लिए जमा प्रमाणपत्र (सीडी) और वाणिज्यिक पत्र (सीपी) के लिए 3 महीने की दरें एमएसएफ दर से ऊपर क्रमशः 67 बीपीएस और 102 बीपीएस थीं (चार्ट 42 बी)।

वर्ष के दौरान अब तक (13 जनवरी तक) प्राथमिक बाजार में सीडी निर्गम के जरिये 5.2 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रहा जो पिछले साल की संबंधित अवधि के 1.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक है जो बैंकों की बढ़ते ऋण उठाव के कारण धन

चार्ट 43: जी-सेक बाजार में घटनाक्रम



की अतिरिक्त मांग को दर्शाता है। सीपी निर्गम वर्ष के दौरान अब तक (15 जनवरी तक) घटकर 10.9 लाख करोड़ रुपये रह गया, जो पिछले साल की संबंधित अवधि में 17.2 लाख करोड़ रुपये था, बैंक ऋण की सहायता से धन जुटाने के पसंदीदा साधन के रूप में उभर रहा है। मुद्रा बाजार में औसत जोखिम प्रीमियम (3 महीने का सीपी माइनस 91-दिन ट्रेजरी बिल) इस अवधि के दौरान 110 बीपीएस पर ऊंचा रहा, जो अधिशेष चलनिधि में कमी को दर्शाता है।

केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय समेकन की प्रतिबद्धता और अनुमानित सकल बाजार उधारी से कम की घोषणा के जवाब में 10-वर्षीय बेंचमार्क जी-सेक यील्ड में कमी आई (चार्ट 43 ए)। कारोबार के दौरान 7.40 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद बजट घोषणा के दिन यानी एक फरवरी, 2023 को कारोबारी सत्र के अंत तक बेंचमार्क प्रतिफल घटकर 7.28 प्रतिशत पर आ गया। इसके बाद जी-सेक यील्ड ने अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड के साथ मिलकर सख्त पूर्वाग्रह का प्रदर्शन किया और 7.34 फीसदी पर बंद हुआ। इस मियादी संरचना में, जी-सेक प्रतिफल में उपज वक्र के छोटे छोर पर तेजी से नरमी आई, जो आगे चलकर कम दर वृद्धि की उम्मीदों का संकेत है (चार्ट 43 बी)।

कॉर्पोरेट बॉन्ड प्रतिफल और स्प्रेड रेटिंग श्रेणियों में कठोर हो गया है, विशेष रूप से 3-5 साल की परिपक्वता के लिए जहां निर्गम ज्यादातर केंद्रित होते हैं (सारणी 4)। कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी करने के जरिये जुटाया गया धन दिसंबर में बढ़कर 1.37 लाख

सारणी 4: वित्तीय बाजार - दरें और स्प्रेड

लिखत	ब्याज दर (प्रतिशत)			स्प्रेड (आधार अंक) (तदनुसारी जोखिम-मुक्त दर की तुलना में)		
	13 दिसं 2022-15 जन 2023	16 जन 2023-07 फर 2023	उतार-चढ़ाव (आधार अंकों में)	13 दिसं 2022-15 जन 2023	16 जन 2023-07 फर 2023	उतार-चढ़ाव (आधार अंकों में)
1	2	3	(4 = 3-2)	5	6	(7 = 6-5)
कॉर्पोरेट बॉण्ड						
(i) एएए (1-वर्ष)	7.87	7.87	0	91	88	-3
(ii) एएए (3- वर्ष)	7.77	7.79	2	59	62	3
(iii) एएए (5- वर्ष)	7.76	7.86	10	40	52	12
(iv) एए (3- वर्ष)	8.49	8.49	0	130	132	2
(v) बीबीबी- (3- वर्ष)	12.14	12.13	-1	496	497	1

टिप्पणी: प्रतिफल और स्प्रेड की गणना मासिक औसत के रूप में की जाती है।

स्रोत: एफआईएमएमडीए; और ब्लूमबर्ग।

करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो नवंबर, 2022 में 0.77 लाख करोड़ रुपये था। बॉन्ड बाजार में औसत जोखिम प्रीमियम (5 साल एए माइनस 5 साल जी-सेक) 16 जनवरी से 8 फरवरी, 2023 के दौरान 52 बीपीएस तक बढ़ गया, जो 13 दिसंबर, 2022 से 15 जनवरी, 2023 के दौरान 40 बीपीएस था।

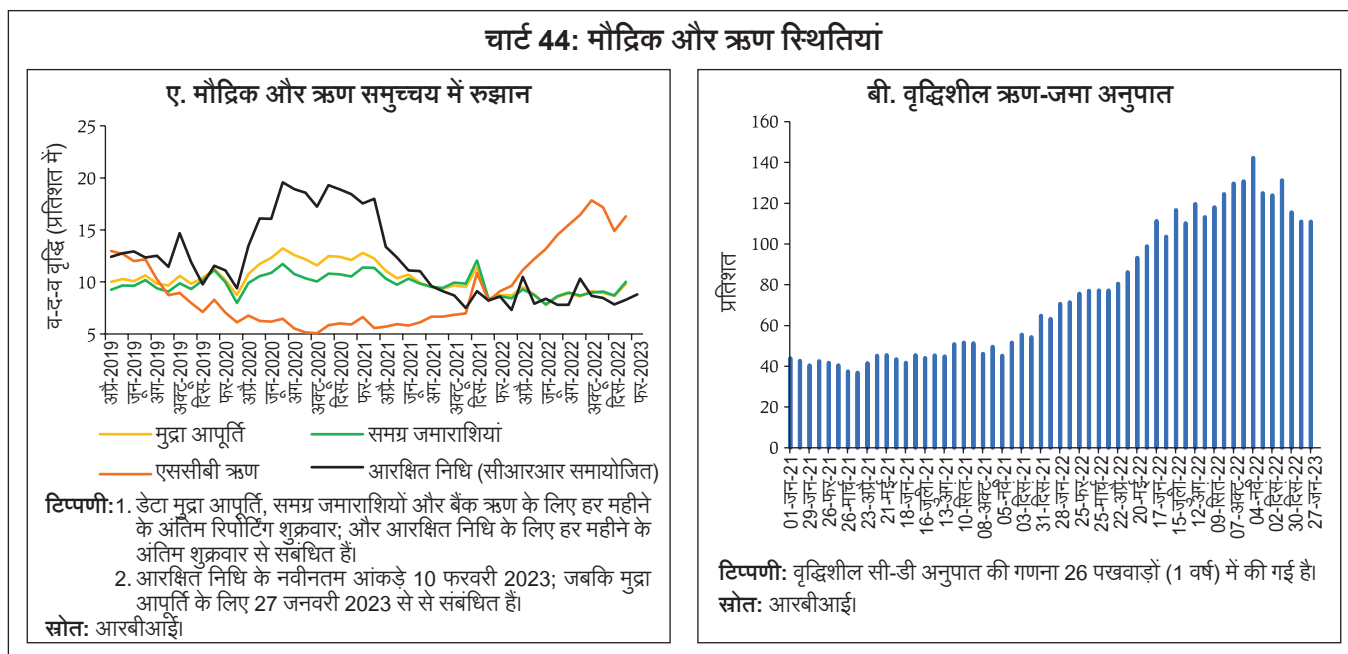
नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में परिवर्तन के पहले दौर के प्रभाव को छोड़कर आरक्षित धन (आरएम) 10 फरवरी, 2023 को 8.8 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) (एक साल पहले 7.7 प्रतिशत) बढ़ा [चार्ट 44 ए]। आरएम के सबसे बड़े घटक संचलन में मुद्रा (सीआईसी) में 8.15 फीसदी (पिछले साल 8.2 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। मुद्रा आपूर्ति (एम3) में 27 जनवरी, 2023 को 9.8 प्रतिशत (पिछले साल 8.4 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से बैंकों के साथ इसके सबसे बड़े घटक - कुल जमा - से प्रेरित थी, जिसमें 10.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की ऋण वृद्धि 27 जनवरी, 2023 को 16.3 प्रतिशत (पिछले साल 8.2 प्रतिशत) पर बनी रही। जमा संग्रहण में तेजी के साथ, दिसंबर 2022 के मध्य से वृद्धिशील सी-डी अनुपात में कमी आई है (चार्ट 44 बी)।

बैंकों ने मई 2022 से जनवरी 2023 के दौरान अपनी बाहरी बेंचमार्क-आधारित उधार दरों (ईबीएलआर) को 225 बीपीएस के

परिमाण तक संशोधित किया है। एससीबी की 1 साल की औसत सीमांत लागत आधारित ऋण दर (एमसीएलआर) में 120 बीपीएस की वृद्धि हुई है। नतीजतन, एससीबी के नए और बकाया रुपये के ऋणों पर भारत औसत उधार दरें (डब्ल्यूएलआर) मई-दिसंबर 2022 के दौरान क्रमशः 137 बीपीएस और 80 बीपीएस तक बढ़ गईं। इसी अवधि के दौरान अनुसूचित बैंकों की बकाया जमा राशियों पर भारत औसत घरेलू मीयादी जमा दर (डब्ल्यूएडीटीडीआर) में 75 आधार अंकों की वृद्धि हुई (सारणी 5)।

भारत सरकार ने 30 दिसंबर, 2022 को 2022-23 की चौथी तिमाही के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं की दरों को 20 से 110 बीपीएस की सीमा में संशोधित किया, जिसमें सावधि जमा में सबसे अधिक वृद्धि हुई (चार्ट 45)। 3 साल तक की अवधि की पोस्ट ऑफिस सावधि जमा पर ब्याज दरें अब फॉर्मूला-आधारित दरों के साथ निकटता से संरेखित हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 में एक नई योजना, यानी महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र की घोषणा की गई थी, जो महिला जमाकर्ताओं के लिए 7.5 प्रतिशत की निश्चित ब्याज दर पर 2 साल की अवधि के लिए 2 लाख रुपये तक की जमा सुविधा प्रदान करेगी। बैंकों द्वारा दी जाने वाली सावधि जमा दरें सामान्य रूप से, 3 साल तक की परिपक्वता अवधि के लिए समान परिपक्वता वाली छोटी बचत जमाओं की तुलना में कम हैं।

चार्ट 44: मौद्रिक और ऋण स्थितियां



सारणी 5: बैंकों की जमा और उधार दरों में संचरण

(आधार अंकों में भिन्नता)

अवधि	रेपो दर (आधार अंक)	मीयादी जमा दरें (आधार अंक)		उधार दरें (आधार अंक)		
		माध्यिका अवधि जमाराशि दरें (कार्ड दर)	डब्ल्यूएडीटीडी- आर - बकाया जमाराशियां	1-वर्षीय एमसीएलआर (माध्यिका)	डब्ल्यूएलआर - नया रुपया ऋण	डब्ल्यूएलआर - बकाया रुपया ऋण
सहजता का दौर फरवरी 2019 से मार्च 2022	-250	-208	-188	-155	-232	-150
सख्ती का दौर मई 2022 से जनवरी 2023*	+225	78	75	120	137	80

टिप्पणी: *: डब्ल्यूएलआर और डब्ल्यूएडीटीडीआर पर अद्यतन डेटा दिसंबर 2022 से संबंधित है;

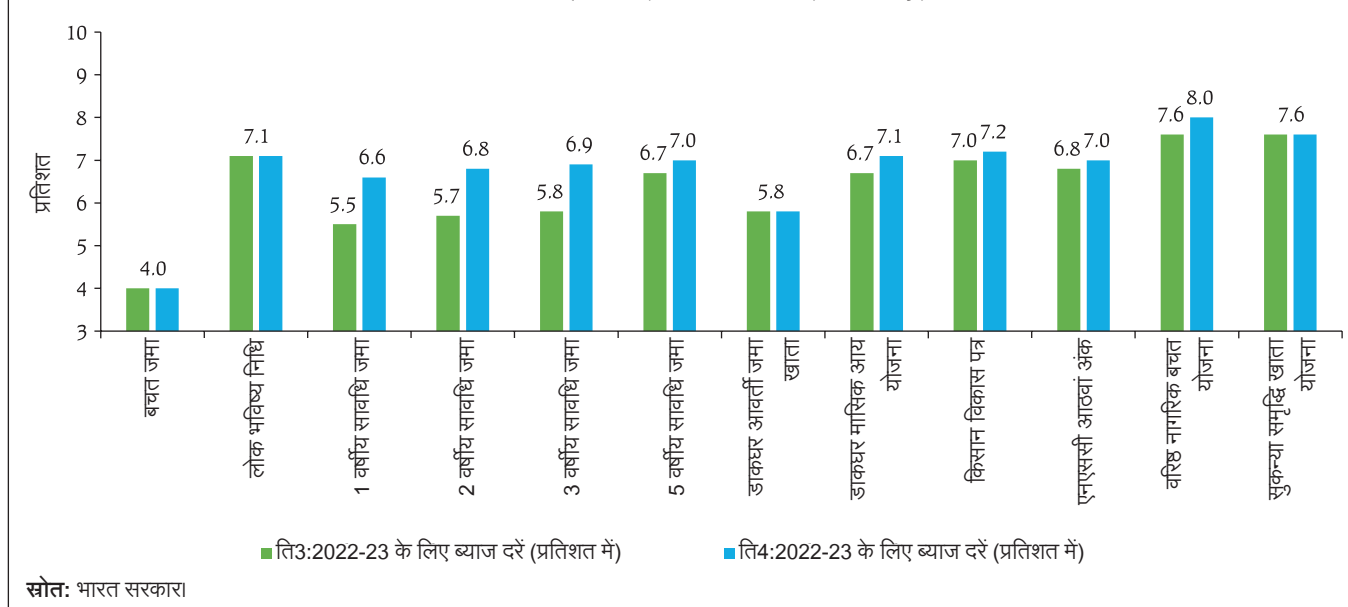
2. डब्ल्यूएलआर: भारत औसत उधार दर; डब्ल्यूएडीटीडीआर: भारत औसत घरेलू मीयादी जमा दर; एमसीएलआर: निधि-आधारित उधार दर की सीमांत लागत

स्रोत: आरबीआई।

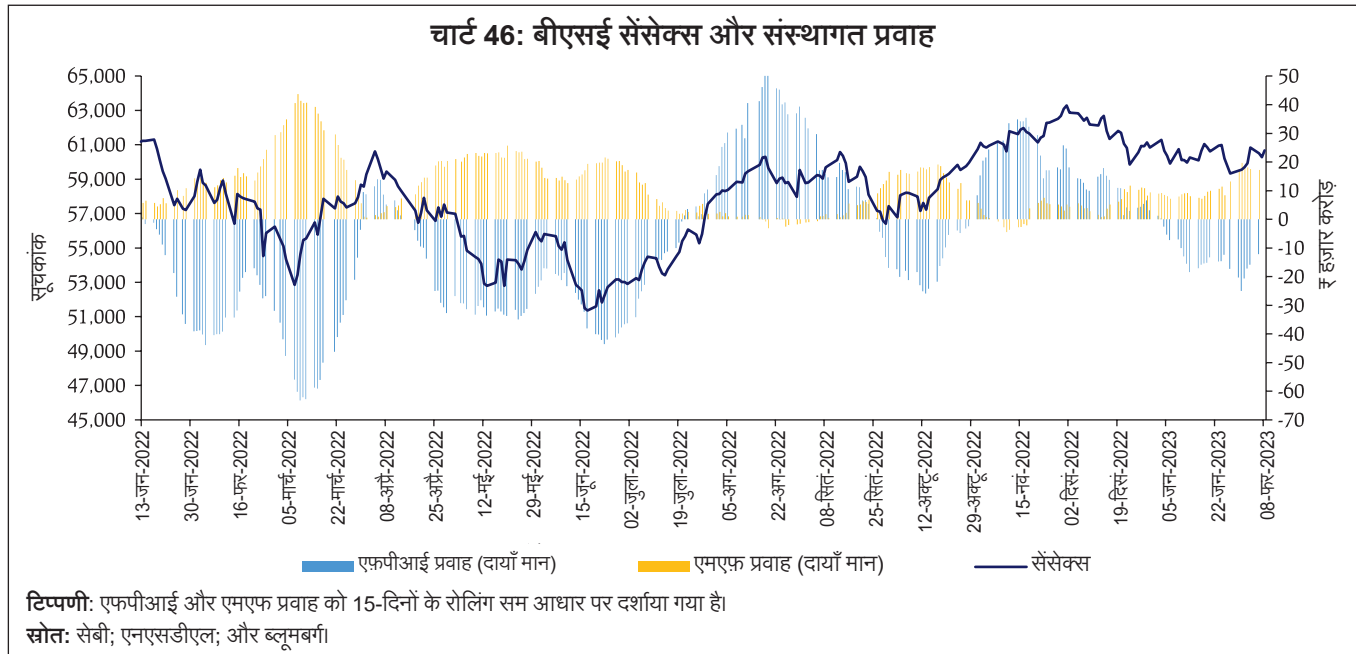
जनवरी 2023 की पहली छमाही में सीमित रहने के बाद, कच्चे तेल पर अप्रत्याशित कर में कमी के बाद, घरेलू इक्विटी बाजार शुरु में दूसरी छमाही में ऊपर चले गए। एक व्यापारिक समूह के शेयरों में असामान्य मूल्य उतार-चढ़ाव के बाद महीने के अंत में भावनाएं नकारात्मक हो गईं। कुल मिलाकर, एफपीआई के शुद्ध विक्रेता बनने के साथ, बीएसई सेंसेक्स में जनवरी 2023 के दौरान 2.1 प्रतिशत की गिरावट आई (चार्ट 46)। फिर भी, केंद्रीय

बजट 2023-24 में पूंजीगत व्यय में वृद्धि और चुनिंदा प्रत्यक्ष कर राहत¹⁸ से संबंधित घोषणाएं, वित्तीय क्षेत्र के नियामकों द्वारा घरेलू वित्तीय और व्यापक आर्थिक स्थितियों की सुदृढ़ता की पुनः पुष्टि करने वाले बयानों ने बाजार की भावनाओं को बढ़ावा देने में मदद की। बीएसई सेंसेक्स फरवरी 2023 (15 फरवरी, 2023 तक) के दौरान 2.9 प्रतिशत ऊपर उठा।

चार्ट 45: अल्प बचत योजनाओं पर ब्याज दरें



¹⁸ वित्त मंत्री ने नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कई बदलावों का प्रस्ताव किया, जैसे एमएसएमई, सहकारी समितियों और स्टार्ट-अप के लिए कर लाभ के साथ आयकर में छूट के लिए आय सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये करना, कर स्लैब को युक्तिसंगत बनाना, वेतनभोगी वर्ग के लिए मानक कटौती का प्रावधान, उच्चतम अधिभार दर को 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करना, आदि। इन उपायों से प्रत्यक्ष कर राजस्व में 37,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ने की उम्मीद है।



भारतीय इक्विटी बाजार ने 27 जनवरी, 2023 को तेजी से निपटान व्यवस्था में अपना संक्रमण पूरा किया, जिसमें इक्विटी खंड की सभी प्रतिभूतियां टी + 1 निपटान में चली गईं। यह सितंबर 2021 में शुरू हुई एक प्रक्रिया की परिणति का प्रतीक है, जिससे भारत सबसे छोटे निपटान चक्रों के साथ वैश्विक नेताओं में से एक बन गया है जो निपटान, प्रतिपक्ष और संचालन से जुड़े जोखिमों को कम करने में मदद करेगा और व्यापार मात्रापर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा।

2022-23 की तीसरी तिमाही के लिए 1,109 गैर-वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों¹⁹ द्वारा घोषित कॉर्पोरेट आय परिणामों से पता चला है कि कंपनियों की राजस्व वृद्धि में कमी देखी गई (चार्ट 47 ए)। व्यय में वृद्धि के बावजूद, अन्य आय द्वारा समर्थित वर्ष-दर-वर्ष आधार पर परिचालन लाभ में मामूली सुधार हुआ। इनपुट लागत दबाव कम होने से परिचालन लाभ मार्जिन में क्रमिक आधार पर सुधार देखा गया। अन्य आय, जिसमें कॉर्पोरेट्स की खजाना प्रबंधन गतिविधियों से आय शामिल है, ने वृद्धि दर्शायी। कुल

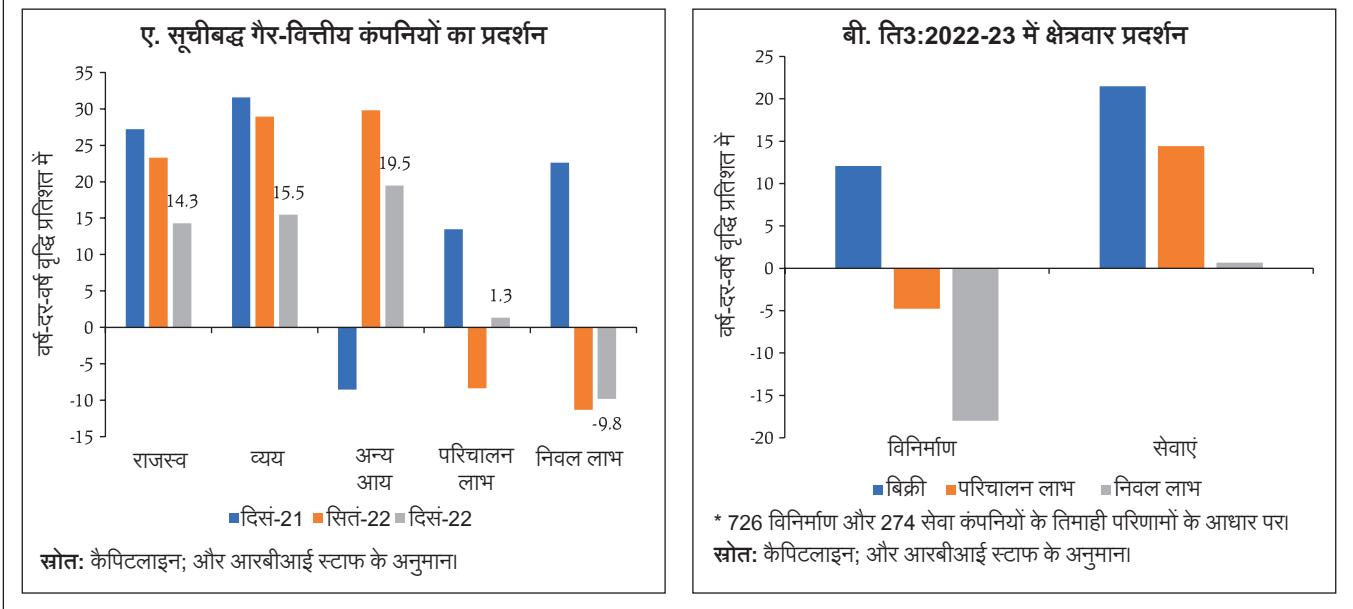
मिलाकर गैर-वित्तीय कंपनियों की निवल लाभ वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) लगातार दूसरी तिमाही में नकारात्मक रही। सेवा क्षेत्र ने बिक्री और परिचालन लाभ में तोस वृद्धि दर्ज की। उच्च ब्याज लागत और मुख्य रूप से लोहा और इस्पात उद्योग में अन्य खर्च से विनिर्माण कंपनियों के शुद्ध मुनाफे में 18.0 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की गिरावट आई [चार्ट 47 बी]।

बैंकों और अन्य वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों²⁰ की आय तोस बनी हुई है और ऋण वृद्धि द्वारा समर्थित राजस्व (वर्ष-दर-वर्ष) में तोस दो अंकों की वृद्धि हुई है (चार्ट 48)। अन्य आय, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सुरक्षा लेनदेन, शुल्क और कमीशन से लाभ/हानि शामिल है, में भी तीव्र वृद्धि दर्ज की गई। टॉप-लाइन की तुलना में व्यय धीमी गति से बढ़ने के साथ, परिचालन मुनाफे में वृद्धि हुई। प्रावधान लागत सालाना आधार पर समतल पर रही और बदले में बैंकों और वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों के कुल निवल मुनाफे में तोस वृद्धि दर्ज की गई।

¹⁹ प्रारंभिक परिणाम 2021-22 की तीसरी तिमाही के दौरान निजी कॉर्पोरेट व्यवसाय क्षेत्र के प्रदर्शन पर आरबीआई के अध्ययन में शामिल कुल बिक्री आकार का 74.3 प्रतिशत कवर करते हैं।

²⁰ 862 बैंकों और अन्य वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों के परिणामों के आधार पर, जो बाजार पूंजीकरण का लगभग 89 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते हैं।

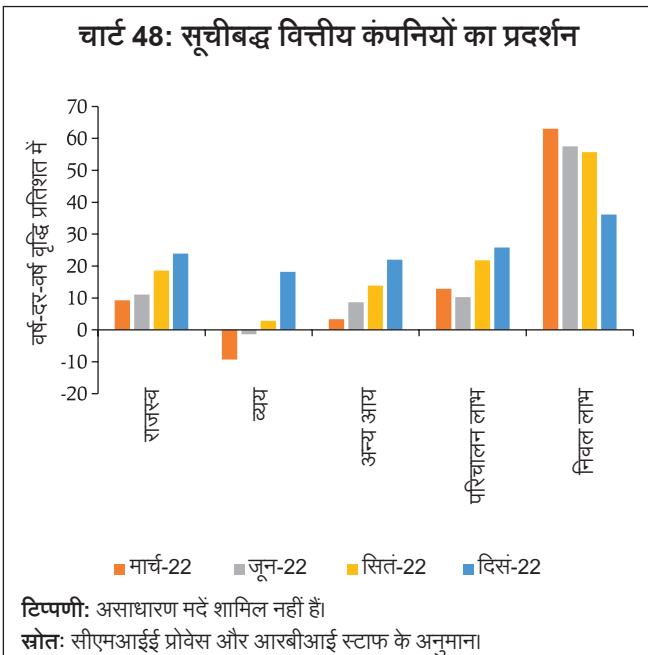
चार्ट 47: कॉरपोरेट प्रदर्शन



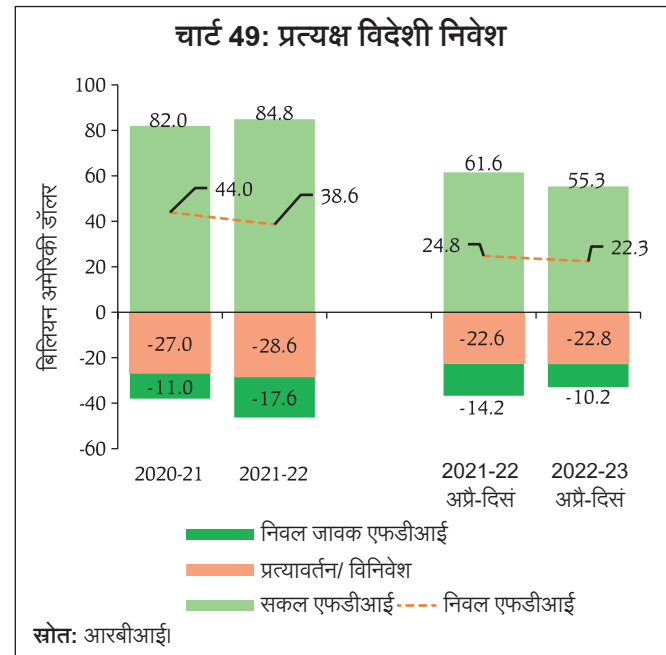
अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान सकल आवक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) एक साल पहले के 61.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 55.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया (चार्ट 49)। इस अवधि के दौरान निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एक वर्ष पूर्व के 248 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 223 बिलियन अमरीकी डालर रहा, जो मुख्य रूप से इक्विटी अंतर्वाह में गिरावट

को दर्शाता है। अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान विनिर्माण, वित्तीय सेवाओं, कंप्यूटर सेवाओं, खुदरा और थोक व्यापार और संचार सेवाओं द्वारा एफडीआई इक्विटी प्रवाह का बड़ा हिस्सा प्राप्त किया गया था। अमेरिका, सिंगापुर और मॉरीशस इस अवधि के दौरान एफडीआई के प्रमुख स्रोत देश थे।

चार्ट 48: सूचीबद्ध वित्तीय कंपनियों का प्रदर्शन



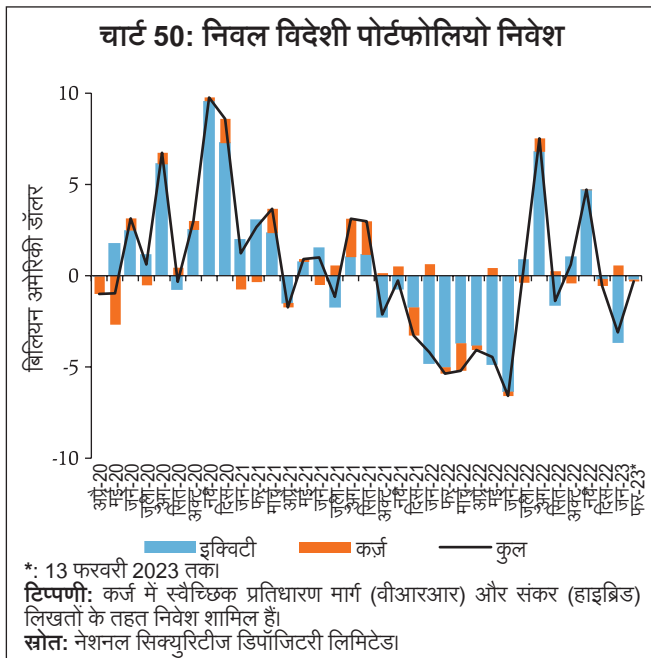
चार्ट 49: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश



2023-24 में एफडीआई दृष्टिकोण के लिए केंद्रीय बजट का 'बुनियादी ढांचा और निवेश' और 'हरित विकास' का विषय अच्छा संकेत है। भारत 'एफडीआई स्टैंडआउट वॉचलिस्ट' में दूसरे स्थान पर है जो दुनिया के शीर्ष 50 एफडीआई गंतव्यों के एफडीआई प्रक्षेपवक्र का आकलन करता है²¹

एफपीआई जनवरी 2023 में घरेलू पूंजी बाजारों में निवल विक्रेता बन गए (चार्ट 50)। इक्विटी खंड की अगुवाई में जनवरी 2023 में भारत से निवल एफपीआई बहिर्वाह 3.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। हालांकि, जनवरी 2023 के दौरान ऋण खंड में 0.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश देखा गया। वित्तीय सेवाओं, ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों, और धातु और खनन क्षेत्रों ने इक्विटी बाजार में पोर्टफोलियो निवेश का बड़ा हिस्सा आकर्षित किया। दूसरी ओर सूचना प्रौद्योगिकी, उपभोग्य ईंधन और पूंजीगत सामान शेरों में विनिवेश की सूचना मिली।

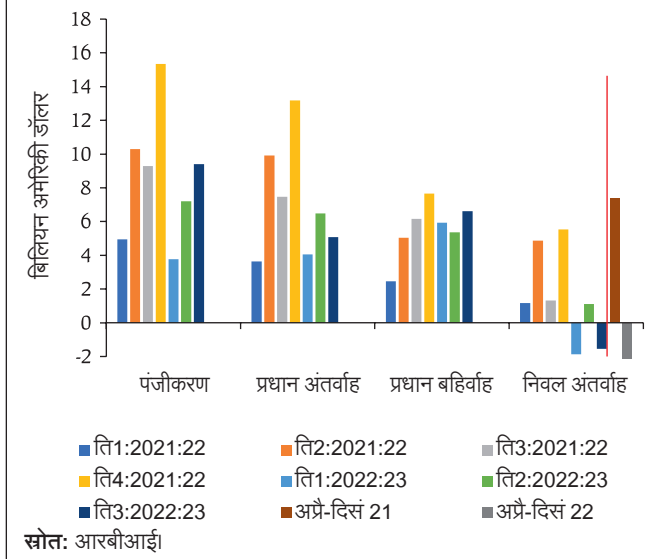
अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) पंजीकरण राशि²² 20.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी,



²¹ एफडीआई आउटलुक 2023, एफडीआई इंटेलिजेंस।

²² पंजीकरण राशि ईसीबी मार्ग के माध्यम से स्वीकृत उधार राशि को ले लेती है।

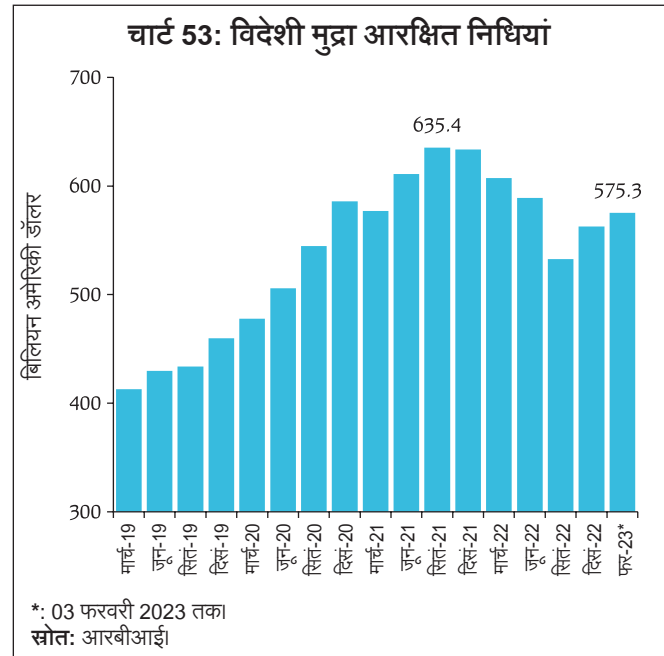
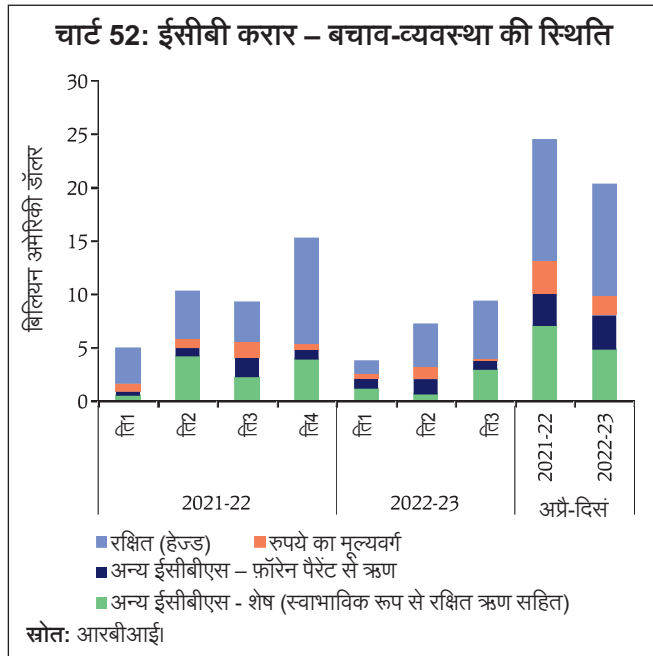
चार्ट 51: ईसीबी - पंजीकरण, अंतर्वाह और बहिर्वाह



जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 24.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। वर्ष के दौरान के संचालनों से पता चलता है कि 2022-23 की पहली तिमाही में गिरावट के बाद, पंजीकरण राशि में तेजी आई, जो आंशिक रूप से 6 जुलाई, 2022 को रिजर्व बैंक द्वारा घोषित उदारीकरण उपायों द्वारा समर्थित थी। हालांकि अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान भारत को ईसीबी का सकल संवितरण 15.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, लेकिन उच्च पुनर्भुगतान के कारण निवल ईसीबी ऋणात्मक हो गया, और हाल ही में, ईसीबी पंजीकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बाद में तैयार किया जाना निर्धारित किया गया (चार्ट 51)।

अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान ईसीबी समझौते की राशि के तीन-चौथाई से अधिक प्रभावी रूप से हेजिंग रहे और शेष में स्वाभाविक हेज के साथ ऋण शामिल थे (यानी, उधारकर्ताओं की आय विदेशी मुद्रा में है) [चार्ट 52]।

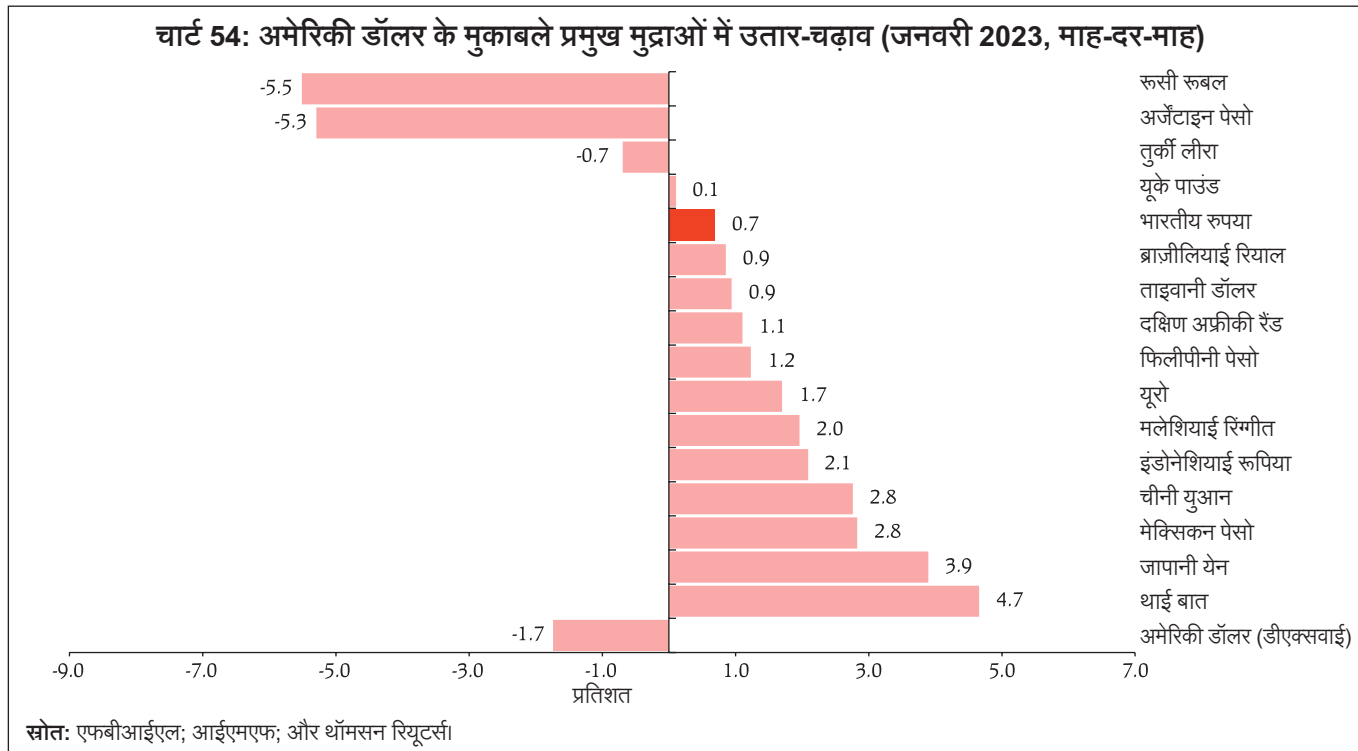
सितंबर 2022 के अंत से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 42.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ गया और 3 फरवरी, 2023 को 575.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें 2022-23 के लिए अनुमानित नौ महीने से अधिक आयात शामिल है (चार्ट 53)।



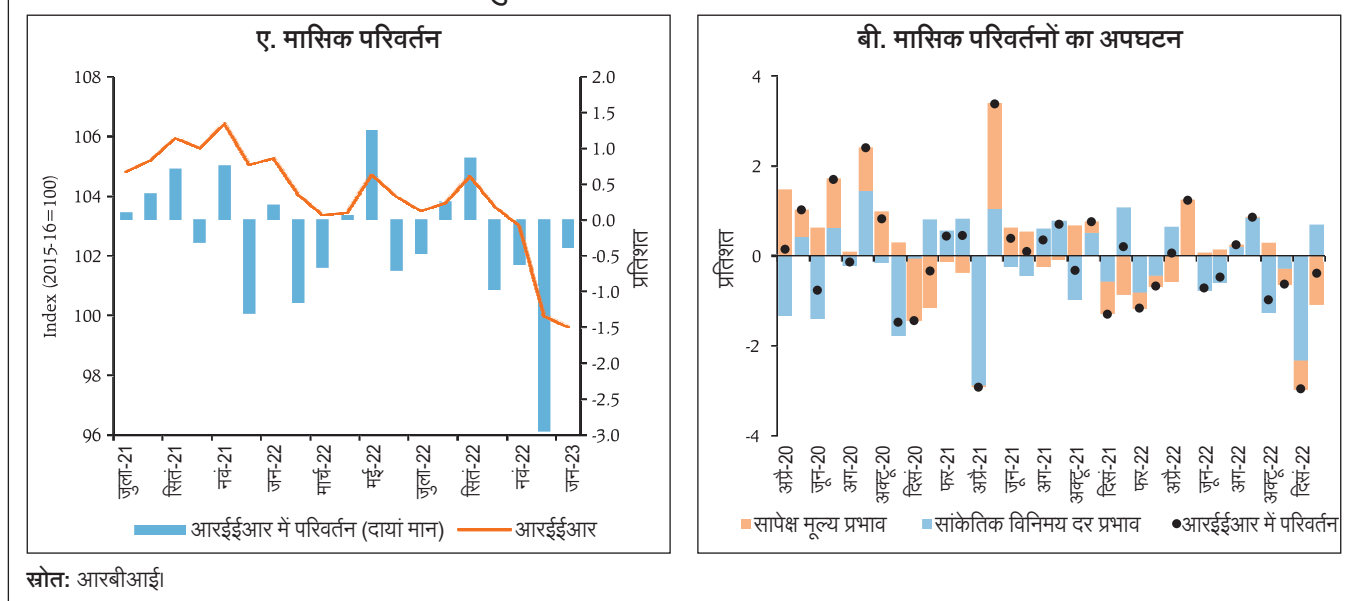
विदेशी मुद्रा बाजार में, भारतीय रुपया (आईएनआर) जनवरी 2023 में अमेरिकी डॉलर (एम-ओ-एम) की तुलना में 0.7 प्रतिशत बढ़ गया, क्योंकि अमेरिकी फेड ने कम आक्रामक रुख अपनाया और अमेरिकी डॉलर में 1.7 प्रतिशत की गिरावट आई (चार्ट 54)।

रुपये का प्रदर्शन कई अन्य ईएमई और आरक्षित मुद्राओं के अनुरूप था।

40-मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) के संदर्भ में, जनवरी 2023 में आईएनआर में 0.4 प्रतिशत की गिरावट आई (एम-ओ-एम) (चार्ट 55)।



चार्ट 55: 40-मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में उतार-चढ़ाव



भुगतान प्रणाली

डिजिटल लेनदेन विभिन्न तरीकों से उन्नत हुआ और एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) के नेतृत्व में खुदरा क्षेत्र में मजबूत पकड़ बनी रही [सारणी 6]। आपूर्ति पक्ष में, भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) योजना के तहत परिनियोजित भुगतान स्वीकृति उपकरणों की संख्या अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान 59 प्रतिशत बढ़ी।

8 फरवरी, 2023 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में बीमा कंपनियों और फैक्ट्रिंग व्यवसाय करने वाली

एजेंसियों की भागीदारी की अनुमति देकर और टीआरईडीएस प्लेटफॉर्मों पर द्वितीयक बाजार संचालन को सक्षम करके व्यापार प्राप्ति छूट प्रणाली (टीआरईडीएस) से संबंधित गतिविधि के दायरे का विस्तार करने के उपायों का प्रस्ताव किया गया है। इसमें भारत आने वाले सभी यात्रियों के लिए यूपीआई (मर्चेट भुगतान के लिए) के विस्तार का भी प्रस्ताव किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने 10 देशों के अनिवासी भारतीयों को यूपीआई प्लेटफॉर्म पर शामिल करने में समर्थ बनाया है।²³ डिजिटल प्रणाली के बढ़ते अंगीकरण के प्रमाण के रूप में, हाल ही में, जारी रिज़र्व बैंक के डिजिटल भुगतान सूचकांक

सारणी 6: चुनिंदा भुगतान प्रणालियों में वृद्धि दरें

(वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत में)

भुगतान प्रणाली संकेतक	लेन-देन की मात्रा				लेन-देन के मूल्य			
	दिसं-21	दिसं-22	जन-22	जन-23	दिसं-21	दिसं-22	जन-22	जन-23
आरटीजीएस	17.9	11.5	15.7	12.6	21.7	5.9	13.9	20.1
एनईएफटी	22.3	29.0	26.2	32.2	6.5	9.4	12.8	15.0
यूपीआई	104.4	71.4	100.5	74.1	98.7	55.0	93.0	56.1
आईएमपीएस	24.5	9.7	27.0	7.8	35.6	22.7	34.1	23.4
एनएसीएच	-2.7	10.5	28.8	-10.4	5.1	34.5	26.4	14.4
एनईटीसी	74.9	27.2	54.8	30.2	59.7	34.3	50.0	33.6
बीबीपीएस	137.0	60.4	130.2	59.8	165.2	63.6	148.8	66.6

स्रोत: आरबीआई।

²³ एनपीसीआई परिपत्र, जनवरी 2023।

(आरबीआई-डीपीआई) ने सितंबर 2022 में 24.1 प्रतिशत की वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) दिखाई। 2023 में, भारत में डिजिटल भुगतान की उपयोगकर्ता प्रवेश दर दुनिया की तुलना में अधिक होने की उम्मीद है²⁴

केंद्रीय बजट 2023-24 में मजबूत डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए विभिन्न उपायों की भी घोषणा की गई है। इनमें डिजिटल भुगतान मोड को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 1500 करोड़ रुपये का राजकोषीय समर्थन जारी रखना, एक कृषि त्वरक निधि की स्थापना करना, राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस नीति के माध्यम से अनाम डेटा तक सुरक्षित पहुंच को सक्षम करना, डिजीलॉकर²⁵ के माध्यम से उपलब्ध दस्तावेजों के दायरे का विस्तार करना, व्यवसायों द्वारा जानकारी संग्रहीत करने और साझा करने के लिए एक 'एटिटी डिजीलॉकर' बनाना, डिजिटल क्षमताओं को विकसित करने के लिए एमएसएमई को प्रशिक्षित करना शामिल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना, 5 जी सेवाओं का उपयोग करके एप्लिकेशन विकसित करने के लिए 100 प्रयोगशालाओं की स्थापना और अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) प्रक्रिया को सरल बनाना।

निष्कर्ष

हमारा मानना है कि भारत मौजूदा पुराने और शेष विश्व के वृहद आर्थिक अनुमानों से अलग हो जाएगा। हमारे विचार में, (क) 2023-27 की अवधि में भारत की विकास संभावनाओं और (ख) भारत के संभावित विकास को बढ़ाते हुए अलगीकरण का साधन केंद्रीय बजट होगा।

तात्कालिक विकास संभावनाओं को देखें, तो केंद्रीय बजट को कई मामलों में सभी पक्षों से सराहना मिली है। समेकन और पूंजीगत व्यय पर किए गए वादों के अलावा, बजट में प्रस्तावित कर परिवर्तनों से परिवारों के हाथों में कम से कम 35,000 करोड़ रुपये आएंगे। विकास के दृष्टिकोण पर इन तीन पहलुओं के निहितार्थ गहरे हैं। सबसे पहले, करों पर बचत से उपभोग पर परिवारों द्वारा खर्च को बढ़ावा मिलेगा। भारत की उपभोग की

सीमांत प्रवृत्ति (एमपीसी) 0.54 होने का अनुमान है, कर गुणक 1.16 है। इसलिए, भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि को 2023-24 में अकेले कर कटौती से 15 आधार अंकों की वृद्धि मिलेगी।

दूसरा, 2023-24 में पूंजीगत व्यय के लिए आवंटन में वृद्धि (राज्यों को ऋण सहायता, रेलवे, रसद और पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान सहित, जिन्हें प्रभावी राजस्व घाटे के तहत बाहर रखा गया है और इसलिए पूंजी खाते में जोड़ा गया है) 3.2 लाख करोड़ रुपये है²⁶ यह बढ़ा हुआ पूंजीगत व्यय 2023-27 के दौरान 10.3 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त उत्पादन उत्पन्न करेगा - कर गुणक के विपरीत जिसका अल्पकालिक प्रभाव पड़ता है, गतिशील पूंजीगत व्यय गुणक पहले वर्ष में 1 से बढ़कर दूसरे वर्ष में 2.45, तीसरे वर्ष में 3.14 और 2026-27 में 3.25 चरम पर पहुंच जाता है। रेलवे पर पूंजीगत व्यय और राज्यों को ऋण सहायता इस बढ़ी हुई आय का 43 प्रतिशत योगदान देगी, जबकि रसद में निवेश (60,000 करोड़ रुपये) से 2023-27 में 1.95 लाख करोड़ रुपये या बढ़ी हुई आय का 19 प्रतिशत उत्पन्न होने की उम्मीद है।

तीसरा, राजकोषीय समेकन निजी क्षेत्र के लिए उत्पादक संसाधनों को मुक्त कर सकता है और पूंजी की लागत को कम करने में भी योगदान दे सकता है। केंद्रीय बजट में कुल व्यय में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 0.41 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया गया है²⁷ इससे निजी निवेश के लिए संसाधन मुक्त होंगे। व्यय गुणक के संयोजन के साथ, यह 2023-24 में अर्थव्यवस्था की विकास दर को 10 आधार अंकों तक बढ़ा सकता है²⁸

इन सभी को एक साथ रखने और आर्थिक सर्वेक्षण के 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर के अनुमान को आधार के रूप में लेते हुए, केंद्रीय बजट के कर, पूंजीगत व्यय और राजकोषीय समेकन प्रस्तावों को प्रभावी ढंग से लागू करने पर, वे 2023-24 में भारत

²⁶ केंद्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय 2022-23 (संशोधित अनुमान) के 10.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 (बीई) में 13.7 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा।

²⁷ 2023-24 (बजट अनुमान) में कुल व्यय पिछले वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद के 15.33 प्रतिशत से घटकर सकल घरेलू उत्पाद का 14.92 प्रतिशत होने का अनुमान है, जिसके परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद के 0.41 प्रतिशत की गिरावट आई है।

²⁸ कारोबार चक्र के विस्तारवादी चरण में व्यय गुणक का अनुमान चार तिमाहियों में (-) 0.22 है, जबकि मंदी की अवधि में सकारात्मक व्यय गुणक होता है जब निजी क्षेत्र की ऋण की मांग आम तौर पर कमजोर हो जाती है (मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट, 2022)।

²⁴ स्रोत: स्टेटिस्टा डेटाबेस 03 फरवरी, 2023 तक एक्सेस किया गया।

²⁵ डिजीलॉकर नागरिकों के दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों के भंडारण, साझाकरण और सत्यापन के लिए एक सुरक्षित क्लाउड-आधारित प्लेटफॉर्म है।

की वास्तविक जीडीपी वृद्धि को 7.0 प्रतिशत के करीब ले जा सकते हैं।

भारत की क्षमता को देखें, तो केंद्रीय बजट (क) पूंजीगत व्यय पर जोर देकर; (ख) डिजिटलीकरण और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने जैसी नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके; और (ग) जनसांख्यिकीय लाभांश जो एक साथ मिलकर भारतीय अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावना सीमा का विस्तार कर सकता है, को जब्त करके अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता का विस्तार करेगा। सबसे पहले, पूंजीगत व्यय पर निरंतर जोर देने के अलावा, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्कृष्टता केंद्र, राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस नीति और केवाईसी मानदंडों के सरलीकरण से उत्पादकता को सकारात्मक झटका लग सकता है और कुल कारक उत्पादकता (टीएफपी) में वृद्धि हो सकती है जो प्रति वर्ष 10 आधार अंकों की संभावित वृद्धि को बढ़ा सकती है।

दूसरा, केंद्रीय बजट भाषण में हरित विकास प्राथमिकता के तहत 12 योजनाओं का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें चार योजनाओं के तहत पहले से ही उल्लिखित 85 हजार करोड़ रुपये का ठोस परिव्यय है।²⁹ इससे 2030 तक 1.7 लाख करोड़ रुपये के निजी निवेश (2 का क्राउड-इन फैक्टर लेते हुए)³⁰ में भारी बढ़ोतरी होगी, जिससे कुल हरित निवेश को 2.6 लाख करोड़ रुपये तक ले जाया सकता है और जीडीपी में 3.3 लाख करोड़ रुपये या संभावित उत्पादन के लगभग 100 आधार अंकों की वृद्धि हो सकती है। भौतिक और डिजिटल पुस्तकालयों की स्थापना के साथ-साथ युवाओं और शिक्षकों को कुशल बनाकर जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने से संभावित जीडीपी वृद्धि 5 आधार अंकों से बढ़कर 15 आधार अंक प्रति वर्ष हो सकती है।³¹

राजकोषीय समेकन से उत्पन्न व्यापक आर्थिक स्थिरता का माहौल और इसलिए ऋण में कमी से मध्यम अवधि में मुद्रास्फीति

में कमी आने की उम्मीद है, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक आर्थिक अस्थिरता और देश के जोखिम प्रीमियम में कमी आएगी, जिससे एक अच्छे चक्र की शुरुआत होगी। अनुमानों से पता चलता है कि एकल आधार पर, यानी मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों को ध्यान में रखे बिना, इससे अगले पांच वर्षों में मुद्रास्फीति में प्रति वर्ष औसतन 26 आधार अंकों की कमी हो सकती है³², जो बदले में, संभावित विकास को और 10 आधार अंक तक बढ़ा देगी।³³

इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, संभावित वृद्धि 6.0 प्रतिशत (2022-23 में आईएमएफ द्वारा अनुमानित³⁴) से बढ़कर 6.8 प्रतिशत होने की उम्मीद है।³⁵ बजट में घोषित उपायों के कारण भारत की संभावित वृद्धि में बढ़ोतरी के साथ, 2027-28 तक सकल घरेलू उत्पाद के 54.3 प्रतिशत तक केंद्र सरकार के ऋण का तेजी से समेकन होने की संभावना है।

सभी संस्कृतियों की पौराणिक कथाओं में, सूर्य को आमतौर पर चार घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ की सवारी के रूप में चित्रित किया गया है। उदाहरण के लिए, ग्रीस में अपोलो के लिए ऐसा है; मिस्र में रा; रोम में सोला भारतीय पौराणिक कथाओं में, हालांकि, सूर्य का रथ सात घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। घोड़ों के अर्थ बारे में कई व्याख्याएं उपलब्ध हैं – विभिन्न शास्त्र उन्हें इंद्रधनुष के सात रंग प्रदान करते हैं; सात वैदिक मान या छंद; और इसी तरह अन्य। सातवां घोड़ा सपनों, आकांक्षाओं और भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है। कहा जाता है कि अगर अन्य छह घोड़े घायल या थक भी जाते हैं, तो भी सातवां घोड़ा सूर्य के रथ को उसके गंतव्य तक ले जा सकता है। यह डॉ. धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध पुस्तक का विषय है और श्याम बेनेगल की इसी नाम की फिल्म का विषय भी है, जिसका नाम सूरज का सातवां घोड़ा है। हमारे विचार में, केंद्रीय बजट 2023-24 सूर्य का सातवां घोड़ा है।

²⁹ बजट में हरित हाइड्रोजन मिशन, ऊर्जा संक्रमण, ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं, नवीकरणीय ऊर्जा निकासी, हरित ऋण कार्यक्रम, पीएम-प्रणाम, गोबरधन योजना, भारतीय प्रकृतिक खेती जैव-इनपुट संसाधन केंद्र, तटरेखा पर्यावासों और मूल आय के लिए मैंग्रोव पहल (मिष्ठी), अमृत धरोहर, तटीय शिपिंग और वाहन प्रतिस्थापन सहित 12 प्रस्तावों को रेखांकित किया गया है।

³⁰ आईईए (2012), आईएमएफ (2021), अंतर-अमेरिकी विकास बैंक (2006), यूरोपीय आयोग (2013) देखें।

³¹ कुछ संदर्भों में तिलक (1989) शामिल हैं; तबर एट अल, (2016); जेमेल एट अल, (2016); और डी रिडर एट अल, (2020)।

³² वान बॉन, एन (2015) पर आधारित आंतरिक अनुमान।

³³ मोहदेस और रायसी (2014) पर आधारित 33 आंतरिक अनुमान।

³⁴ अनुच्छेद IV परामर्श, दिसंबर 2022।

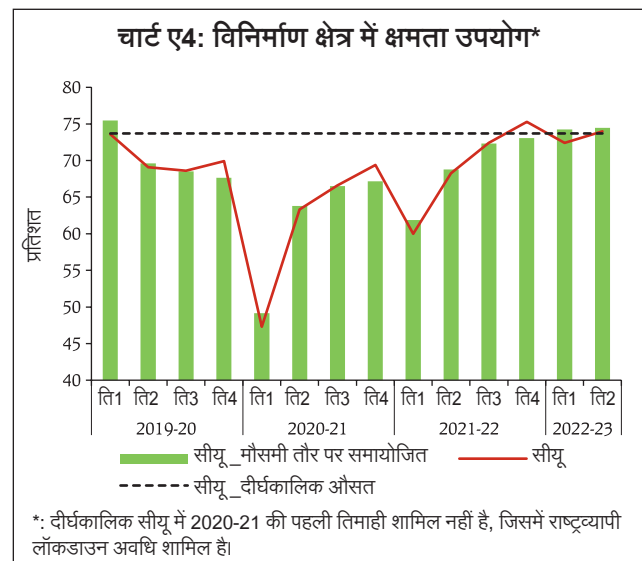
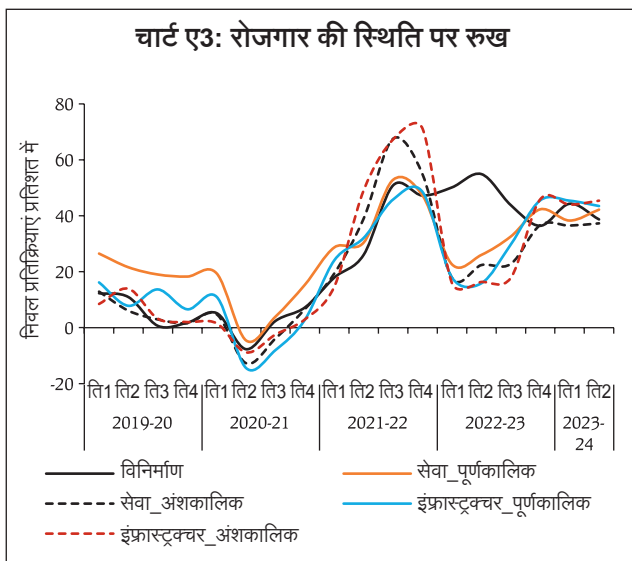
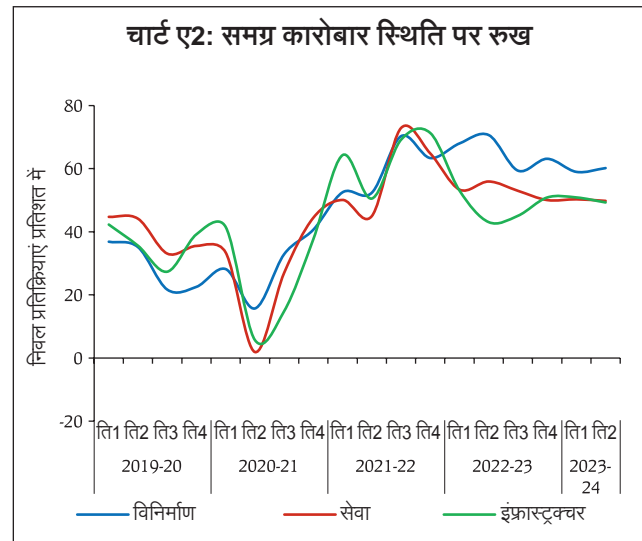
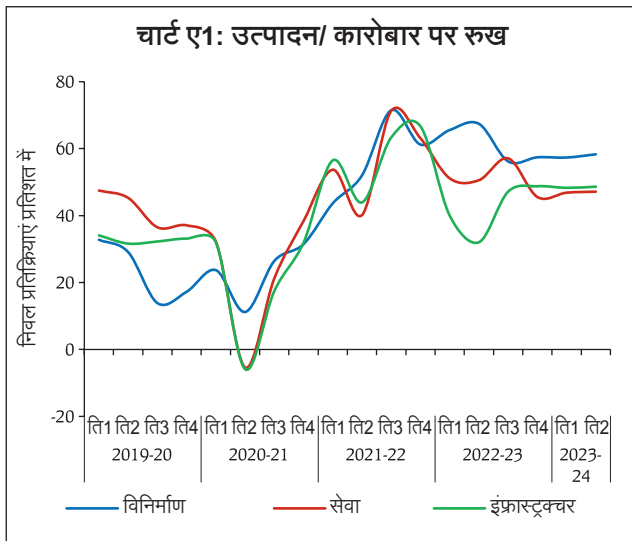
³⁵ उच्च संभाव्यता विकास मूल्यांकन बजट में अलग-अलग विकास सहायक उपायों के प्रभाव के आकलन पर आधारित होता है, जो बाद में एकत्रित होते हैं, न कि इन सभी प्रमुख उपायों के बीच क्रॉस इफेक्ट्स को पकड़ने के लिए एक गतिशील मॉडल ढांचे में संभावित वृद्धि में आकलित वृद्धि भी अगले कुछ वर्षों में होने की संभावना है, न कि 2023-24 में क्योंकि कुछ उपायों का पूर्ण प्रभाव, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, 2026-27 तक और यहां तक कि 2030 तक भी होगा।

अनुबंध 1: आरबीआई के उद्यम सर्वेक्षण से प्रमुख निष्कर्ष

2022-23 की तीसरी तिमाही के दौरान किए गए रिजर्व बैंक के उद्यम सर्वेक्षणों³⁶ के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

- कंपनियां समग्र कारोबारी स्थितियों को लेकर उत्साहित हैं, जिनके 2023-24 की पहली छमाही (चार्ट ए1 और ए2) तक विस्तार जारी रहने की उम्मीद है।
- पूर्णकालिक और अंशकालिक कर्मचारियों (चार्ट ए3) दोनों के लिए नौकरी के अवसरों का विस्तार होने की संभावना है।

- व्यवसाय उत्पादन, ऑर्डर बुक, रोजगार की स्थिति, क्षमता उपयोग और समग्र व्यावसायिक स्थिति पर आशावादी रहते हैं।
- क्षमता उपयोग (सीयू) और मौसमी रूप से समायोजित सीयू 2022-23 की दूसरी तिमाही में दीर्घकालिक औसत सीयू को पार कर लिया; सुधार जारी रहने की संभावना है (चार्ट ए 4 और ए 5)।



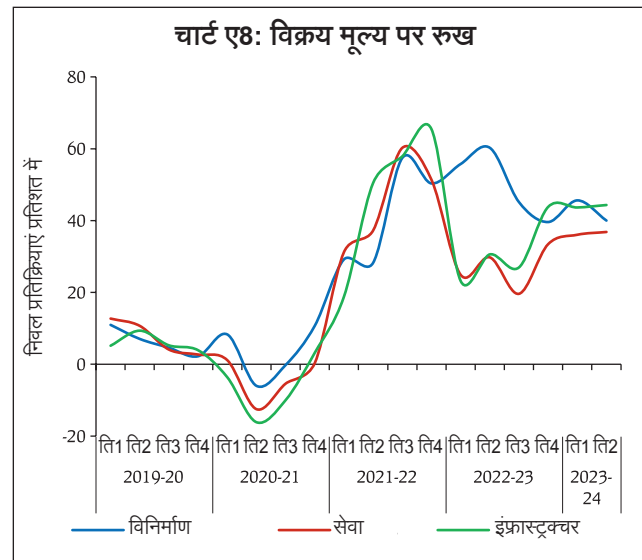
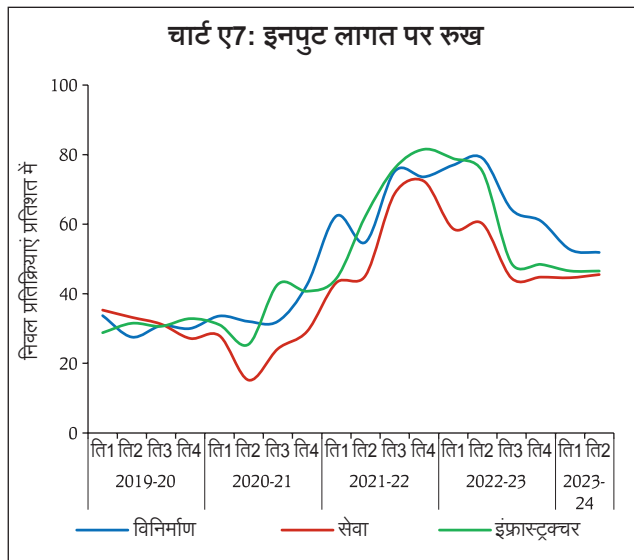
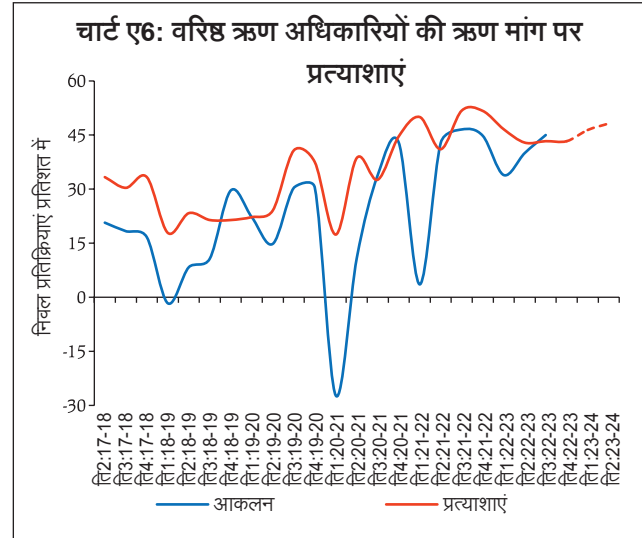
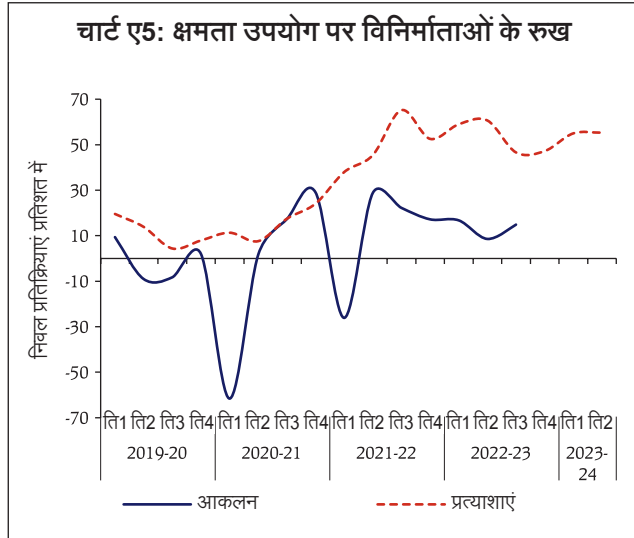
स्रोत: आरबीआई

³⁶ https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=55184

अनुबंध 1: आरबीआई के उद्यम सर्वेक्षण से प्रमुख निष्कर्ष (जारी)

- वरिष्ठ ऋण अधिकारियों को उम्मीद है कि 2023-24 की पहली छमाही के दौरान बैंकों से ऋण मांग में हालिया वृद्धि बनी रहेगी (चार्ट ए 6)।

- उच्च इनपुट लागत दबाव और मूल्य निर्धारण शक्ति की वापसी के कारण, अधिक कंपनियों को बिक्री मूल्यों (चार्ट ए 7 और ए 8) में वृद्धि की उम्मीद है।



टिप्पणी: "निवल प्रतिक्रिया" सकारात्मक रिपोर्ट करने वाले उत्तरदाताओं और नकारात्मक की रिपोर्ट करने वाले उत्तरदाताओं के प्रतिशत के बीच का अंतर है। यह -100 और 100 के बीच है; शून्य से अधिक कोई भी मान, विस्तार/ सकारात्मक को इंगित करता है और शून्य से कम मान संकुचन/ नकारात्मक को इंगित करता है।

स्रोत: आरबीआई